

राज्यसभा में नेता सदन होंगे पीयूष गोयल >>3

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 35

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 15 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

बिटिया को कहानी ऐसी भायी, शब्दों की जादूगर बनी माई



शाहजहांपुर : आशा शुक्ला आठवीं कक्षा में थीं कि शादी हो गई। 31 साल बाद बेटी ने अहसास कराया तो कलम पकड़ी और तीन साल में ही एक बड़ा रचना संसार रच दिया। 48.61 लाख लोग उनकी रचनाओं को आनलाइन पढ़ चुके हैं। (पेज-10)

क्या कोरोना पर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे सकती हैं अदालतें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस पर विचार करेगा कि क्या कोरोना जैसी आपात स्वास्थ्य स्थिति में अदालतें कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकती हैं? अगर हां तो किस हद तक ? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रबंधन मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हर जिले में निश्चित संख्या में एंबुलेंस, आइसीयू बेड, टीकाकरण आदि के बारे में दिए गए आदेश और प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था को 'भगवान भरोसे' बताने की टिप्पणी से असहमति जताते हुए कहा कि यह देखना होगा कि ऐसे मामलों में अदालतें किस हद तक दखल दे सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी के पास सौ सुझाव हो सकते हैं? तो क्या वे कोर्ट का आदेश बन सकते हैं? हमें याद रखना होगा कि हम संवैधानिक अदालत हैं।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और दिनेश महेश्वरी की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा, कितनी एंबुलेंस होंगी, कितने आक्सीजन बेड हैं, इस सब पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम यह नहीं कह रहे कि कोई अपना सुझाव नहीं दे सकता लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि स्थानीय कंपनी टीके का फार्मूला लेकर उत्पादन करें। ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता। पीठ ने माना की हाई कोर्ट का आदेश अव्यवहारिक है और उस पर पालन संभव नहीं है। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

अगर हां, तो किस हद तक, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

शीर्ष अदालत ने कहा, उद्देश्य कितना भी अच्छा हो संविधान में वर्णित शक्तियों का सम्मान होना चाहिए



बुधवार को पीठ ने कहा, अगर हाई कोर्ट का आदेश व्यवहारिक भी होता तो भी सवाल उठता है कि क्या जो क्षेत्र कार्यपालिका के लिए चिन्हित हैं उसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए। पीठ ने कहा, इस मुश्किल समय में सभी को सावधानी से चलना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या किया जाए और कौन करे। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा कि आपात स्थिति में मिल कर प्रयास करने की जरूरत होती है, लेकिन अच्छा इरादा किसी को दूसरे के क्षेत्राधिकार में घुसने की इजाजत नहीं देता। वैसे इस बारे में कोई समान फार्मूला नहीं हो सकता लेकिन कुछ तय मानक होते है जिनके अंदर ही हर संस्था को काम करना चाहिए।

जस्टिस महेश्वरी ने न्यायमित्र वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता से कहा कि वह कोर्ट को इस सुनवाई में मदद करते हुए बताएंगे कि जब हर संस्था की सीमा और मानक तय हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। गुप्ता ने कहा, संवैधानिक अदालतों को बहुत से अधिकार हैं और वे जनहित में आदेश दे सकती हैं। गुप्ता ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजा हलफनामे में कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा दिया है। पीठ ने कहा, लेकिन राम भरोसे की टिप्पणी को कैसे सही ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने मामले को 12 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए उप्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, वह इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सभी आदेशों को कोर्ट में पेश करें। पीठ ने कहा, वह फिलहाल हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं। ज्ञात हो, हाईकोर्ट ने गत 17 मई को कोरोना प्रबंधन मामले में सुनवाई करते हुए बहुत से आदेश दिये थे जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की है।

महंगाई भत्ते में 11 फीसद की बढ़ोतरी

तोहफा ▸ एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा लाभ

एक जुलाई, 2021 से होगा लागू, नहीं मिलेगा एरियर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली



नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार ने बुधवार को बड़ी राहत प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 11 फीसद की वृद्धि का फैसला किया गया। अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 28 फीसद की दर से डीए और डीआर का भुगतान होगा। यह फैसला इस साल एक जुलाई से मान्य होगा। इससे 48.34 लाख केंद्रीय कर्मियों व 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। डीए का कोई एरियर नहीं मिलेगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीए और डीआर में होने वाली इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल एक जनवरी से डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी। अमूमन हर छह महीने पर सरकार डीए और डीआर में महंगाई दर में होने वाली बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ोतरी करती है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर की तीन किस्तें बकाया थीं। सरकार ने एक साथ 11 फीसद की बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन उसका पिछले डेढ़ साल के डीए से कोई लेना-देना नहीं होगा। पिछले साल कोरोना की वजह से सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव को देखते हुए डीए फ्रीज करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा सभी महकमों के खर्च में भी कटौती की गई थी जो कमोबेश अब भी जारी है।

न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे के विकास की योजना पांच साल बढ़ी

'प्रेट्र' के मुताबिक, कई अदालतों के अब भी किराये के परिसरों में काम करने के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की खातिर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) 1993-94 से चल रही है। विस्तारित अवधि के दौरान यह एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी। इस दौरान 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिसमें 5,357 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा होगा। इसमें ग्राम न्यायालय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस फैसले से जिला व अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 3,800 अदालत कक्षों, 4,000 आवासीय इकाइयों, 1,450 वकील कक्षों, 1,450 शौचालय परिसरों व 3,800 डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण में मदद मिलेगी। राज्यों को पैसे तभी जारी किए जाएंगे जब अधिसूचित ग्राम न्यायालयों का संचालन शुरू हो जाएगा।

ओबीसी वर्गीकरण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की पिछड़ी जातियों की पहचान करने व वर्गीकरण के जरिये उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए गठित जस्टिस रोहणी आयोग के कार्यकाल को छह माह के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई के बजाए अब 31 जनवरी, 2022 तक हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया। आयोग के कार्यकाल में 11वीं बार बढ़ोतरी की गई है। ओबीसी के उपवर्गीकरण को लेकर केंद्र ने 2017 में इस आयोग का गठन किया था। आयोग को ओबीसी की जातियों का पता लगाने व वैज्ञानिक तरीके से इसके वर्गीकरण का जिम्मा सौंपा है। इसे लेकर आयोग काफी काम कर चुका है। राज्यों के साथ चर्चा करके अब उसे वर्गीकरण फार्मूले को अंतिम रूप देना है। माना जा रहा है कि आयोग का यह अंतिम विस्तार होगा।

अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए तीन सूत्रीय एजेंडा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एससीओ के तहत विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक में जयशंकर ने पेश किया भारत का एजेंडा



एस. जयशंकर। फाइल

अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से बढ़ते हमलों के बीच भारत ने वहां शांति स्थापित करने के लिए तीन सूत्रीय एजेंडा पेश किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान के मुद्दे पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह एजेंडा पेश किया। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष व लोकतांत्रिक देश बनाते हुए इस समूचे इलाके को आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त रखना है।

जिस बैठक में भारत ने यह एजेंडा पेश किया है उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी उपस्थित थे। जयशंकर ने पूर्व में तालिबान के निरंकुश शासन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य पूर्व की तरह नहीं हो सकता।

जयशंकर ने कहा, अफगान की जनता, इस क्षेत्र के लोग और पूरी दुनिया को एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, शांतिप्रिय हो और समृद्ध हो। यह भारत की तरफ से प्रस्तावित रोडमैप का पहला हिस्सा है। रोडमैप का दूसरा हिस्सा है सभी तरह की हिंसा का खात्मा करना और सरकार व नागरिकों पर आतंकी हमलों को रोकना व इसके लिए राजनीतिक समूहों व समुदायों में बातचीत की शुरुआत करना।

तीसरा एजेंडा है अफगानिस्तान के पड़ोसियों को आतंकवाद व उग्रवाद से बचाना। इन रोडमैप को हासिल करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री ने समग्र तौर पर सीजफायर लागू करने की बात कही है। भारत पहले भी यह मांग करता रहा है। जयशंकर ने कहा है कि शांति स्थापित करने के लिए गंभीरता से बात करना ही एक मात्र रास्ता है। दोहा, मास्को व इस्तांबुल प्रक्रिया के तहत शांति स्थापित करने के लिए जो वार्ताएं हुई हैं उन्हें अनिवार्य तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए।

अफगानिस्तान का भविष्य उसका बीता हुआ कल नहीं हो सकता पेज>>3

लखनऊ से अलकायदा के तीन और आतंकी गिरफ्तार

आतंकी मिनहाज को पिस्तौल मुहैया कराने में थी अहम भूमिका, अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल का बन चुके थे हिस्सा, हो रही पूछताछ



मोहम्मद मुस्तकीम



शकील



मोहम्मद मुईद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल के तीन और आतंकियों को बुधवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान लखनऊ के वजीरगंज थानाक्षेत्र स्थित बांसमंडी निवासी शकील, सीतापुर रोड स्थित तकिया तारनशाह मदेयगंज निवासी मुहम्मद मुस्तकीम व न्यू हैदरगंज कैंपवल रोड निवासी मुहम्मद मुईद के रूप में हुई है। मिनहाज को पिस्तौल मुहैया कराने व उप्र प्रदेश को दहलाने की साजिश में इन तीनों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। रविवार को लखनऊ से ही गिरफ्तार किए गए आतंकी मिनहाज व मसीरुद्दीन से पूछताछ में इन तीनों का नाम सामने आया था। एटीएस शकील की तलाश पहले से कर रही थी। वह 11 जुलाई को आतंकियों के विरुद्ध एटीएस के लखनऊ थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपित है।

मुख्य साजिशकर्ता मिनहाज ही: अब तक की छानबीन में सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता मिनहाज ही है। वह लखनऊ में रहकर अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल को विस्तार देने में जुटा था। वाराणसी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले इन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। हर संदिग्ध पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ठेके पर मकान बनाने का काम करता है मुस्तकीम पेज>>5

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राज्य सरकारों को मिलेगा अधिकार

नई दिल्ली : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। केंद्र ने ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के पहले के अधिकारों को बहाल करने के लिए संसद का रास्ता चुना है। संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में बिल लाने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र ने एससी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिये बदला था। आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। ज्ञात हो, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ अपने फैसले में जैसे ही यह कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ों की अलग से सूची बनाने का हक नहीं है। राज्यों में नया बवाल खड़ा हो गया। (पेज-3)

भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाएं राज्य, लापरवाह अफसरों पर करें कार्रवाई : केंद्र

नई दिल्ली : कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं और हिल स्टेशनों एवं बाजारों में बेपरवाह उमड़ती भीड़ पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाने और कोरोना प्रोटोकाल को लागू कराने के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक वाहनों में कोरोना से बचाव के आचरण का पालन नहीं किया जा रहा है। शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भल्ला ने कहा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए लोग कोरोना से बचाव के नियमों का जरूर पालन करें। (पेज-6)

सुप्रीम कोर्ट ने उप्र में कांवड़ यात्रा की अनुमति पर लिया स्वत : संज्ञान

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने संबंधी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र, उप्र एवं उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 16 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक और उप्र में सशर्त इजाजत संबंधी मीडिया में आई खबर को परेशान करने वाली बताया। कोर्ट ने कहा,लोग भ्रमित हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। पीठ ने कहा, इसी खबर के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने की एक और खबर छपी है जिसमें पीएम ने कहा है कि हमें इसे रोकना होगा। एक ही समय में भिन्न भिन्न राजनीतिक बयानों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार के संबंधित सचिव इस पर जवाब दें। (पेज-6)

प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में, 1583 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। कोरोना संकट के कारण लंबे समय बाद वाराणसी आ रहे मोदी जापान और भारत की मित्रता के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 744.82 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान समेत 206 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, पेयजल व सीवेज और ग्राम विकास की कई योजनाएं शामिल हैं। प्रोटोकाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी लगभग साढ़े दस बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। फिर हेलीकाप्टर से बीएचयू हेलीपैड आने के बाद सीधे आइआइटी टेक्नो ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान ही प्रधानमंत्री 1582.93 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। (पेज-5)

हौसले को सलाम

कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी सेना की जांबाज, 147 और एससीसी अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन, रक्षा मंत्रालय ने कहा, इन सभी को लेने होंगे सभी जरूरी प्रशिक्षण

सेना की महिला अधिकारियों का संघर्ष रंग लाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय सेना की शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) वाली कुल 147 अतिरिक्त महिला अधिकारियों को बुधवार को स्थायी कमीशन दिया गया। इन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में निर्धारित संशोधित मानक तय किए थे। इन महिला अधिकारियों ने अपने इस अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को कहा था कि महिला एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) देने के लिए सेना के मूल्यांकन मानदंड उनके साथ भेदभाव पूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार महिला अधिकारियों पर फिर से विचार किया गया और नए परिणामों को अब सार्वजानिक किया गया। परिणाम के अनुसार, 147 और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि कुल 615 में से 424 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया।

615 एसएससी महिला अधिकारियों में से 424 को पीसी

बयान में कहा गया कि कुछ महिला अधिकारियों के परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका पर स्थिति साफ होने के बाद इन परिणामों पर विचार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है शीर्ष अदालत ने फरवरी 2020 में एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि महिला एसएससी अधिकारियों को कमांड पोस्टिंग सहित सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए। इस संदर्भ में सेना ने महिला अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए सितंबर 2020 में एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया था। इसके परिणाम नवंबर 2020 में घोषित किए गए थे।

जिन महिला अधिकारियों को नवंबर 2020 में स्थायी कमीशन नहीं दिया गया वे सुप्रीम कोर्ट चली गईं। इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने पाया कि इन महिला अधिकारियों के प्रति सेना द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंड प्रणालीगत भेदभाव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के अपने आदेश में संशोधित मानदंड निर्धारित किए जिसके आधार पर सेना में स्थायी कमीशन के लिए महिला अधिकारियों का मूल्यांकन होगा।

रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सभी महिला अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन दिया गया, उन्हें सेना में उच्च नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और चुनौतीपूर्ण सैन्य असाइनमेंट से गुजरना होगा। 33 महिला अधिकारियों के एक बैच ने हाल ही में आर्मी वार कालेज महू से मध्य-स्तरीय टैक्टिकल ओरियंटेशन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी महिला एसएससी अधिकारी, जिनके विषय में सेना के चयन बोर्ड ने विचार किया और उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया, वे अभी भी कम से कम 20 साल की सेवा के अधीन पेंशन के लिए पात्र होंगी।

77 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के राजधानी में, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 76,095 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 0.10 फीसद सैंपल पाजिटिव पाए गए हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 जुलाई, 2021

सीबीआइ को सौंपी जाएगी बस खरीद व रखरखाव मामले की जांच : भाजपा

किया दावा ▸ राजनिवास में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व अन्य नेताओं ने धरना दिया

उपराज्यपाल द्वारा मांग माने जाने के बाद खत्म किया अपना धरना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद व रखरखाव मामले की जांच सीबीआइ करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेसवार्ता में कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भाजपा की यह मांग मान ली है।

प्रेसवार्ता से पहले आदेश गुप्ता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ सीबीआइ या भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने की मांग को लेकर राजनिवास पहुंचे। उनकी मांग मानने से इन्कार करने पर भाजपा नेता राजनिवास में ही धरने पर बैठ गए। बाद में उपराज्यपाल जांच सीबीआइ से कराने को तैयार हो गए, जिसके बाद नेताओं ने धरना समाप्त कर दिया।



डीटीसी बसों की खरीदारी व रखरखाव मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे (बाएं से) विजेंद्र गुप्ता, आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह बिधूड़ी। सौ.भाजपा

भाजपा दिल्ली सरकार द्वारा बस खरीद व रखरखाव के लिए जारी की गई निविदा में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। उसकी शिकायत पर उपराज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में रखरखाव के लिए जारी निविदा में कई कमी बताई गई है। वहीं, भाजपा इस जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि बस खरीद पर लगभग नौ सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि वारंटी अवधि में तीन साल के रखरखाव पर 35 सौ करोड़ रुपये खर्च किया जाना है। यह गलत है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है।

भाजपा विधायकों की शिकायत पर एसीबी ने जांच के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन उसे जांच की इजाजत नहीं दी गई। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने भी गड़बड़ी की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस खरीद और उनके रखरखाव के लिए निविदा जारी करने में नियमों की अवहेलना की गई है। निष्पक्ष जांच के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही डीटीसी के अन्य अधिकारियों को भी पद से हटाने की जरूरत है।

कांग्रेस ने भी की सीबीआइ से शिकायत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : डीटीसी बसों की खरीद और रखरखाव के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने सीबीआइ से शिकायत कर इस मामले में जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि पूरी टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुए भ्रष्टाचार की खबरें जब जनता के सामने आईं तो भाजपा के विधायकों ने एसीबी से शिकायत करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दिलवाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने इस पर भी हैरत जताई कि उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति ने बस टेंडर को खारिज करने के बावजूद किसी प्रकार की जांच का आदेश नहीं दिया।

जैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- रोहिणी में सीवेज पंपिंग स्टेशन के उद्घाटन स्थल पर नहीं पहुंच सके जल मंत्री सत्येंद्र जैन
- सोलंकी बोले, पेयजल न मिला तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों का होगा बहिष्कार

उत्तर-पश्चिमी जिला भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के राजा विहार में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब किया गया, जब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व जल मंत्री सत्येंद्र जैन राजा विहार की अनधिकृत कालोनी की सीवर लाइन व साढ़े चार मिलियन लीटर क्षमता के सीवेज पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन करने आने वाले थे। एक बार तो भाजपा कार्यकर्ताओं व आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति भी बन गई। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद होने के कारण स्थिति बिगड़ने नहीं पाई। भाजपा कार्यकर्ताओं को देखकर जैन को सीवर लाइन का उद्घाटन किए बिना ही लौटना पड़ा। उन्होंने पास ही एक मंच पर जाकर लोगों को संबोधित किया, लेकिन उद्घाटन नहीं किया। हालांकि बाद में जैन ने ट्वीट कर सीवर लाइन का उद्घाटन करने का दावा किया।

विजेंद्र गुप्ता बोले, दस जुलाई को ही मैं कर चुका हूं उद्घाटन : जहां पंपिंग स्टेशन व सीवर लाइन का उद्घाटन होना था, उस परिसर के बाहर देवेंद्र सोलंकी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जबकि अंदर रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मोर्चा संभाला हुआ था। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'सत्येंद्र जैन उस सीवर लाइन का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं, जिसका उद्घाटन मैं दस जुलाई को ही कर चुका हूं।'



रोहिणी विधानसभा के राजा विहार इलाके में सीवर लाइन के उद्घाटन स्थल पर काले झंडे व खाली मटके लेकर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता। इस सीवर लाइन का उद्घाटन करने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचने वाले थे पर प्रदर्शन के कारण वे यहां नहीं आ पाए। जागरण

देवेंद्र सोलंकी ने कहा कि पेयजल को लेकर उत्तर-पश्चिमी जिले में हाहाकार मचा है। कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने पेयजल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए फैसला किया गया है कि जब तक जिले के हर क्षेत्र में पेयजल नहीं आता, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों का बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसकी शुरुआत जल मंत्री सत्येंद्र जैन से की गई है। दिल्ली सरकार के विधायकों के घरों का भी घेराव किया जाएगा।

सोलंकी ने कहा कि लोग पेयजल की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। जहां पानी आ भी रहा है, वह पीने लायक नही हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार के मंत्री सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का काम सिर्फ उद्घाटन व पोस्टरों तक ही सीमित है। जैन के जाने के बाद कालोनी में भाजपा ने रैली भी निकाली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने सत्येंद्र जैन व आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए।

न्यूज गैलरी

वीमारों की मदद को क्राउड फंडिंग शुरू नहीं होने पर कोर्ट सख्त

नई दिल्ली : दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल क्राउड फंडिंग प्लेटफार्म 31 मार्च तक शुरू करने के आदेश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार को चेताया कि अगर प्लेटफार्म संचालित नहीं किया गया तो केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने प्रतिक्रिया तब दी जब केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि प्लेटफार्म संचालित हुआ या नहीं। इस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस तरह के जवाब से आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। (जासं)

सिपाही पद की भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी, 11 गिरफ्तार

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को 11 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दूसरे की जगह फिजिकल टेस्ट दे रहे थे। आरएफआइडी सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने इन आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सोनिया विहार थाने में अब तक 21 आरोपितों के खिलाफ 14 एफआइआर दर्ज की जा चुकी है। डीसीपी श्वेता चौहान के मुताबिक विगत 28 जून से दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट सेल राजधानी में तीन जगहों पर सात मैदानों में सिपाही पद के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में कुल 67 हजार 740 युवाओं ने आवेदन किया है। सिपाही के करीब साढ़े पांच हजार पद भरे जाने हैं। (जासं)

राजधानी में टीके की कमी से थमी टीकाकरण की रफ्तार

नई दिल्ली : राजधानी में टीके की कमी के कारण बुधवार को सिर्फ एक लाख 29 हजार 54 लोगों को ही टीका लग सका। इनमें 92 हजार 547 लोगों को टीके की पहली और 36 हजार 507 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। इससे एक बार फिर टीकाकरण की रफ्तार थम गई। इससे पहले यह आंकड़ा दो लाख से ऊपर रहता था। टीके की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्र बंद रहे। दिल्ली सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार सुबह स्टाक में कोविशील्ड की 63 हजार 840 डोज थीं, जो शाम तक टीकाकरण के बाद खत्म हो गईं। (जासं)

मानसून की पहली झमाझम बारिश से बदली दिल्ली की फिजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- बुधवार को सुबह से देर शाम तक रुक-रुककर चला बारिश का दौर, कई इलाकों में तो पानी जमकर बरसा
- रिज क्षेत्र में दर्ज हुई सर्वाधिक 107.4 मिमी बारिश, अगले छह दिन तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

मंगलवार को उमस भरी गर्मी से जूझ रहे दिल्लीवासियों को मानसून की दस्तक से राहत मिली तो बुधवार को मानसून की पहली झमाझम बारिश ने जमकर भिगोया। सुबह से शाम तक रुक-रुककर हुई इस बारिश ने दिल्ली की फिजा भी बदल दी। कई इलाकों में तो भारी बारिश हुई। मौसम विभाग अनुमान है कि बारिश का यह दौर अभी जारी रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 28.5 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। लगातार दो दिन बारिश होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश की वजह से हवा में नमी का स्तर 60 से 100 फीसद रहा।

रिज क्षेत्र में सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक सर्वाधिक 107.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। यह पिछले पांच सालों में रिकार्ड बारिश बताई जा रही है। मालूम हो कि 15 मिमी से नीचे दर्ज होने वाली बारिश को हल्की, 15 से 64.5 मिमी के बीच मध्यम, 64.5 मिमी और 115.5 मिमी के बीच भारी, 115.6 और 204.4 मिमी के बीच बहुत भारी माना जाता है। 204.4 मिमी से ऊपर अत्यधिक भारी वर्षा मानी जाती है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में भी राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि सप्ताह भर तक बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया गया। सप्ताह के आखिर तक तापमान 33 डिग्री तक आ जाएगा। लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

जलभराव से जनजीवन रहा प्रभावित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में लगातार दूसरे दिन हुई मानसून की बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई तेज बारिश से जगह-जगह सड़कों और फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। इससे वाहन धीमी गति से रेंगते रहे। आजादपुर अंडरपास के नीचे पानी भरने से इसे बंद कर दिया गया। साथ ही यहां से गुजरने वाले यातायात को मुकरबा चौक और वजीरपुर तिराहे की ओर डायवर्ट करना पड़ा। साथ ही कई इलाकों में बाजारों और घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। इससे लोगों को काफी दिक्कतें हुईं। कई जगह पेड़ गिरने से भी लोगों को निकलने में परेशानी हुई। कई इलाकों में निगम की ओर से पानी निकाल दिया गया, लेकिन अधिकतर इलाकों में देर शाम तक पानी भरा रहा।

इन जगहों पर लगा जाम : रिंग रोड, आइटीओ चौराहा, मिंटो रोड, विकास मार्ग, मदर डेयरी रोड, कश्मीरी गेट, मथुरा रोड, सराय काले खां, एनएच-91, आश्रम चौक, डीएनडी, कालिंदी कुंज, आजादपुर से मुकरबा चौक तक, आजादपुर मंडी, रिठाला से पीतमपुरा चौक तक, पीरागढ़ी



बुधवार को राजधानी में हुई झमाझम बारिश व जलभराव से विकास मार्ग पर जाम से जूझते लोग। संजय

चौक, केएन काटजू मार्ग, धौला कुआं सहित कई जगहों पर जाम लगा।

इन इलाकों में हुआ जलभराव : आइटीओ पर पुराने पुलिस मुख्यालय के पीछे बहादुरशाह जफर मार्ग, एमसीडी आटो वर्कशाप ओखला, मालवीय नगर, मुखर्जी नगर वीआइपी कालोनी, आजादपुर अंडरपास, गणेश नगर अंडरपास, किराड़ी, कुतुबगढ़, लाडपुर, रिठाला, बवाना, रोहिणी-हेलीपोर्ट रोड, कराला, कंझावला, बेगमपुर, रामा विहार, मुबारकपुर, रानी खेड़ा, माडल टाउन, आजादपुर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बादली अंडरपास, ब्रह्मपुरी, करावल नगर, मूंगा नगर, मुस्तफाबाद, विश्वास नगर, वेलकम, गांधी नगर, प्रीत विहार, त्रिलोकपुरी, वजीराबाद रोड, मयूर विहार, मंडावली, गीता कालोनी, दिलशाद गार्डन, न्यू अशोक नगर, पांडव नगर, दयालपुर, लक्ष्मी नगर, घोंडा, झिलमिल, मंडावली व केशव चौक अंडरपास, पालम फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन, नजफगढ़ व जनकपुरी आदि जगहों पर जलभराव हुआ।

इन जगहों पर गिरे पेड़ : निगम बाल विद्यालय लाडो सराय, सीआर पार्क, डिफेंस कालोनी और जनकपुरी।

अब बसों के लिए नहीं करना होगा इंतजार, गूगल एप्स से जुड़ेंगी बसें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में बसों के लिए लोगों को घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को गूगल एप्स से जोड़ दिया है। इस माध्यम से दिल्लीवासी आखिरी मिनट तक यात्रा की योजना बना सकेंगे। इस पहल के बाद गूगल पर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल सकेगी। उपयोगकर्ता को गूगल प्लेटफार्म पर बसों के वास्तविक समय में मार्ग, सभी बस स्टाप, आगमन और प्रस्थान का समय प्रदर्शित होगा। सार्वजनिक बसों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की है। गूगल मैप्स से आज हुई साझेदारी के साथ दिल्ली वैश्विक शहरों की सूची में शामिल हो गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए बुधवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इस कदम से दिल्ली उन वैश्विक शहरों में शामिल हो गई है, जो सार्वजनिक परिवहन की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि लोग आखिरी मिनट तक अपनी यात्रा की योजना बना सकें। इस सुविधा के वर्चुअल लांच के दौरान दिल्ली संवाद और विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, परिवहन आयुक्त व गूगल इंडिया के अधिकारी भी उपस्थित थे। गहलोत ने बताया कि यह सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध है और उपयोगकर्ता गूगल मानचित्र सेटिंग में या डिवाइस भाषा सेटिंग में भी भाषा बदल सकते हैं।

सिंगापुर, लंदन, न्यूयार्क जैसी होगी सुविधा : डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि हम चाहते थे कि दिल्ली के निवासियों को दिल्ली के किसी भी स्टाप से बसों की वास्तविक समय आगमन की जानकारी प्राप्त हो। जैसे आप एप आधारित टैक्सी के वास्तविक समय स्थान को देख सकते हैं। साथ ही हम यह भी चाहते थे कि यह जानकारी एक-दो एप्स तक सीमित न हो, बल्कि 100 नवीन ऐप्स हों- जैसा कि आप सिंगापुर या लंदन या न्यूयार्क जैसे वैश्विक शहरों में देखते हैं। गूगल के निदेशक (उत्पाद प्रबंधन) रमेश नागराजन ने कहा कि हम लगातार गूगल मैप्स के अनुभव को और अधिक उपयोगी बनाने के तरीके तलाश रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विशेष रूप से इन समय में दिल्ली के लोगों को स्मार्ट यात्रा विकल्प बनाने में इस जानकारी तक पहुंच बनाने से लाभ होगा।

बुजुर्ग महिला की हत्या कर चार घंटे तक शव के टुकड़े करता रहा दंपती

जासं, नई दिल्ली : मोहन गार्डन में बुजुर्ग महिला कविता ग्रोवर की हत्या मामले में पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अनिल आर्य व तनु आर्य के रूप में हुई। दंपती ने बुजुर्ग महिला से डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे। बार-बार मांगने से नाराज आरोपितों ने कविता की गला दबाकर हत्या की और बाद में रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से चार घंटे तक शव के टुकड़े करता रहा। अगले दिन सुबह शव के टुकड़े को दो बैग में भरकर नजफगढ़ नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नजफगढ़ ड्रेन से बैग, हत्या में प्रयुक्त चाकू व बुजुर्ग महिला का पर्स बरामद कर लिया है। बुजुर्ग महिला से आरोपितों की पहचान काफी समय से थी।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि तीन जुलाई को कविता ग्रोवर की पुत्रवधू मेघा ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का पता नहीं लगने के बाद अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। स्थानीय लोगों से पूछताछ व घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने आरोपित दंपती की पहचान कर ली।

तुगलकाबाद से एयरोसिटी के बीच कारिडोर परियोजना में बदलाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- रंगपुरी पहाड़ी में अब नहीं बनेगा मेट्रो डिपो
- आठ हजार वृक्षों को बचाने के लिए लिया गया फैसला

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण में बड़ा बदलाव किया है। रंगपुरी पहाड़ी में मेट्रो डिपो बनाने का प्रस्ताव था, जिससे लगभग आठ हजार वृक्ष काटने पड़ते। इन्हें बचाने के लिए अब यहां पर मेट्रो का डिपो नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही तुगलकाबाद से एयरोसिटी मेट्रो कारिडोर को रिज प्रबंधन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

मेट्रो के चौथे चरण में तुगलकाबाद से एयरोसिटी के बीच कारिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कारिडोर रिज क्षेत्र से होकर गुजरेगा। निर्माण कार्य से रिज क्षेत्र में वृक्षों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर रिज प्रबंधन बोर्ड ने डीएमआरसी को इस कारिडोर में बदलाव करने का सुझाव दिया था। इस मुद्दे को लेकर बोर्ड व डीएमआरसी के अधिकारियों की बैठक हुई। डीएमआरसी के अधिकारियों ने कारिडोर में बदलाव में असमर्थता जताई। साथ ही उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए रंगपुरी पहाड़ी में 31 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले मेट्रो डिपो के प्रस्ताव को वापस लेने



दिल्ली की लाइफ लाइन है मेट्रो। फाइल फोटो

का प्रस्ताव रखा जिसे सहमति दे दी गई। नया डिपो बनाने के बजाय सरिता विहार व अजरौंदा स्थित डिपो से इस नए कारिडोर की जरूरत पूरी की जाएगी। इसके लिए सरिता विहार डिपो तक नई लाइन बिछाई जाएगी। तुगलकाबाद-एयरोसिटी कारिडोर की कुल लंबाई 23.62 किलोमीटर होगी। 19.34 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत व 4.27 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। इस पर 16 स्टेशन होंगे। एलिवेटेड कारिडोर का काम चल रहा है। भूमिगत कारिडोर के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया है। इग्नू व महरौली से महिपालपुर के बीज कारिडोर का हिस्सा रिज क्षेत्र में आएगा।

जांच में लापरवाही बरतने पर पुलिस पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली दंगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली दंगे के दौरान भजनपुरा इलाके में दंगाइयों द्वारा एक व्यक्ति की आंख में गोली मारने के मामले में लापरवाही से जांच करने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी को गोली लगी और पुलिस ने जानलेवा हमले व शस्त्र अधिनियम की धारा नहीं जोड़ी। यह बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है। इस पर कोर्ट ने भजनपुरा थानाध्यक्ष और उनके पर्यवेक्षक अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर पूर्वी जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वह जुर्माना वसूल कर एक सप्ताह में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में जमा कराएं। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति आयुक्त को भेजने का निर्देश भी दिया है।

शिकायतकर्ता मुहम्मद नासिर ने पुलिस से गत वर्ष 19 मार्च को शिकायत की थी। उसमें बताया था कि 24 फरवरी को दंगाइयों ने उन पर गोली चलाई थी, जो उनकी आंख में लगी थी। जीटीबी अस्पताल में उनका इलाज हुआ था। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया। इस मामले में गत वर्ष 21 अक्टूबर को महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट ने पुलिस को अलग मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने उस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करते हुए कहा था कि इस घटना को लेकर पहले ही एक मुकदमा दर्ज है। उसमें शिकायतकर्ता के नाम का भी जिक्र किया गया था। साथ ही बताया था कि शिकायतकर्ता ने जिन सात व्यक्तियों पर आरोप लगाया है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने पुलिस की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटना गत वर्ष 24 फरवरी की थी और अगले दिन मोहनपुर मौजपुर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया गया था। पुलिस को पता था कि घटना में गोली लगने से कुछ लोग घायल हुए थे, उसके बावजूद जानलेवा हमले व शस्त्र अधिनियम की धारा नहीं लगाई गई। इस मामले में कई केस डायरियां लिखी गईं। इनको तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया।

नोएडा एयरपोर्ट

इसी सप्ताह होगा शेयर होल्डर एग्रीमेंट

नियाल और विकासकर्ता कंपनी के सीईओ करेंगे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर, अधिगृहीत जमीन इसी सप्ताह नियाल के नाम पर लीज होगी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) व यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच इसी सप्ताह शेयर होल्डर एग्रीमेंट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नियाल सीईओ को हस्ताक्षर के लिए अधिकृत किया गया है। एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत की गई 1334 हेक्टेयर जमीन की इसी सप्ताह नियाल के नाम पर लीज होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए नियाल का गठन किया है। प्रदेश सरकार की ओर से नियाल नोएडा एयरपोर्ट से संबंधित कार्य संपन्न कराएगी। इसके मद्देनजर इसी सप्ताह नियाल व विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट होगा। प्रदेश सरकार ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए नियाल के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह को अधिकृत कर दिया है। विकासकर्ता कंपनी की ओर से सीईओ क्रिस्टोफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे।

नियाल को लीज पर दी जाएगी जमीन

नागरिक उड्डयन विभाग इसी सप्ताह नोएडा एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत 1334 हेक्टेयर जमीन की लीज नियाल के नाम पर करेगा। एयरपोर्ट निर्माण के लिए नियाल यह जमीन विकासकर्ता कंपनी को सौंपकर भौतिक कब्जा देगी। विकासकर्ता कंपनी को जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहले ही पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन विस्थापन कार्य पूरा न होने के कारण यह काम आगे नहीं बढ़ा। अब विस्थापन कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। एयरपोर्ट से प्रभावित सभी छह गांव रोही, पारोही, दयानतपुर, किशोरपुर, रन्हेरा की प्रभावित आबादी ने जेवर बांगर में पुनर्वास कर लिया है।

स्टांप शुल्क पर खर्च होंगे 96 करोड़

नोएडा एयरपोर्ट की जमीन की लीज नियाल के नाम पर होने में 96 करोड़ स्टांप शुल्क लगेगा। नियाल में शामिल प्रदेश सरकार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण अपनी अंशधारिता के हिसाब से यह रकम जारी कर चुके हैं।

मास्टर प्लान पर केंद्रीय मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार

नोएडा एयरपोर्ट के संशोधित मास्टर प्लान पर केंद्रीय मंत्रालयों की हरी झंडी का इंतजार है। विकासकर्ता कंपनी ने दिसंबर में एयरपोर्ट का मास्टर प्लान नियाल को सौंपा था। इसे परीक्षण एवं सुझाव के लिए नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि को भेजा गया था। उनके सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित मास्टर प्लान तैयार कर फिर से केंद्रीय मंत्रालयों को भेजा गया है। इस पर सहमति मिलते ही यमुना प्राधिकरण व नियाल बोर्ड में इसे स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

इस बार भी वर्चुअल प्लेटफार्म पर होगा दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- मेले की थीम रहेगी- कोरोना काल में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य, प्रवेश होगा निःशुल्क

दिल्ली पुस्तक मेला इस बार भी वर्चुअल ही होगा। मेला सितंबर के पहले हफ्ते में होगा और तीन दिन का रहेगा। हालांकि भारतीय प्रकाशक संघ (एफआइपी) और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) के बीच प्रगति मैदान में पुस्तक मेले के आफलाइन आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर के कारण इसकी अनुमति मिलने की उम्मीद कम होने के कारण इसके वर्चुअल संस्करण पर ही मुहर लगा दी गई है।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन तीन से पांच सितंबर के दौरान होगा। मेले की थीम कोरोना काल में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य रखी गई है। मेले के लिए 25 स्टालों की बुकिंग भी हो गई है, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। मेले में पाठकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। खास बात यह है कि इस बार इस मेले में नवोदित लेखकों के लिए अपनी पांडुलिपि प्रदर्शित करने के लिए भी अलग से एक कार्नर बनाया जा रहा है ताकि लेखक और प्रकाशक का आपस में संवाद स्थापित हो सके। पिछले साल जब पहली बार यह मेला वर्चुअल हुआ तो दो दिन का रखा गया था और इसमें करीब दो लाख लोगों की हिस्सेदारी रही थी। इसीलिए इस बार इसे तीन दिन का कर दिया गया है। मेले में थीम के अनुरूप ही थीम मंडप भी रहेगा। इसमें कोरोना काल के दौरान की स्थितियों पर विभिन्न पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। साथ ही वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा लेखकों और पाठकों के बीच चर्चा एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह भी आनलाइन ही आयोजित होंगे।

> कोरोना प्रोटोकाल का पालन भी जरूरी है और सालाना मेले का आयोजन भी अनिवार्य है। इसीलिए इस बार फिर वर्चुअल प्लेटफार्म ही चुना गया है। पिछले साल के सफल आयोजन और पूर्णतया सुरक्षित होने के चलते पाठकों एवं प्रकाशकों का सहयोग भी उत्साहजनक देखने को मिल रहा है।
>
> -नवीन गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली पुस्तक मेला आयोजन समिति, एफआइपी

26 हजार आवेदन मिल चुके हैं सरकार को बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए। इनमें 9,700 छात्राएं भी शामिल हैं। योजना में जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक कर्ज मिल सकेगा।

निकट भविष्य में भारत से सैन्य मदद की पड़ेगी जरूरत : मामुंदजई

साक्षात्कार

अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों में तालिबान की तरफ से युद्ध जैसे हालात बना दिए गए हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत की चिंता भी लाजिमी है, क्योंकि उसने वहां अरबों डालर की मदद भेजी है और वहां तालिबान का मजबूत होना भारत अपने रणनीतिक हितों के लिए सही नहीं मानता। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजदूत **फरीद मामुंदजई** ने विशेष संवाददाता **जयप्रकाश रंजन** के साथ अपने देश के हालात और भारत की भावी भूमिका के बारे में विस्तार से बात की। मामुंदजई नई दिल्ली में कार्यरत उन गिने-चुने विदेशी राजनयिकों में से हैं जो खुलकर हिंदी बोलते हैं।


फरीद मामुंदजई (सौ. ट्विटर)

> तालिबान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 21 आतंकी संगठन और हैं जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद और अल-कायदा भी हैं।

> तालिबान का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं, जो 20 साल पहले भी सक्रिय थे और इस संगठन के नेता थे। इनका इंसानियत पर भरोसा नहीं है।

> तालिबान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 21 आतंकी संगठन और हैं जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद और अल-कायदा भी हैं।

> यह 30 साल पुराना भारत नहीं है। आज का भारत विश्व की अहम शक्ति है, जिसकी बात सभी सुनेंगे। उम्मीद है कि भारत अपनी छवि और ताकत का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में शांति बहाली का कूटनीतिक प्रयास करेगा।

• अभी अफगानिस्तान की ताजा स्थिति क्या है? तालिबान का कितना प्रभाव हो चुका है?

- हालात तो बहुत गंभीर हैं। 14 अप्रैल, 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी का एलान किया था और उसके बाद से तालिबान की तरफ से युद्ध जैसे हालात बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। लगभग एक तिहाई इलाके में युद्ध की स्थिति है। इस बीच चार हजार लोगों की मौत हो चुकी है और तीन लाख लोग बेघर हो चुके हैं। कोरोना की वजह से आंतरिक हालात पहले ही खराब थे, अब और बुरा दौर चल रहा है। आतंकवाद को मानने वाली शक्तियां एकजुट हैं। तालिबान अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 21 आतंकी संगठन और हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद और अल-कायदा भी हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार जिम्मेदारी से अपनी जनता और देश को बचाने की कोशिश में है। हमें लगता है कि अमेरिका ने सेना वापसी में जल्दबाजी की है, उसे हमें और समय देना चाहिए था ताकि इस तरह की शक्तियों से मुकाबले के लिए और तैयार हो सकें।

• कहा जा रहा है कि इस बार का तालिबान अलग है। क्या यह सच है, क्या तालिबान इस तरह का संकेत दे रहा है?

- जो लोग यह तर्क दे रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि तालिबान का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं, जो 20 साल पहले भी सक्रिय थे और इस संगठन के नेता थे। इनका आतंकवाद पर भरोसा है। ये वही लोग हैं जो स्कूलों-कालेजों के खिलाफ हैं, जो आधुनिकता के खिलाफ हैं। अभी आपने देखा होगा कि कैसे अफगानिस्तान के 22 ऐसे सैनिकों को शहीद किया है जो निहत्थे थे और आत्मसमर्पण कर चुके थे। इनका इंसानियत पर भरोसा नहीं है। नार्थ-ईस्ट के प्रांतों में तालिबान ने मध्ययुगीन प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। आप संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट देखिए, इनके साथ के लोगों का रिकार्ड देखिए, इनकी सोच नहीं बदली है। अभी हाल में इन्होंने काबुल में विद्युत आपूर्ति लाइन को उड़ा दिया, यह भी नहीं सोचा कि इस बिजली की वहां के अस्पतालों और स्कूलों को भी जरूरत है। तालिबान बदला है, यह कहने वालों को पहले आम अफगानियों से बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वे तालिबान के बारे में क्या सोचते हैं।

• तालिबान के साथ दुनिया के कई देशों में शांति वार्ता हो रही है, इसका कोई नतीजा निकलता दिख रहा है?

- अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए कई जगहों पर बात हो रही है। अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं, तब भी (बुधवार को) दुशांबे में कई देशों की बैठक हो रही है। दोहा में जल्द ही बैठक की तैयारी है। ईरान में भी इस बारे में प्रयास हो रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह इस तरह की वार्ता के पक्ष में है, लेकिन तालिबान इसकी आड़ में ज्यादा समय लेने में लगा है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा इलाकों में युद्ध जैसे हालात बना सके। अफगान सरकार के प्रतिनिधि दोहा में पिछले 10 महीनों से हैं, लेकिन बातचीत का नतीजा ऐसा नहीं है, जिसे हम उपलब्धि कह सकें। शांति के लिए उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ, तालिबान का एकमात्र मकसद यह है कि वह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काबिज हो सके, ताकि बाद में दावा कर सके कि उसे ज्यादा समर्थन हासिल है।

• ऐसे में भारत कैसे मदद पहुंचा सकता है?

- भारत कई तरह से मदद कर सकता है। यह 30 साल पुराना भारत नहीं है। आज का भारत विश्व की अहम शक्ति है जिसकी बात सभी सुनेंगे। हमें उम्मीद है कि भारत अपनी छवि और ताकत का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में शांति बहाली का कूटनीतिक प्रयास करेगा। संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से आस है कि वह एक शांतिप्रिय, आतंकवाद से मुक्त अफगानिस्तान बनाने की बात उठाता रहेगा। दूसरा, हमें भारत से अगले 10 वर्षों तक ढांचागत विकास में मदद चाहिए, ताकि हम और मजबूत हो सकें।

• क्या भारत से सैन्य मदद की जरूरत है?

- अभी भारत से सैन्य मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सेना की तरफ से कुछ साजो-समान और हथियार हमें मुहैया कराए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी के बाद यह मदद न मिले तब हमें भारत से सैन्य मदद चाहिए। भारत को वहां अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक साथ कई आतंकी संगठनों से लंबे समय तक लड़ने के लिए हमें हेलीकाप्टर, हथियार और दूसरे साजो-समान चाहिए। हमारे पास चार लाख सैनिकों की सेना है जो काफी सक्षम है। भारत हमारा पड़ोसी है और इस क्षेत्र में शांति में ही उसका हित है। यूरोपीय देश और अमेरिका आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन भारत व यहां के देशों के हित स्थायी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना इस समूचे क्षेत्र व भारत के लिए खतरा है। तालिबान पाकिस्तान के लिए भी खतरा साबित होगा। हम पाकिस्तान से आग्रह कर रहे हैं, उसका प्रभाव तालिबान पर सबसे ज्यादा है। इसलिए वह उन्हें शांति की राह पर आने के लिए समझाए। पाकिस्तान सरकार हमसे वादा भी करती है, लेकिन इसका कोई असर अभी तक देखने को नहीं मिला।

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा, मानसून सत्र में पूरी तैयारी के साथ आएं

▸ सत्र के लिए सरकार ने 17 नए विधेयकों को किया है सूचीबद्ध

▸ 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से कहा कि संसद के मानसून सत्र में वे पूरी तैयारी के साथ आएं।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे होमवर्क करने और सत्र के दौरान सरकार का दृष्टिकोण प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान संसदीय कार्यवाही और नियमों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे सभी कार्यवाहियों से परिचित हो लें।

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें पेश करने के लिए सरकार ने 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। छह अन्य विधेयक दोनों सदनों में विभिन्न चरणों में लंबित हैं।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लंबे अर्से के बाद नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट की फिजीकल बैठक हुई। प्रेट्र

रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक : समाचार एजेंसी 'एएनआइ' के मुताबिक, मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की संभावना है। इसी तरह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी रविवार को लोकसभा में सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई है। 'आइएएनएस' के मुताबिक, यह बैठक भी संसद परिसर में सुबह 11 बजे होने की संभावना है।

रविवार को भाजपा संसदीय दल की भी बैठक : मानसून सत्र से पहले रविवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। इसके अलावा उसी दिन राजग में शामिल दलों के नेताओं की भी बैठक निर्धारित है। इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ के आवास पर भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 20 वरिष्ठ पार्टी नेता उपस्थित थे।

'एलएसी विवाद को लंबा खींचना दोनों देशों के हित में नहीं'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच तकरीबन 10 महीने बाद एक बार फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को लेकर बातचीत हुई। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दुशांबे में हुए आयोजन के दौरान एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की अलग से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इसमें एलएसी पर बने हालात पर खासतौर से चर्चा हुई। करीब एक घंटे चली बातचीत में तनाव खत्म करने पर कोई सहमति बनती नहीं दिखी। हालांकि, भारत ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है एलएसी विवाद को लंबा खींचना दोनों देशों के हित में नहीं है।

जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि एलएसी पर अपनी तरफ से यथास्थिति बदलने वाला कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, दोनों पक्ष आगे भी बात करने को राजी हैं जो एक शुभ संकेत है।

बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि स्टेट काउंसिलर व विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक घंटे द्विपक्षीय बैठक चली। बातचीत मुख्य तौर पर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एलएसी में तनाव के मुद्दे पर केंद्रित रही। इस बात को खास तौर पर बताया गया कि अपनी मर्जी से स्थिति को बदलने वाला कदम स्वीकार नहीं होगा। हमारे संबंधों को बेहतर करने के लिए यह जरूरी है कि सीमा पर पूरी तरह से शांति व स्थायित्व हो। हमारे बीच वरिष्ठ कमांडरों के बीच शीघ्र ही वार्ता करने को लेकर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया है कि दोनों मंत्रियों के बीच आगे भी संपर्क में बने रहने की सहमति बनी है।


दुशांबे में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर चीनी समकक्ष वांग यी के साथ। प्रेट्र

वांग यी व जयशंकर के बीच इस तरह की एक और मुलाकात सितंबर, 2020 में मास्को में एससीओ के आयोजन के दौरान हुई थी। उसमें दोनों मंत्रियों के एलएसी पर तनाव समाप्त करने के लिए पांच सूत्रीय फार्मूले पर सहमति बनी थी। इस फार्मूले के आधार पर सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता के कई दौर चले थे, जिसकी वजह से दिसंबर, 2020 और फरवरी, 2021 में तनाव भरे कुछ इलाकों से सैनिकों की वापसी की गई। हालांकि, अभी भी एलएसी के कई ऐसे इलाके हैं जहां चीन वादा करने के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि जयशंकर ने चीन के पक्ष को सितंबर, 2020 की बैठक में बनी सहमति के बारे में बताया और कहा कि उसे पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। जयशंकर ने यह भी बताया कि पैंगोंग झील इलाके में सफलतापूर्वक सैनिकों की वापसी के बावजूद दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं हो सका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीनी दल भारत के साथ इस लक्ष्य के लिए फिर से काम करेगा, क्योंकि वहां हालात ठीक नहीं हो पाए हैं। जयशंकर ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस बात के लिए भी राजी थे कि इस तरह के हालात को लंबे समय तक बनाए रखना किसी के हित में नहीं है। यह द्विपक्षीय रिश्तों पर नकारात्मक असर डाल रहा है। भारत व चीन के रिश्तों में वर्ष 1988 से जो प्रगति हुई है उसके लिए सीमा पर शांति का भी योगदान है। यह दोनों पक्षों के हित में है कि एलएसी पर तनाव का शीघ्रता से हल निकाला जाए। दोनों मंत्रियों ने इस विवाद के समाधान के लिए सीनियर कमांडरों के नेतृत्व में चल रही बातचीत का अगला दौर जल्द ही करने की सहमति जताई। आगामी बैठक में तनाव का दोनों पक्षों की तरफ से स्वीकार्य समाधान निकालने पर जोर होगा। यह भी सहमति बनी है कि दोनों तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे हालात बिगड़ें।

अफगानिस्तान का भविष्य उसका बीता हुआ कल नहीं हो सकता

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका बीता हुआ कल नहीं हो सकता। उन्होंने सीधे तौर पर तालिबान को मदद देने वाले देश पाकिस्तान व उसकी एजेंसियों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि कई ऐसी शक्तियां अफगानिस्तान में सक्रिय हैं जो अलग एजेंडे पर काम कर रही हैं। इन्हें वैध नहीं ठहराया जा सकता। ताकत की बदौलत जबरन सत्ता कब्जा करने को सहन नहीं किया जा सकता।

इस बैठक से पहले एससीओ के विदेश मंत्रियों की अलग से हुई बैठक में जयशंकर ने भारत की तरफ से एक बार फिर आतंकवाद को फंडिंग करने वाले देशों पर एससीओ की तरफ से कदम उठाने की मांग की। एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में यह बात पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उठा चुके हैं। भारत की यह मांग पाकिस्तान के संदर्भ में है जो आतंकवाद को फंडिंग देने के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के खतरे का सामना कर रहा है।

पीयूष गोयल का बढ़ा कद, राज्यसभा में होंगे नेता सदन

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद के 19 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रोन्नत करके राज्यसभा में नेता सदन नियुक्त किया गया है। वह थावर चंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में सरकार का विधायी एजेंडा पूरा करने के लिए उन्हें कई राजनीति चुनौतियों से निपटना होगा। उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उन्हें नई भूमिका के लिए शुभकामना दी। अभी तक पीयूष गोयल राज्यसभा में उपनेता की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। सदन के नेता के रूप में नियुक्ति से भाजपा में उनका राजनीतिक कद बढ़ा है, क्योंकि इस पद पर कभी जसवंत सिंह और अरुण जेटली जैसे दिग्गज रह चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, 'मुझे विश्वास है कि पीयूष भाई अपने समर्पण, क्षमताओं व ऊर्जा से राज्यसभा में भाजपा की बुलंद आवाज बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य संकल्प को मजबूत करेंगे।' 57 वर्षीय पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों और कपड़ा समेत विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार है।


केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भाजपा द्वारा रास में सदन का नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई देते केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी। प्रेट्र

2014 में केंद्रीय मंत्री बनने से पहले पीयूष गोयल पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। समाचार एजेंसी 'एएनआइ' के मुताबिक, वह 1984 से भाजपा से जुड़े हैं और संगठन के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह पार्टी की सूचना संवाद प्रचार समिति के प्रमुख थे और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की घोषणापत्र एवं प्रचार समिति के सदस्य थे।

प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मुहम्मद सोलिह ने बुधवार को भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश में कोविड-19 महामारी के बावजूद विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में पर संतोष व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने फोन पर सोलिह के साथ बातचीत की और उन्हें महामारी से संघर्ष में मालदीव को समर्थन देने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रपति सोलिह ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सहयोग और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में मदद के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने मालदीव में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास (सागर) में मालदीव मध्य स्तंभ है। मोदी ने ट्वीट किया है, 'मालदीव के राष्ट्रपति एटआइबीयूसोलिह से बातचीत की। उन्हें कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में मालदीव की मदद करने की भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। हमने द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।'

ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को मिलेगा अधिकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मानसून सत्र में लाएगा बिल, पहले जैसी व्यवस्था होगी बहाल

▸ सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने की थी इसकी पैरवी, लेकिन अदालत ने खारिज कर दी थी पुनर्विचार याचिका


सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान कर बना सकेंगे सूची। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकारों में फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी। केंद्र ने ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के पहले के अधिकारों को बहाल करने के लिए अब संसद का रास्ता चुना है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र ने एससी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिये बदला था, जिसमें पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया था।

आरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ अपने फैसले में जैसे ही यह कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद तो राज्यों में नया बवाल खड़ा हो गया।

सूत्रों की माने तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद नए मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी अधिकारियों के साथ इस पर लंबी मंत्रणा की है। साथ ही अधिकारियों को इस पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले थावरचंद गहलोत ने भी राज्यों के अधिकार बहाली की वकालत की थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी पुनर्विचार याचिका : खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान दिए गए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी। इसमें राज्यों के ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के अधिकारों को बहाल करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

सतर्क है केंद्र सरकार

केंद्र इस मामले को लेकर इसलिए भी सतर्क है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने राज्य सूची के आधार पर अपने यहां अलग-अलग जातियों को पिछड़े वर्ग में जगह दे रखी है। इसका लाभ भी वे राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में ले रहे हैं। अब तक ओबीसी आरक्षण पर केंद्र और राज्यों की अलग-अलग सूची है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूदा समय में करीब 2,600 जातियां शामिल है।

एलएसी और अफगानिस्तान पर चर्चा नहीं कर सके राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को रक्षा संबंधी की संसद की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा के लिए लाए गए विषय को लेकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि समिति की बैठक में सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद जुआल ओरांव की अध्यक्षता वाली समिति में शामिल कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया।

एक अन्य विपक्षी दल के नेता ने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया: एक सूत्र ने बताया, बैठक के एजेंडे में छावनी बोर्डों कामकाज पर चर्चा करना शामिल था। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली कुछ बैठकों से लगातार इसी पर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पर बात हो, लेकिन चीन सीमा पर जो कर रहा है और अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ऐसे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार, इस पर समिति के प्रमुख ओरांव ने कहा कि जो विषय एजेंडे में है, उसी पर बात होगी। सूत्रों ने बताया, एक अन्य विपक्षी दल के नेता ने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया और कहा कि चीन की आक्रमकता समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है।

जल जीवन मिशन

जेई से प्रभावित पांच राज्यों के 61 जिलों को उच्च प्राथमिकता

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु ने की पहल, एक लाख गांवों के हर घर को होने लगी सुनिश्चित शुद्ध जलापूर्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मानसून की सक्रियता के साथ ही देश के पांच प्रमुख राज्यों में बढ़ते जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) के प्रकोप पर काबू पाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन राज्यों के चिह्नित 61 जिलों में शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पिछले 22 महीनों के भीतर इन जिलों के तकरीबन एक करोड़ परिवारों को नल से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। इन जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वच्छ जलापूर्ति कर जापानी बुखार नाम की इस बीमारी से बचाव के उपाय किए गए हैं।

एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित जिलों वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पानी का कनेक्शन दिया गया है। इन जिलों में पानी का कनेक्शन देने की दर 32 फीसद से अधिक रही है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में जलापूर्ति वाले नल कनेक्शन देने की दर 23.43 फीसद रही। इन पांचों राज्यों को 2021-22 के लिए जापानी बुखार के घटक के रूप में 463 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जापानी बुखार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। इसमें मौत तक हो जाती है। यह संक्रमण विशेष रूप से गरीब और आर्थिक पृष्ठभूमि के कुपोषित बच्चों को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नोडल मंत्रालय के साथ पांच केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से रोकथाम और नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए पांच राज्यों के 61 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है। इन जिलों में बीमारी पर काबू पाने के लिए जल जीवन मिशन सबसे अहम कार्यक्रम है। मिशन के आदर्श वाक्य 'कोई भी छूटे ना' के तहत देश के हर गांव के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। देश के 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अब तक 7.72 करोड़ परिवारों को पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार और पुडुचेरी के शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में जलापूर्ति नल से हो रही है। इस समय देश के 69 जिलों और लगभग एक लाख गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन पांच राज्यों में बिहार ने बीमारी से प्रभावित अपने चिह्नित 15 जिलों को प्राथमिकता देते हुए 85 फीसद से अधिक घरों में पानी का कनेक्शन दे दिया है। यहां के नालंदा में 96 फीसद, सारण और गोपालगंज में 94 फीसद, सिवान में 84 फीसद और पूर्वी चंपारण में 80 फीसद ग्रामीण घरों में कनेक्शन लगा दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सबसे अधिक जोर असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल पर रहा है। वहां के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने इसके लिए हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया है।

क्या है जापानी इंसेफेलाइटिस

जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) मर्ज गंदे पानी में पनपने वाले फ्लैवी वायरस के कारण होता। मच्छरों के काटने से यह वायरस मनुष्यों और पशुओं के शरीर में पहुंचता है। इससे पीड़ित मरीज के मस्तिष्क के आसपास की झिल्ली में सूजन आ जाती है। यह बीमारी जापान से फैलते हुए भारत पहुंची है। गंभीर रूप से पीड़ित होने पर मरीजों की मौत भी हो जाती है।


शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है प्राथमिकता। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कह के रहेंगे माधव जोशी

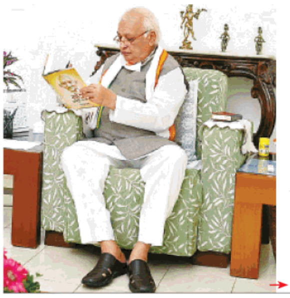


50 हजार रुपये का पांच याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है नैनीताल हाई कोर्ट ने चमोली जिले में ऋषिगंगा व तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के लिए वन और पर्यावरण मंजूरी रद करने व रैणी गांव का पुनर्वास करने की मांग करती जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 जुलाई, 2021

दहेज के खिलाफ केरल के राज्यपाल ने रखा उपवास

- विपक्षी कांग्रेस व भाजपा ने राज्यपाल का किया समर्थन
- महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य की वामपंथी सरकार को घेरा



पिछले दिनों दहेज हत्या के लगातार कई मामले सामने आने के बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बुधवार को तिरुअनंतपुरम स्थित राजभवन में एक दिवसीय उपवास के दौरान राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान। एएनआइ

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल में पिछले दिनों दहेज हत्या के लगातार कई मामले सामने आने के बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक पहल हुई है। राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने बुधवार को राजभवन में एक दिवसीय उपवास रखा। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है, जब राज्यपाल ने सामाजिक कल्याण के लिए उपवास रखा है।

विपक्षी कांग्रेस व भाजपा ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनजागरूकता के लिए राज्यपाल की तरफ से उठाए गए गांधीवादी कदम का समर्थन किया। साथ ही कहा कि राज्य की पिनराई विजयन की नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही है और इसी वजह से राज्यपाल को उपवास के लिए मजबूर होना पड़ा। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'राज्यपाल को बधाई जो केरल में महिला व लड़कियों की सुरक्षा के लिए उपवास रख रहे हैं।' उन्होंने राज्यपाल के कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि शायद यह देश के प्रशासनिक इतिहास का 'दुर्लभ प्रकरण' है। मुरलीधरन ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि राज्यपाल को महिला सुरक्षा के लिए उपवास क्यों रखना पड़ा।

केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरण ने दवा किया कि राज्य के लोगों की सुरक्षा में सरकार की विफलता के कारण ही राज्यपाल को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने उपवास को 'दुर्लभ घटना' बताते हुए कहा कि राज्यपाल ने 'उचित मुद्दे' को उठाया है। कन्नूर के सांसद ने कहा, 'केरल में अब यह स्थिति हो गई है कि राज्यपाल को विरोध के लिए गांधीवादी रास्ता अपनाना पड़ रहा है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है।'

इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए राज्यपाल खान ने राजभवन में सुबह आठ बजे उपवास शुरू किया और लोगों से दहेज प्रथा को समाप्त करने की अपील की। उपवास शाम छह बजे तक चला। उनके समर्थन में लोगों ने गांधी भवन में गांधी समर्थक निधि के तत्वावधान में उपवास किया। पिछले महीने खान ने महिलाओं से शादी के समय दहेज की मांग न करने और इस कुप्रथा के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की अपील की थी। उन्होंने यह अपील मेडिकल छात्रा विस्मया के घर जाने के बाद की थी, जो दहेज उत्पीड़न की शिकायत करने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में कोल्लम जिले में अपने पति के घर मृत पाई गई थी।

डंडे के बल पर नहीं हो सकता जनसंख्या नियंत्रण : कुशवाहा

जागरण संवाददाता, मधुबनी

जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण डंडे के बल पर नहीं हो सकता। पुलिस तंत्र के माध्यम से कानून का भय दिखाकर यह कभी सफल नहीं हो सकता। यह हर व्यक्ति से जुड़ा मसला है। लोगों को सजग और महिलाओं को शिक्षित कर ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वे बुधवार को जिला अतिथिगृह में मीडिया से मुखातिब थे। बता दें, बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि बच्चों के लालन-पालन के प्रति पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। वे जैसे-जैसे शिक्षित और प्रशिक्षित होंगी, जनसंख्या भी नियंत्रित होती जाएगी। शिक्षित होने पर महिलाओं में यह भाव पैदा होगा कि कम बच्चे रहने पर बेहतर तरीके से लालन-पालन हो सकेगा।

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले– बच्चा एक ही अच्छा

जासं, जयपुर : राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डा. रघु शर्मा ने कहा कि 'हम दो और हमारे दो' के दिन लद गए हैं। अब तो 'बच्चा एक ही अच्छा' का समय है। उन्होंने कहा कि अब परिवार में एक ही बच्चा अच्छा है, जिससे उसकी देखभाल सही तरह से की जा सके।

नसबंदी का विरोध न किया होता तो जनसंख्या नियंत्रित रहती : बघेल

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर केंद्र व भाजपा की राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली सदी के सातवें दशक में कांग्रेस शासन के दौरान विपक्षी दलों ने नसबंदी कार्यक्रम का कड़ा विरोध किया था। अगर वह कार्यक्रम जारी रहता तो आज जनसंख्या नियंत्रित रहती।

तीसरी संतान होने पर महिला सभासद की सदस्यता खत्म

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : तीसरी संतान को जन्म देने पर लक्सर नगर पालिका के वार्ड चार की सभासद नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद प्रशासन और शासन स्तर से कार्रवाई की गई।

हरिद्वार शहर के शिवपुरी निवासी पंकज बंसल ने 2020 में नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर मामले की शिकायत की थी। याचिका में बताया था कि नगर के वार्ड संख्या चार में नीता पांचाल 2018 में दूसरी बार सभासद निर्वाचित हुई थीं। निर्वाचन के बाद उन्होंने तीसरी संतान को जन्म दिया। नियमानुसार वह पद पर नहीं रह सकती हैं।

हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने एसडीएम और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) से जांच रिपोर्ट मांगी थी। जांच रिपोर्ट में तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने शासन को कार्रवाई की संस्तुति कर दी थी।

न्यूज गैलरी

अब बंगाल कांग्रेस में रार, महासचिव ने दिया इस्तीफा

कोलकाता: बंगाल कांग्रेस के महासचिव रोहन मित्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर मित्रा ने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि चापलूसों ने न केवल आपका पतन किया है, बल्कि यह बंगाल में पार्टी के पतन का भी कारण बना है। रोहन ने अधीर रंजन चौधरी की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ किया कि पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी है। हालांकि उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। (राब्यू)

श्रम कानून को लेकर केंद्र से टकराव की राह पर ममता

कोलकाता : कृषि कानूनों के बाद अब श्रम कानून को लेकर बंगाल की ममता सरकार केंद्र से टकराव की राह पर है। राज्य के अधिकांश श्रमिक संगठन केंद्र के श्रम कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। वाममोर्चा और कांग्रेस के श्रमिक संगठन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर चुके हैं। ममता उनसे सहमत हैं। तृणमूल कांग्रेस भी कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं है। सूबे में केंद्र के श्रम कानून को लागू न किया जाए, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) को छोड़कर आठ ट्रेड यूनियनों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि श्रम कानून के प्रविधानों में फेरबदल कर श्रमिकों के काम की सुरक्षा का उल्लंघन किया गया है। (राब्यू)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नंदीग्राम का संग्राम, सुवेंदु ने दायर की याचिका

ममता की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अधिकारी को जारी किया नोटिस

भाजपा नेता ने बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने की अपील की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट का संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर नंदीग्राम के चुनाव परिणाम को चुनौती देती ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की है। सुवेंदु ने अपील की है कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के अलावा देश के किसी भी दूसरे हाई कोर्ट में की जाए।

इस बीच, मामले में ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने ममता की याचिका को वैध करार देते हुए सुवेंदु अधिकारी समेत चुनाव आयोग व रिटर्निंग आफिसर को नोटिस जारी किया।

जस्टिस शंपा सरकार की एकल पीठ ने नंदीग्राम में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) समेत चुनाव से जुड़े सभी रिकार्ड व दस्तावेज, उपकरण, वीडियो रिकार्डिंग आदि को संरक्षित रखने का संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि रिकार्ड को तब तक संरक्षित रखा जाए, जब तक याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है।



सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

न्यायमूर्ति कौशिक चंद ने सुनवाई से खुद को कर लिया था अलग

इससे पहले ममता के मामले को अन्य पीठ में भेजने की अपील पर न्यायमूर्ति कौशिक चंद ने सुनवाई से सात जुलाई को खुद को अलग कर लिया था। न्यायमूर्ति चंद ने इस मामले से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

ममता ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का लगाया है आरोप

उल्लेखनीय है कि नंदीग्राम के चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता ने वोटों की फिर से गिनती की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बंगाल में प्रचंड जीत के बावजूद नंदीग्राम सीट पर ममता को भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से करीबी मुकाबले में 1,956 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी पर जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 123 के तहत चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं।

बाडीगार्ड की मौत की जांच करने सुवेंदु के घर पहुंची सीआइडी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी के बाडीगार्ड की तीन साल पहले मौत हो गई थी। उस मामले में अपराध अन्वेषण विभाग (सीआइडी) की टीम बुधवार को जांच के लिए सुवेंदु के घर पहुंची। जिस समय सीआइडी वहां पहुंची, तब सुवेंदु मौजूद नहीं थे। जांच टीम द्वारा घर के सामने बनी बैरक में छानबीन की गई। सुवेंदु अधिकारी के भाई और तृणमूल कांग्रेस सांसद दिव्येंदु अधिकारी से भी सीआइडी की टीम ने बातचीत की।

बता दें, कुछ ही दिन पहले बाडीगार्ड शुभाब्रत की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने फिर से जांच की मांग करते हुए भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 और 120 के तहत शिकायत दर्ज कराई तो जांच सीआइडी को सौंप दी गई।

यह है मामला : शुभाब्रत ने 13 अक्टूबर, 2018 को पूर्व मेदिनीपुर जिले में अपने किराये के घर पर कथित रूप से खुद को गोली मार ली थी। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में अगले दिन उनकी मौत हो गई थी।

सुवेंदु अधिकारी उस समय राज्य के परिवहन मंत्री थे। बताते चलें कि शुभाब्रत का एक करीबी तृणमूल का विधायक है। सुवेंदु अधिकारी ने पहले ही इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह केस राजनीति से प्रेरित है। केस का निपटारा हो चुका है, फिर से जांच करवा उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है।

अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचीं ममता, डेढ़ घंटे चली बैठक

- विधानसभा सत्र के बाद सीएम और राज्यपाल के बीच बैठक से कयासों का दौर
- राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव थम जाने की संभावना



कोलकाता स्थित राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करती बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एएनआइ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर जारी टकराव के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने राजभवन पहुंच गईं। राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक, ममता दोपहर करीब 3:30 बजे राज्य सचिवालय से सीधे राजभवन गईं। राज्यपाल ने गुलदस्ता भेंट कर ममता का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल की पत्नी व राज्य की प्रथम महिला सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं।

दोनों के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा सत्र के बाद सीएम और राज्यपाल के बीच यह बैठक राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि शायद राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव थम जाएगा।

बंगाल में विधानपरिषद के गठन पर चर्चा की संभावना : सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में विधानपरिषद गठन का विधेयक पारित किया है। दोनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होने के कयास हैं।

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के बाद हुई हिंसा के संदर्भ में भी राज्यपाल ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष चिंता जताई है। इसके अलावा मुकुल रॉय को विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में भी ममता और धनखड़ के बीच बात होने की चर्चा है।

बताते चलें कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव तब और बढ़ गया था, जब ममता ने बीते दिनों राज्यपाल को भ्रष्ट बताते हुए जैन हवाला मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि राज्यपाल ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।

द्रमुक नेता दयानिधि मारन के पायलट बने भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी

- दो घंटे पहले साथ बैठक करने वाले द्रमुक सांसद कैप्टन की ड्रेस में नहीं पहचान पाए भाजपा नेता को



राजीव प्रताप रूडी और दयानिधि मारन। फाइल

नई दिल्ली, जेएनएन : जिसके साथ आप काम करते हैं और समय बिताते हैं, उसे उसकी हरकतों से भी पहचान लेते हैं। लेकिन, जब वह अप्रत्याशित तरीके से आपके सामने आ जाए तो कई बार नजरें ही नहीं, ज्ञानेंद्रियां भी धोखा खा जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के साथ जो अपनी ही फ्लाइट में मौजूद भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को कैप्टन की पोशाक व मास्क लगाने के कारण नहीं पहचान पाए। दोनों नेता कुछ ही देर पहले एक बैठक में शामिल हुए थे।

द्रमुक नेता ने फ्लाइट के इस अनुभव को ट्विटर पर साझा किया। 'अविस्मरणीय फ्लाइट : 13 जुलाई, 2021' शीर्षक नोट में मारन ने लिखा, 'मैं संसद की प्राक्कलन समिति की बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली से चेन्नई के लिए इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुआ। पहली कतार में बैठा था। चालक दल ने एलान किया कि बोर्डिंग पूरी हो चुकी है। तभी कैप्टन की पोशाक में एक शख्स ने पूछा-तो, आप भी इस फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। चूंकि वह मास्क लगाए हुए थे तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन आवाज सुनी सी लगी। जवाब में मैंने अपना सिर हिलाया और आश्चर्य करने लगा कि वह कौन हो सकते हैं। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखें मुस्कुराहट का एहसास दे रही थीं। तब उन्होंने आश्चर्य से कहा- तो आप मुझे नहीं पहचानते! मुझे तब एहसास हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे साथी, वरिष्ठ सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं।'

दयानिधि रोचक अंदाज में लिखते हैं, 'सिर्फ दो घंटे पहले वह और मैं प्राक्कलन समिति की चर्चा में शामिल थे और अब मैं उन्हें नेता से कैप्टन की भूमिका में देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह सुखद आश्चर्य था। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह एहसास हुआ था कि मैंने नहीं पहचाना। मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मैं उस उड़ान में था जिसके कैप्टन मेरे अच्छे दोस्त और सहकर्मी हैं। जब मेरे पिताजी केंद्र में वाणिज्य मंत्री थे तब रूडी जी भी राज्यमंत्री थे।' उन्होंने लिखा, 'सच में यह फ्लाइट अविस्मरणीय है! ऐसा कब होता है जब संसद का कोई मौजूदा सदस्य किसी कामर्शियल फ्लाइट को उड़ाता है? हमें सुरक्षित तरीके से दिल्ली से चेन्नई पहुंचाने के लिए शुक्रिया कैप्टन राजीव प्रताप रूडी!'

रूडी बिहार की छपरा सीट से भाजपा सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। वह कामर्शियल पायलट हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं।

सिद्धू होंगे पंजाब कांग्रेस के नए 'सरदार'

- कांग्रेस हाईकमान ने लिया फैसला, जल्द हो सकता है एलान
- दो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाने की चर्चा

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए 'सरदार' होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए पार्टी हाईकमान उनका नाम लगभग फाइनल कर चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर एलान होना बाकी है, लेकिन सिद्धू कैंप की ओर से करीबियों को तैयारियां शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सिद्धू के नाम का एलान करने से पहले हाईकमान पार्टी में निचले स्तर तक की प्रतिक्रियाओं पर मंथन भी करना चाहता है। स्वयं सिद्धू पार्टी नेताओं से संपर्क कर उनका सहयोग मांग रहे हैं।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के साथ ही दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। इनमें एक अनुसूचित जाति से होगा और दूसरा हिंदुओं में सवर्ण जाति से होगा। हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुई बैठक के बाद ही इस फार्मूले पर मन बनाया है। कैप्टन का कहना था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर अगर जट्ट समुदाय को ही प्रतिनिधित्व दिया गया तो दूसरे वर्ग से छिटक सकते हैं।



नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल/इंटरनेट मीडिया

सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद हाईकमान ने सिद्धू को पंजाब की कमान सौंपने का मन बना लिया। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं कि दो-तीन दिन में नए प्रदेश अध्यक्ष का एलान हो जाएगा।

कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सेखड़ी का नाम आगे

कार्यकारी अध्यक्ष के लिए बटाला से पूर्व विधायक अश्वनी सेखड़ी का नाम सबसे आगे है। वह पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर अकाली दल जाने की तैयारी में थे लेकिन कैप्टन के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने फैसला बदल दिया था।

हाईकमान शुरू से चाहता था कि सिद्धू हों अध्यक्ष

कांग्रेस हाईकमान शुरू से ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश की कमान सौंपने का पक्षधर रहा है, लेकिन कैप्टन नहीं चाहते थे कि सिद्धू को यह जिम्मेदारी दी जाए। यह तर्क भी दिए गए कि सिद्धू के पास संगठन में काम करने कोई अनुभव नहीं है और अभी वह पार्टी में जूनियर हैं। इसके बावजूद सिद्धू ही हाईकमान की पहली पसंद रहे, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा हाथ रहा।

सही कह रहे आरएसएस प्रमुख, भारतीयों का डीएनए एक : इरफान

राज्य ब्यूरो, रांची : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान झारखंड के कांग्रेसियों को रास आ रहा है। हाल ही में मोहन भागवत ने एक समारोह में दौरान कहा था कि भारत में सभी का डीएनए एक है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक डा. इरफान अंसारी ने इसे आरएसएस प्रमुख का अबतक का सबसे बढ़िया बयान बताया है। अंसारी ने कहा, हम सभी एक हैं और आपस में नफरत पैदा करने और लड़ाई कराने वाली ताकतों को परास्त कर देंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ही हम भारतीयों के डीएनए में अंतर करते हैं। देश को सांप्रदायिक राजनीति से दूर रखना आवश्यक है। हमारा मिशन विकास पर केंद्रित होना चाहिए। युवाओं के रोजगार पर सरकार को फोकस करना चाहिए और आरएसएस प्रमुख को तमाम ज्वलंत मुद्दों पर न सिर्फ बोलना चाहिए। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश कच्छप भी आरएसएस प्रमुख की बातों को सौ प्रतिशत सही बताते हैं।

घेराबंदी

अमेठी के रास्ते स्मृति ईरानी की रायबरेली में दस्तक, जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बनीं अध्यक्ष

कांग्रेस के आंगन में जड़ें जमा रहीं 'तुलसी'

अजय सिंह, रायबरेली

कभी कांग्रेस का अभेद्य दुर्ग रही अमेठी फतह करने के बाद भाजपा की तुलसी (केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी) दबे पांव रायबरेली में जड़ें जमा रहीं। वह हर मोर्चे पर यहां कांग्रेस की घेराबंदी करने में जुटी हैं। वह एक बार फिर कांग्रेस और इसकी मुखिया सोनिया गांधी पर भारी पड़ीं। उन्हें जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) अध्यक्ष बना दिया गया।

कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में शुमार अमेठी में पहली बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कदम रखा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सफल हो पाएंगी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में वह पहली बार जनता के बीच गईं। नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। इसके बावजूद हार नहीं मानी। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के नाते योजनाओं को अमेठी तक पहुंचाती रहीं। नतीजतन 2019 के चुनाव में इसका असर पड़ा।

कांग्रेस के 'युवराज' को उन्हीं के गढ़ में चारों खाने चित कर दिया। इसके बाद उनका निशाना गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली है। वह गाहे-बगाहे अपने दौरे में इसका इजहार भी करती हैं। जिले की सलोन विधानसभा सीट उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आती है, इस नाते वे जनता के सुख-दुख में साथ खड़ी नजर आती हैं। अब अचानक दिशा की बैठक के लिए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंशा और स्पष्ट हो जाती है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को घेरने की तैयारी हो चुकी है। बहरहाल कांग्रेस प्रवक्ता विनय द्विवेदी का कहना है कि अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया जाना चाहिए। कारण वह रायबरेली सांसद हैं। ऐसा न कर ओछी राजनीति की जा रही है।

सोनिया गांधी का घटा कद : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कद उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में घटा दिया गया। दिशा में स्मृति ईरानी को अध्यक्ष, जबकि सोनिया गांधी को सह अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 2018 में हुई बैठक में सोनिया गांधी अध्यक्ष, जबकि तत्कालीन अमेठी सांसद रहे राहुल गांधी को सह अध्यक्ष बनाया गया था।



स्मृति ईरानी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेर रही हैं। फाइल

लोकसभा चुनाव के बाद हर बार दिशा के लिए अध्यक्ष व सह अध्यक्ष का मनोनयन ग्रामीण विकास मंत्रालय से होता है। बिना मनोनयन के जिले में दिशा का गठन नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार से मनोनयन का पत्र आ गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अध्यक्ष, जबकि सांसद सोनिया गांधी को सह अध्यक्ष बनाया गया है।

–प्रेमचंद्र पटेल, पीडी डीआरडीए

दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती कांग्रेस : पटोले

राज्य ब्यूरो, मुंबई



एमवीए गठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बयान

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस के साथ 2014 में धोखा हो चुका है। अब वह दुबारा धोखा नहीं खाना चाहती। इसलिए वह खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रही है। 2024 में वह पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी।

नाना पटोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। पहले उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस द्वारा अकेले लड़ने की बात कहकर सरकार में अपने दोनों सहयोगी दलों शिवसेना एवं राकांपा की नाराजगी मोल ले ली। पिछले शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री द्वारा खुद पर नजर रखने की बात कहकर इस नाराजगी को और बढ़ा दिया। बुधवार को उन्होंने 2014 के चुनावों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के दुबारा धोखा न खाने की बात कही है। उनका इशारा 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राकांपा द्वारा गठबंधन तोड़ दिए जाने की ओर है। दरअसल कांग्रेस उससे पहले 2004 और 2009 के विधानसभा चुनाव राकांपा के साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन 2014 में सीटों के समझौते पर बात न बनने के कारण अचानक गठबंधन टूट गया था। इसके कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। तब कांग्रेस 2009 की तुलना में 40 सीटें कम जीतकर 42 पर सिमट गई थी क्योंकि जिन सीटों पर पिछले एक दशक से राकांपा लड़ती आई थी, वहां उसका संगठन ही नहीं था।

नाना पटोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही पूरे राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभाएं कर रहे हैं। ऐसी ही एक सभा में शनिवार को उन्होंने कहा था कि राज्य में कांग्रेस पुनः खड़ी हो रही है। यह देखकर शिवसेना और राकांपा के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी है। इसलिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हम पर नजर रख रहे हैं। बाद में नाना ने स्पष्टीकरण दिया था कि सरकार चलाना और पार्टी चलाना, दोनों अलग-अलग काम हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए सभाएं कर रहे हैं। नाना ने यही बात बुधवार को भी दोहराई कि वह कांग्रेस को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि उसे दुबारा धोखा न खाना पड़े।

बता दें कि 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 42 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर थी, जबकि 2019 में वह 44 सीटों के साथ चौथे स्थान पर आ गई है। इन दिनों नाना पटोले द्वारा दिए जा रहे बयानों और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से शिवसेना और राकांपा तो परेशान है हीं, कांग्रेस का वह गुट भी असहज महसूस कर रहा है, जो शांति से महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में बने रहने के हिमायती है।

80 तक का रिवर्स आर्डर में पहाड़ा सुना रांची के विराज ने बनाया रिकार्ड। यह रिकार्ड 10 मिनट 16 सेकेंड बना। उपलब्धि हासिल करने वाला वह देश का दूसरा बच्चा है।

न्यूज गैलरी

चिटफंड घोटाले में सीबीआइ ने एक को किया गिरफ्तार

कोलकाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को कहा कि उसने कोलकाता स्थित चिटफंड कंपनी इनफिनिटी रियलकॉम लिमिटेड से जुड़ी अपनी जांच के सिलसिले में देवव्रत सिन्हा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीबीआइ के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने बंगाल में दो स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। (राब्यू)

कैद नेताओं के इशारों पर काम कर रहे आतंकी

कोलकाता : कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को पता चला है कि बांग्लादेश की विभिन्न जेलों में बंद आतंकी नेताओं के इशारे पर बंगाल में जेएमबी आतंकी अपना संजाल फैला रहे थे। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों जेएमबी आतंकियों की डायरी में जेएमबी नेता नाहिद तसनीम और जेएमबी व हूजी नेता अलअमीन के नंबर मिले हैं। ये आतंकी नेता बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं। (राब्यू)

नक्सल कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने किया आत्मसमर्पण

जगदलपुर : नक्सल कमांडर रावुलु श्रीनिवास उर्फ रमन्ना के बेटे रावुलु रंजीत उर्फ श्रीकांत ने बुधवार को तेलंगाना के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी के समक्ष हैदराबाद में आत्मसमर्पण कर दिया। रंजीत के आत्मसमर्पण से दण्डकारण्य में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। रंजीत का पिता रमन्ना नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। (नईदुनिया)

आइएसआइ के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण से 34 वर्षीय ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। वह कई महीनों से आइएसआइ को भारतीय सेना से जुड़े अति गोपनीय दस्तावेज भेज रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित हबीब खान राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। पिछले दो-तीन सालों से वह पोखरण में ठेके पर भारतीय सेना के लिए सब्जियां आपूर्ति कर रहा था। (जासं)

एक पोल्ट्री फार्म में होगी 240 महिलाओं की हिस्सेदारी

मैनपुरी : गांव-देहात की महिलाएं अब चौका-चूल्हा तक सीमित नहीं हैं। वह स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कुछ अलग राह बना रही हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र सिकंदरपुर सरैया के 20 समूहों की 240 सदस्य भी इन्हीं जैसी हैं। इन्होंने सामूहिक रूप से मुर्गी पालन की कमान संभाल आत्मनिर्भर बनने की ठानी है। इनका जुनून देख सरकार इनके गांव में ही विशाल पोल्ट्री फार्म तैयार करा रही है। उप्र कुक्कट पालन योजना के तहत ये प्रोजेक्ट सिकंदरपुर सरैया गांव में लगाया जा रहा है। (जासं)

पहली बार पाक सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा महिला कमांडर के हाथ में

जालंधर : मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी सोनाली मिश्रा जालंधर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पंजाब फ्रंटियर की नई आइजी होंगी। ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाली वह देश की पहली महिला अधिकारी होंगी। सोनाली मिश्रा वर्तमान में दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में 'जी शाखा' के रूप में जानी जाने वाली खुफिया शाखा का नेतृत्व कर रही हैं। वह बीएसएफ में ही कश्मीर घाटी में बतौर आइजी सेवाएं दे चुकी हैं। बीएसएफ वहां आपरेशनल कमांड के तहत पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (एलओसी) की रक्षा करती है। माना जा रहा है कि सोनाली का यह अनुभव पंजाब में सीमा पार से होने वाली हेरोइन की तस्करी व घुसपैठ रोकने में मदद करेगा। वह पाकिस्तान सीमा से होने वाली तस्करी और घुसपैठ से भलीभांति परिचित हैं। (जासं)

मोदी आज काशी को देंगे 1583 करोड़ की सौगात

दौरे के दौरान कोरोना से निबटने की तैयारियों पर चिकित्सकों से करेंगे बात

भारत-जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत लोकार्पित करेंगे 78 परियोजनाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी



वाराणसी में भारत-जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। इसे जापान सरकार के सहयोग से 186 करोड़ रुपये खर्च कर आकार दिया गया है। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आगमन पर पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। उत्तम राय चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। कोरोना संकट के कारण लंबे समय बाद वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री जापान और भारत की मित्रता के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 744.82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान समेत 206 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, पेयजल व सीवेज, ग्राम विकास की कई योजनाएं हैं।

प्रोटोकाल के मुताबिक प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पर लगभग साढ़े दस बजे उतरेंगे। फिर हेलीकाप्टर से बीएचयू हेलीपैड आने के बाद सीधे आइआइटी टेक्नो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 1582.93 करोड़ की परियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के तहत शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए सभा में पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री बीएचयू में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट से तैयार एमसीएच (मदर चाइल्ड हेल्थ) विंग जाएंगे और उद्घाटन संग अवलोकन करेंगे। यहां कोविड की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर बीएचयू समेत स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों से बात करेंगे। पीएम इससे पूर्व बनारस के डाक्टरों से दूसरी लहर के संबंध में वर्चुअल वार्ता व सराहना कर चुके हैं। एमसीएच विंग बीएचयू के चिकित्सा अधिकारियों व डीएम कौशल राज शर्मा की ओर से कोविड की तीसरी लहर से निबटने के लिए की गई तैयारियों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकाप्टर से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में उतरेंगे। सड़क मार्ग से दोपहर लगभग डेढ़ बजे सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। जापान की मदद से 186 करोड़ रुपये की लागत से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के साथ बनारस के 500 प्रबुद्धजन संग संवाद करेंगे। इस दौरान जापानी राजदूत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। जापानी प्रधानमंत्री का रिकार्डेड वीडियो संदेश भी सुनाया जाएगा। उद्घाटन के बाद पीएम संपूर्णानंद हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और दोपहर लगभग तीन बजे बाबतपुर स्थित लालबहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। संपूर्ण आयोजन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ होंगे।

- सड़क, पेयजल, सीवेज समेत ग्राम्य विकास की 206 परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास

स्कैन करें और पढ़ें 'पीएम मोदी के वाराणसी दौरे' से संबंधित सभी सामग्री।

मतांतरण का विरोध पर हत्या चाहते थे आरोपित

जागरण संवाददाता, बदायूं :

- दिनेश बनकर दानिश ने बनाए थे प्रेम संबंध, निकाह के बाद बना लिया था बंधक
- पिता व भाई भी करता था शारीरिक शोषण, दो आरोपित गिरफ्त से दूर

बुलंदशहर के अहार क्षेत्र में रहने वाली युवती से पहचान बदलकर प्रेम संबंध, फिर जबरन मतांतरण का आरोपित दानिश बेहद खतरनाक इरादे रखता था। आरोप है कि मतांतरण का विरोध करने पर दानिश व उसके स्वजन युवती की हत्या करने की योजना बना रहे थे। इससे पहले वह किसी तरह वहां से भाग निकली। मंगलवार को दानिश व उसके पिता अहमद मियां को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी दोनों आरोपित बुधवार को भी पकड़ में नहीं आए।

बदायूं निवासी दानिश दिल्ली में नौकरी करता था। वहीं बुलंदशहर निवासी युवती रहती थी। एक साल पहले दानिश ने अपना नाम दिनेश बताकर उससे दोस्ती की। इसके बाद शादी का नाटक किया। कुछ दिन युवती को दिल्ली में ही रखा। पिछले महीने उसे लेकर अपने गांव गौरामई आया, तब युवती को पता चला कि वह दिनेश नहीं, दानिश है। विरोध किया तो उसे बंधक बना लिया। जबरन मतांतरण कर निकाह कर लिया। आरोप है कि दानिश, उसके पिता अहमद मियां, भाई चाहत मियां, मुजरिया निवासी रिश्तेदार आमिर ने मानसिक व शारीरिक शोषण किया। मुकदमे में इसका उल्लेख किया गया। पुलिस का कहना है मतांतरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। यदि उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया तो धाराएं बढ़ा दी जाएंगी।

12 जून को बचकर भागी थी पीड़िता: युवती को अपने साथ हुए फरेब की जानकारी मिली तो विरोध जताने लगी थी। आरोप है कि वह कानूनी कार्रवाई न कर दे, इसलिए उसे बंधक बनाकर रखा जाता था। किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। उसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, इसकी भनक लगने पर 12 जून को वहां से भाग निकली थी। वहां से खुर्जा क्षेत्र में रहने वाले बहनोई के घर पहुंची। आरोपितों की दहशत के कारण कई दिन पीड़ित परिवार थाने नहीं पहुंचा। मंगलवार को चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को दानिश के भाई चाहत, आमिर की तलाश में दबिश होती रही मगर दोनों हाथ नहीं आए।

मनरेगा में और काम की दरकार, सौ दिन पूरा करने वाले दो लाख

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली।

गांव में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा का महत्व अब और बढ़ गया है। कोविड-19 से प्रभावित शहरी मजदूरों के गांव लौटने से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पर बोझ बढ़ गया है। सालभर में सौ दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना में तीन-चार महीनों के भीतर ही सवा दो लाख से अधिक मजदूरों ने अपना सौ दिनों के काम का कोटा पूरा कर लिया है। इसके बाद उन्हें अब और काम की जरूरत होगी, जिसके लिए अधिनियम में प्रविधान नहीं है। हालांकि इसके लिए सरकार अतिरिक्त प्रविधान कर सकती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान भी कोविड-19 का प्रकोप था, जिससे पलायन कर गांव पहुंचे मजदूरों ने मनरेगा में रिकार्डतोड़ काम किया। उस दौरान कुल 72 लाख से अधिक मजदूरों को 100 दिनों का काम मिला था। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में मनरेगा में काम मांगने और करने वाले मजदूरों की संख्या पिछले साल की तिमाही के मुकाबले बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि रोजगार की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। पिछले साल ही पलायन कर गांव पहुंचे श्रमिकों के लौटने की रफ्तार बहुत धीमी है।

अतिरिक्त कार्य दिवस बढ़ा सकती है सरकार

इसके बावजूद मनरेगा के आंकड़ें कुछ और बयां कर रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह तक मनरेगा में 100 दिनों का काम करने वालों की संख्या सवा दो लाख पहुंच गई है, जिन्हें अब आगे और काम देना संभव नहीं होगा। सूखा और बाढ़ जैसी दैवीय आपदाओं के दौरान कई बार 50 दिनों के अतिरिक्त कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। सूत्रों की मानें तो सरकार मनरेगा में अतिरिक्त कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा सकती है।

हिमाचल में नाले में बह गए पंजाबी सूफी गायक मनमीत, शव मिला

जासं, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के करेरी क्षेत्र में नाले में बहने से पंजाबी सूफी गायक 30 वर्षीय मनमीत सिंह की मौत हो गई है। पुलिस ने उनका शव बरामद कर लिया है।

मनमीत सिंह दोस्तों के साथ धर्मशाला घूमने आए थे और यहां के बाद वह करेरी झील की ओर चले गए थे। रविवार को वह दोस्तों के साथ करेरी क्षेत्र में ही रुके थे और सोमवार सुबह लौटते समय नाला पार करते समय पानी में बह गए।

इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया था। जब नाले में पानी का बहाव कम हुआ तो राहत व बचाव दल ने उनका शव बरामद किया। बचाव दल के सदस्य शव जोनल अस्पताल धर्मशाला ले आए हैं। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन ने इस मामले की पुष्टि की है। मनमीत सिंह सिंगिंग ग्रुप सेन ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे और देश व विदेश में शो करते थे। मनमीत सिंह की मौत से उनके चाहने वाले काफी आहत हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को हुई मूसलधार बारिश से कांगड़ा जिले में नुकसान हुआ था।

नए भारत का नया रेलवे स्टेशन

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है। गांधीनगर कैपिटल पहला स्टेशन है, जिसके ऊपर फाइव स्टार होटल निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कई मायने में अनूठा है। पीएम मोदी 16 जुलाई को इस स्टेशन के अलावा वडनगर स्टेशन व छह अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आइए जानते हैं गांधीनगर कैपिटल स्टेशन की विशेषताओं के बारे में...

- रेन वाटर हार्वेस्टिंग व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं
- 'रेलोपोलिस' के नाम से जाना जाएगा इन हब को, जो कारोबारी अवसर व निवेश को आकर्षित करने में मददगार होंगे
- एसोसिएशन आफ चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) ने प्रदान किया है ग्रीन सर्टिफिकेट



गांधीनगर, गुजरात कैपिटल रेलवे स्टेशन तथा उसके ऊपर बना देश का पहला पांच सितारा होटल। सौ. पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद

24 घंटे सातों दिन काम करने वाले ट्रांसपोर्ट व बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जाएगा स्टेशन को

318 कमरों का फाइव स्टार होटल बनाया गया है स्टेशन के ऊपर

50 स्तंभों (ढाई गुणा ढाई मीटर) पर हुआ है होटल का निर्माण

22 मीटर ऊपर शुरू हो जाता है होटल रेलवे स्टेशन से

7,400 वर्गमीटर में बने होटल पर 700 करोड़ रुपये हुए हैं खर्च, निजी कंपनी करेगी संचालन

1,500 यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा स्टेशन पर, 2,200 तक बढ़ाई जा सकती है इसकी क्षमता

- दोनों तरफ अंडरपास बनाए गए हैं होटल तक पहुंचने के लिए

2016 में की गई थी परियोजना की परिकल्पना, 2017 में शुरू हुआ था काम

100 फीसद अनुकूल होगा रेलवे स्टेशन दिव्यांगों के लिए

105 मीटर की लोहे की मेहराब लगाई गई हैं रेलवे स्टेशन की दोनों तरफ, जिनमें कहीं पर जोड़ नहीं है

1,100 मीटर की खुली जगह व एक वातानुकूलित हाल उपलब्ध होगा सामाजिक व पारिवारिक समारोह के लिए

93 करोड़ रुपये स्टेशन के नवनिर्माण पर किए गए हैं खर्च

03 प्लेटफार्म, दो एस्कैलेटर्स, तीन एलिवेटर व दो पदयात्री सबवे का निर्माण किया गया है स्टेशन पर

08 आर्ट गैलरी हैं, जिनमें गुजरात के ऐतिहासिक स्थलों एवं लोककला का प्रदर्शन किया गया है

01 विशाल सर्वधर्म प्रार्थना खंड भी बनाया गया है स्टेशन पर

07 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं गांधीनगर स्टेशन से, जिनमें हाल में शुरू की गई गांधीनगर-वाराणसी एक्सप्रेस व अहमदाबाद-वनेडा वाया वडनगर मेमू ट्रेन भी

- बेबी फीडिंग रूम, आडियो-वीडियो एलईडी स्क्रीन व अत्याधुनिक एसी वेटिंग रूम होंगे स्टेशन के खास आकर्षण

यात्रियों की संतुष्टि के लिए रेलवे स्टेशनों को हवाईअड्डे की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हमने स्टेशन पर उन सभी सुविधाओं के विकास की कोशिश की है, जिससे यात्रियों को संतुष्टि मिले। इसके जरिये हम राजस्व के नए स्रोत भी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह नए भारत का नया स्टेशन है।
-सुनीत शर्मा, चेयरमैन (रेलवे बोर्ड)

महात्मा मंदिर के ठीक सामने निर्मित रेलवे स्टेशन व पांच सितारा होटल का फायदा वहां होने वाले आयोजनों के प्रतिभागियों को मिलेगा। महात्मा मंदिर में आयोजित सेमिनार, कांफ्रेंस व अंतरराष्ट्रीय स्तर की बिजनेस मीटिंग में शामिल होने वाले उद्यमियों, विक्रेता व खरीदारों को इससे बड़ी सुविधा होगी।
-पीएम चौधरी, संयुक्त प्रबंध निदेशक (गरुड़)

देश में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर होटल का निर्माण हुआ है। यह गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (गरुड़) तथा भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम है। इसमें गरुड़ की हिस्सेदारी 74 फीसद है।
-संजीव कुमार लोहिया, प्रबंध निदेशक (इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन)

इनपुट : अहमदाबाद से शत्रुघ्न शर्मा व प्रेट्र

तीन महिलाओं के जिम्मे था मानव बम के लिए जिहादी व जैकेट का इंतजाम करना

जागरण संवाददाता, कानपुर

लखनऊ में एटीएस के हत्थे चढ़े अलकायदा आतंकवादियों से संपर्क वाली जिन तीन महिलाओं का नाम सामने आया है, वह कानपुर के पनकी के गंगागंज गांव में किराये के मकान में रहती थीं। एटीएस सूत्रों का दावा है कि इन महिलाओं का काम मानव बम के लिए प्रयोग होने वाले जिहादी का चयन करना और उस जैकेट का इंतजाम करना था, जिसे मानव बम बनने वाला व्यक्ति पहनता है। उनकी तलाश में एटीएस की टीम बुधवार को भी गांव पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने तीनों संदिग्ध महिलाओं की एक सप्ताह पूर्व तक मौजूदगी की पुष्टि की है। हालांकि, अब तक यह पता नहीं चल सका है कि वह किसके घर में रहती थीं। एटीएस की अब तक की जांच में सामने आया है कि आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन कानपुर की तीन महिलाओं के संपर्क में थे। सर्विलांस के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों ने इन महिलाओं से दोनों आतंकियों की बातचीत की रिकार्डिंग भी सुनी है। उसे सुबूत के तौर पर सुरक्षित भी किया गया है। आतंकियों की गिरफ्तारी होते ही तीनों महिलाएं गायब बताई जा रही थीं। बुधवार को सामने आया कि महिलाएं पनकी के गंगागंज गांव की घनी स्लम बस्ती में किराये का कमरा लेकर रहती थीं।

रोहिंग्या या बांग्लादेशी होने का अनुमान

दुकानदार ने एटीएस को बताया है कि तीनों महिलाएं सामान लेने उसकी दुकान पर कई बार आईं। वह स्थानीय नहीं थीं, इसका पता उनकी बोली से लगता था। वह अजीब सी भाषा बोलती थीं। महिलाओं के रोहिंग्या या बांग्लादेशी होने का अनुमान है।

लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी हुरैरा सहित तीन ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : सुरक्षाबल के जवानों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आठ घंटे चली भीषण मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी एजाज उर्फ अबु हुरैरा को उसके दो स्थानीय साथियों संग मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों द्वारा दागे गए ग्रेनेड से हुए धमाके में लगी आग से दो मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। मारे गए आतंकियों से दो असाल्ट राइफल, एक पिस्तौल भी मिली है। इस वर्ष अब तक कश्मीर में सुरक्षाबल ने विभिन्न मुठभेड़ में लगभग 77 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें पांच विदेशी आतंकी हैं। जानकारी के अनुसार, पुलवामा के बनूरा इलाके में मंगलवार रात स्वचालित हथियारों से लैस तीन आतंकी अपने संपर्क सूत्र से मिलने आए थे। स्थानीय लोगों ने की सूचना पर सेना और सीआरपीएफ के जवानों संग पुलिस ने आतंकियों को अभियान चलाकर पकड़ा।

ठेके पर मकान बनाने का काम करता है मुस्तकीम

प्रथम पृष्ठ से आगे

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि लखनऊ के वजीरगंज थानाक्षेत्र स्थित बांसमंडी निवासी शकील, सीतापुर रोड स्थित तकिया तारनशाह मदेयगंज निवासी मुहम्मद मुस्तकीम व न्यू हैदरगंज कैंपवल रोड निवासी मुहम्मद मुईद को गिरफ्तार किया गया है। मूलरूप से मुजफ्फरनगर के ग्राम मांडी का निवासी मुस्तकीम ठेके पर मकान बनाने का काम करता है और करीब दस वर्षों से लखनऊ में रह रहा है। मुस्तकीम पहले मसीरुद्दीन के संपर्क में आया था और फिर उसका परिचय मिनहाज से हुआ था। मुस्तकीम ने करीब चार माह पहले मसीरुद्दीन के भाई का मकान बनाने का ठेका भी लिया था। इसी बीच मिनहाज ने मुस्तकीम से एक असलहा खरीदने की बात की थी। मुस्तकीम ने निर्माण सामग्री की सप्लाई करने वाले मुईद के जरिये मिनहाज को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। शकील बांसमंडी में सैफ अहमद के मकान में रह रहा था। उसका घर लखनऊ के वजीरगंज थानाक्षेत्र में ही जनता नगरी, जगत नारायण रोड पर है।

एडीजी के अनुसार मिनहाज व मसीरुद्दीन के इरादों का उनके तीनों सहयोगियों को पता था। तीनों अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल से भी जुड़ चुके थे। एटीएस तीनों से और जानकारियां हासिल करने का प्रयास कर रही है। तीनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकी मिनहाज अहमद व मसीरुद्दीन रविवार को लखनऊ में पकड़े गए थे। दोनों 15 अगस्त से पहले आतंकी घटना करने की फिराक में थे।

शकील एटीएस थाने में दर्ज मुकदमे का नामजद आरोपी है। मिनहाज को असलहा दिलाने में उसकी सबसे सक्रिय भूमिका थी। उस पर अन्य आरोप भी हैं। मुस्तकीम को पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी और वह मिनहाज व मसीरुद्दीन के लगातार संपर्क में था। मुईद की अन्य आरोपों में भी संलिप्तता सामने आई है।
-प्रशांत कुमार, एडीजी कानून-व्यवस्था

रक्षा तकनीक

जैसी जरूरत वैसे ड्रोन बनेंगे आइआइटी में

देश को ड्रोन तकनीक में ताकतवर बनाने की तैयारी, गृह मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव, परिसर में बनेगा भवन

शशांक शेखर भारद्वाज, कानपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर देश को मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) की तकनीक में मजबूत करने की तैयारी में है। यहां सेंटर फार ड्रोन खोला जाएगा, संस्थान के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। सेंटर को मौजूदा वर्ष के अंत तक तैयार करने की योजना है। यहां प्रशासन, पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल (एनडीआरएफ) और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही निजी कंपनियों की जरूरत के मुताबिक छोटे से लेकर बड़े ड्रोन तैयार किए जाएंगे। इससे निगेहबानी, सुरक्षा और आम नागरिकों की जरूरत, सर्च अभियान, कृषि विभाग, प्राकृतिक आपदा राहत या आपातकालीन स्थिति में मदद पहुंचाई जा सकेगी। मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए आइआइटी ड्रोन निर्माण में औद्योगिक संस्थानों और स्टार्टअप को साथ लेगा। वर्तमान माहौल और जरूरत को देखते हुए इसे जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।



अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन। फाइल फोटो

ड्रोन तकनीक का पूरा सेटअप बनेगा: अभी ड्रोन निर्माण के जरूरी उपकरणों के लिए अमेरिका, आस्ट्रेलिया समेत अन्य यूरोपीय देशों की ओर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें कई तरह के सेंसर, बैटरी, कैमरे और इंजन के कुछ कलपुर्जे शामिल हैं। यूरोपीय देशों से महंगे उपकरणों की वजह से चीन, ताइवान, इजरायल से उपकरण लेना मजबूरी है।

यूएवी की अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब बनेगी

ड्रोन, एयरो प्लेन ड्रोन समेत अन्य तरह के यूएवी के निर्माण और उसकी जांच के लिए अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। ड्रोन के लिए फ्लाइंग जोन निर्धारित होगा। इसके लिए संस्थान में जगह चिह्नित हो गई है।

मेधावियों को भी मिलेगा मौका

स्कूल, कालेज समेत अन्य तकनीकी संस्थानों के छात्रों को भी ड्रोन तकनीक की जानकारी मिल सकेगी। वह अपना ड्रोन या फिर उसके आइडिया को संस्थान के अधिकारियों से साझा कर सकेंगे, जिससे उनकी मेधा को निखार आएगा। छात्र-छात्राएं स्टार्टअप भी कर सकेंगे।

सेंटर फार ड्रोन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है। इसमें अत्याधुनिक ड्रोन तैयार करने के साथ ही इसकी तकनीक विकसित की जा सकेगी। कंपनियों को भी जोड़ेंगे।
- प्रो. अभय करंदीकर, निदेशक, आइआइटी कानपुर

प्रदूषण न रोक पाने पर अधिकारियों से वसूला जाएगा भारी जुर्माना

आशीष सिंह, धनबाद

देशभर के चुने शहरों में प्रदूषण का स्तर कम करने के उद्देश्य से शुरू किए गए राष्ट्रीय शुद्ध वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत अब प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार कंपनियों के अधिकारियों से भारी- भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी की गई है। यह रकम प्रतिदिन 30 से 60 हजार रुपये तक हो सकती है। ग्रीन पीस इंडिया के सर्वेक्षण में देश के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए गए धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) समेत कई कंपनियों को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में नोटिस भेजा है। हाल ही में बोर्ड ने बीसीसीएल के भौंरा एरिया पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद से अगले दो वर्ष में वायु प्रदूषण 20 से 30 फीसद कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कोयला कंपनियों के अलावा धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-भारतीय खनन स्कूल (आइआइटी-आइएसएम) और सिंफर को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम को भी 52 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च करने हैं। अगर ये संस्थान प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहते हैं तो इन संस्थानों के अधिकारियों से भी जुर्माना वसूलने की व्यवस्था बनाई गई है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है।

बढ़ते प्रदूषण से लोग कैंसर, बीपी, किडनी संबंधित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अगले दो वर्ष में 30 फीसद तक प्रदूषण कम करना है। जो अधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे उनपर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
- राजीव शर्मा, सदस्य झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

धारा 66ए के तहत केस दर्ज नहीं करें

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने बुधवार को राज्यों से पुलिस को यह निर्देश देने को कहा कि वे सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून, 2000 की रद की जा चुकी धारा 66ए के तहत मामला दर्ज नहीं करें।

उल्लेखनीय है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आनलाइन 'अपमानजनक' टिप्पणी करने को अपराध की श्रेणी में डालने वाली विवादित धारा 66ए को खत्म कर दिया था। इस धारा के तहत तीन साल कैद की सजा का प्रावधान था। शीर्ष न्यायालय ने यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थकों के लंबे समय तक चलाए गए अभियान के बाद दिया था। हाल में शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि उसे इस बात की हैरानी है कि उक्त धारा को निष्प्रभावी करने के फैसले को अब तक भी लागू नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आइटी कानून की हटा दी गई धारा 66ए के तहत मामले पंजीकृत नहीं करें।

कोरोना संक्रमण को सामान्य फ्लू समझने में समझदारी नहीं

देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भविष्य में इसके स्वरूप को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में कहा था



कि समय के साथ कोरोना सामान्य फ्लू जैसा हो जाएगा। इसी को आधार मानते हुए आस्ट्रेलिया की सरकार ने चार चरणों की योजना भी तैयार की है। कोरोना को फ्लू समझने वालों की कमी नहीं है। कई लोगों का तर्क है कि बड़ी आबादी को टीका लगने के बाद यह महामारी फ्लू जैसी ही बनकर रह जाएगी, जिसमें कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेगा और लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं रह जाएगी। महामारी विज्ञानी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो हाइड इस सोच को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसी सोच को समझदारी नहीं कह सकते हैं। इस महामारी से लड़ाई केवल लक्षणों के सामान्य होने तक सीमित नहीं है। इसके और भी दुष्प्रभावों को समझना होगा।



जड़ से हो खत्म

जो हाइड कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के लक्षण गंभीर नहीं होने पर भी शरीर पर इसके बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कोरोना की चपेट में आ चुके युवाओं में भी बाद में कई दिक्कतें देखी गई हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि इस महामारी को पूरी तरह मिटाने का अभियान चलाया जाए।

बहुत से आंकड़े भरमाते हैं

कई लोगों को लगता है कि कोरोना का खतरा सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही है। कुछ आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। ब्रिटेन में दूसरी लहर में संक्रमित होने के बाद करीब एक फीसद बच्चों और दो से तीन फीसद युवाओं को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं 60



साल से ज्यादा उम्र के 10 फीसद से ज्यादा लोग भर्ती हुए। संक्रमण से जान जाने का खतरा भी ऐसा ही है। 20 हजार में किसी एक बच्चे की जान जाने का खतरा रहता है। वहीं 60 साल से ऊपर वालों में हर 100 में एक से ज्यादा की जान जाती है।

सब कुछ और भी है

भर्ती होने और जान जाने के आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहे। इनसे आगे भी एक सच है। ब्रिटेन में पहली लहर में अस्पताल में भर्ती हुए लोगों पर एक अध्ययन से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं।

- संक्रमित नहीं हुए लोगों की तुलना में संक्रमितों के दोबारा किसी कारण अस्पताल जाने की आशंका चार गुना रहती है
- चार से पांच महीने के भीतर किसी स्वास्थ्य संबंधी कारण से जान जाने का खतरा आठ गुना रहता है
- ऐसे लोगों में डायबिटीज, दिल और किडनी की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है
- सामान्य फ्लू के बाद भी कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अक्सर ऐसी परेशानियां देखी गईं
- अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले संक्रमितों में भी ऐसी कई दिक्कतें होने की आशंका बढ़ जाती है
- सिडनी में पाया गया था कि कम गंभीर लक्षण वालों में भी करीब दो महीने तक थकान और सांस उखड़ने जैसे कुछ लक्षण बने रहते हैं

लांग कोविड के खतरे से बचना जरूरी

ठीक होने के बाद भी लक्षण बने रहने को विज्ञानियों ने लांग कोविड नाम दिया है। इससे जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अध्ययन के मुताबिक, सात में एक व्यक्ति में कम से 12 हफ्ते तक कोरोना के लक्षण बने रहते हैं। ब्रिटेन में करीब 10 लाख लोग लांग कोविड से जूझ रहे हैं।

18% लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है

66% लोगों को दैनिक गतिविधियों को अंजाम देने में हो रही मुश्किल

8% बच्चों के भी लांग कोविड का शिकार होने की आशंका

(इनपुट : प्रेट्र)

कोरोना से होने वाली मौतों को दर्ज करने की प्रणाली मजबूत

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) के आंकड़ों के आधार पर कोरोना महामारी से ज्यादा संख्या में मौत का दावा करने वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गलत बताया है। मंत्रालय ने इन खबरों को महज अनुमान और अटकलें करार दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट में गलत निष्कर्ष निकालने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) और एचएमआइएस के आंकड़ों के बीच तुलना की गई है। इस तरह की रिपोर्ट बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं। एचएमआइएस में मौत की संख्या की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंत्रालय ने एक बयान में उल्लेख किया है कि मीडिया रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि 'अन्य सूचना के अभाव में इन मौतों को कोरोना से मौत माना जाना चाहिए।'

बयान में कहा गया है कि खुद मीडिया रिपोर्ट में ही कहा गया है कि 2.5 लाख से ज्यादा मौतों के कारणों का पता नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि बिना किसी ठोस आधार के और सिर्फ अनुमानों के आधार पर किसी भी मौत को कोरोना से मौत बता देना गलत है। बयान में कहा गया है कि कोरोना डाटा प्रबंधन के प्रति केंद्र का दृष्टिकोण पारदर्शी रहा है और कोरोना से होने वाली सभी मौतों को रिकार्ड करने की एक मजबूत प्रणाली पहले से ही मौजूद है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट करते रहने का अधिकार दिया गया है।

उप्र में कांवड़ यात्रा की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

निगरानी ▶ केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने संबंधी खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर केंद्र और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट 16 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक और उत्तर प्रदेश में शर्तों के साथ इसकी इजाजत संबंधी मीडिया में आई खबर को परेशान करने वाली बताया। कोर्ट ने कहा कि लोग पूरी तरह भ्रमित हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोर्ट ने कहा इसी खबर के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने की एक और खबर छपी है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें इसे रोकना होगा। इसमें जरा भी ढिलाई नहीं दी जा सकती।

पीठ ने कहा कि एक ही समय में भिन्न भिन्न राजनीतिक बयानों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार के संबंधित सचिव इस पर जवाब दें। कोर्ट ने कहा कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत 25 जुलाई से होने वाली है इसे देखते हुए मामले पर जल्द सुनवाई की जाएगी।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के संबंधित सचिव, और उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव एवं उत्तराखंड के प्रधान सचिव को शुक्रवार सुबह तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में 16 जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि कोर्ट के आदेश की प्रति सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल बी.वी. बलराम दास, उत्तर प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल प्रदीप मिश्र और उत्तराखंड के स्टैंडिंग काउंसिल अभिषेक अत्री को तत्काल दें। साथ ही आदेश की प्रति तत्काल भारत के प्रधान न्यायाधीश को भी भेजने का निर्देश दिया।

हर साल सावन में होती है यह धार्मिक यात्रा: प्रत्येक वर्ष सावन में कांवड़ यात्रा होती है जिसमें कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी है।

कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में नहीं देंगे घुसने

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

- 24 जुलाई से प्रदेश की हर सीमा पर सख्ती शुरू कर दी जाएगी
- नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के वाहन होंगे सीज

कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर प्रतिबंधित किए गए कांवड़ मेले में यात्रियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी सैंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने बुधवार को जनपद के सभी सीओ और थाना-कोतवाली प्रभारियों के साथ बैठक कर यात्रियों को रोकने की फुल प्रूफ रणनीति बनाई। तय हुआ है कि रोक के बावजूद गांव-देहात के रास्तों से हरिद्वार आने वाले यात्रियों के वाहन सीज कर मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हरिद्वार की सीमाएं भी सील की जाएंगी। वहीं, डीजीपी ने कहा कि 24 जुलाई से सीमा पर सख्ती की जाएगी।

एसएसपी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर से आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने कांवड़ मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है। यात्रियों को रोकने के लिए प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बार्डर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नियुक्त करेंगे। रोक के बावजूद हरिद्वार आने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के वाहनों को सीज किया जाएगा।

बुकिंग न लें ट्रैवल्स एजेंसियां: सीओ: कांवड़ मेला प्रतिबंधित होने के चलते सीओ यातायात विजेंद्र डोभाल ने बुधवार को यातायात पुलिस लाइन कमल दास कुटिया में टूर एंड ट्रैवल्स व बस यूनियन हरिद्वार के ऑपरेटरों की बैठक ली।

उप्र समेत अन्य राज्यों से चर्चा कर रही सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादूनः कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित की है। अपने इस फैसले के संबंध में सरकार उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से निरंतर वार्ता कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कोरोना से जनसामान्य को बचाना है।

400 से ज्यादा पर्यटक वापस लौटाए

जागरण संवाददाता, नई टिहरी

बिना कोविड जांच के जिले में आने वाले पर्यटकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कैम्पटी में दूसरे राज्यों से आए 93 वाहनों में सवार लगभग 400 से ज्यादा पर्यटकों को पुलिस ने बैरंग लौटा दिया।

विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक टिहरी जिले के कैम्पटीफाल और धनोल्टी आदि क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। लेकिन अधिकतर पर्यटक बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के ही जिले में खुलेआम घूम रहे हैं। बुधवार को कैम्पटी पुलिस ने 93 वाहनों में सवार लगभग 400 पर्यटकों को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया और वापस भेज दिया। बीते मंगलवार को भी पुलिस ने कई पर्यटकों को वापस भेजा था। कैम्पटी में बिना मास्क लगाए 40 पर्यटकों का चालान भी किया गया। कैम्पटी थानाध्यक्ष नवीन चंद ने बताया कि बड़ी संख्या में अभी भी पर्यटक बिना कोविड रिपोर्ट के ही घूमने आ रहे हैं। ऐसे पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। कैम्पटीफाल में भी एक बार में पचास से ज्यादा पर्यटकों को नहाने की अनुमति दी गई है।

केंद्र सरकार ने कहा-भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाएं राज्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और हिल स्टेशनों एवं बाजारों में बेपरवाह उमड़ती भीड़ पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाने और कोरोना प्रोटोकाल को लागू कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक वाहनों में कोरोना से बचाव के आचरण का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भल्ला ने स्पष्ट कहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए लोग कोरोना से बचाव के नियमों का जरूर पालन करें।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि संक्रमण के मामलों में कमी और सक्रिय मामलों में गिरावट के बाद विभिन्नि राज्यों में धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को खोला जा रहा है। ऐसा करते वक्त विशेष सावधानी बरते जाने की जरूरत है।

दोबारा प्रतिबंध की चेतावनी

भल्ला ने कहा कि किसी भी संस्थान, परिसर, बाजार या इस तरह के स्थलों पर कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन होता है तो वहां दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित धाराओं में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

लापरवाही के नतीजे सामने आए

भल्ला ने कहा है कि हिल स्टेशनों और बाजारों में बेपरवाह घूमती भीड़ और कोरोना प्रोटोकाल के उल्लंघन के नतीजे सामने आने लगे हैं। कई राज्यों में आर-फैक्टर बढ़ा है जो चिंता का कारण है। आर-फैक्टर यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर आर-फैक्टर एक से कम है, लेकिन पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में यह एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा आर-फैक्टर का मतलब है कि संक्रमण बढ़ रहा है।

हाटस्पाट पर नजर रखें राज्य :

भल्ला ने कहा है कि दुकानों, माल, बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक पार्क, जिम, बैंक्वेट हाल जैसे हाटस्पाट माने जाने वाले स्थलों पर कड़ी नजर रखी जाए। ऐसे स्थलों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग से होंगी दिव्य आरती के दर्शन

संवाद सहयोगी, कटड़ा : देशभर से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। एक माह के भीतर मां के भव्य में सुबह-शाम होने वाली दिव्य आरती का सीधा प्रसारण श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर देख सकेंगे। इसके लिए यात्रा मार्ग पर प्रमुख स्थानों पर एलईडी लगाने का काम जोरशोर से जारी है। एलईडी स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को हर पल मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के दर्शन भी होते रहेंगे, साथ ही यात्रा संबंधी सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध होगी।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से पांच बाई सात फीट की विशाल एलईडी स्क्रीन मां वैष्णो देवी के प्रवेशद्वार दर्शनी ड्योढ़ी, नए ताराकोट मार्ग के प्रवेशद्वार, ताराकोट लंगर परिसर, आद्कुंवारी मंदिर, भैरव घाटी, सांझी छत आदि स्थानों पर लगाई जा रही है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का डिजाइन आइआइटी जम्मू ने तैयार किया है। सभी मौसम में एलईडी स्क्रीन निरंतर चलती रहेगी।

अधिकतम 48 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट रिपोर्ट होगी मान्य : श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बार फिर साफ किया है कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अधिकतम 48 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट रिपोर्ट मान्य होगी। इस संबंध में श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने बुधवार को ट्वीट कर श्रद्धालुओं से अपनी रिपोर्ट साथ लाने की अपील की। जिन यात्रियों के पास 48 घंटे के भीतर करवाई गई कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उनके लिए रेलवे स्टेशन कटड़ा, हैलीपैड, दर्शनी ड्योढ़ी और ताराकोट मार्ग पर जांच की व्यवस्था की गई है। किसी भी श्रद्धालु को बिना टेस्ट करवाए यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

कुंभ मेलाधिकारी डा. सेंगर पर एफआइआर की तैयारी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

- कोरोना जांच फर्जीवाड़े में मेला स्वास्थ्य विभाग प्रभारी की लापरवाही के स्पष्ट तौर पर मिले सबूत

कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े में सीडीओ की जांच में कुंभ मेला अधिष्ठान स्वास्थ्य विभाग और कुंभ मेलाधिकारी (स्वास्थ्य) डा. अर्जुन सेंगर की लापरवाही के प्रमाण मिले हैं। जल्द ही डा. सेंगर और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की तैयारी है। जांच समिति के अध्यक्ष सीडीओ सौरभ गहरवार ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार है और अगले दो-तीन दिन में उसे जिलाधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

मई में सामने आया कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े में कुंभ मेलाधिकारी (स्वास्थ्य) डा. अर्जुन सेंगर के खिलाफ सबूत मिले हैं। फिलहाल अब इस बात की जांच की जा रही है कि यह सब उन्होंने किस दबाव और लालच में आकर किया। जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीडीओ से जांच रिपोर्ट मिलते ही इस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

एसआइटी जल्द करेगी गिरफ्तारी

कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़ा की जांच कर रही एसआइटी एफआइआर में शामिल आरोपितों के खिलाफ सबूत मिलने और एफआइआर में धाराएं बढ़ने के बाद अब आरोपितों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। जांच अधिकारी राजेश साह ने बताया कि जिनके खिलाफ जांच में सबूत हासिल हो गए हैं, अगले एक सप्ताह में उन सभी पर कार्रवाई होगी।

केंद्र ने निजी टीकाकरण केंद्रों की धीमी गति पर गंभीर चिंता जताई

परामर्श

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने बुधवार को कहा कि कुछ राज्यों में निजी केंद्रों द्वारा कोरोना रोधी टीके खरीदने और उन्हें लगाने की धीमी गति 'गंभीर चिंता' का कारण है। उसने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रोज स्थिति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि टीकों की डोज के लिए मांग पत्र तुरंत टीका निर्माताओं को भेजे जाएं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ टीकाकरण अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान टीकों के आर्डर, डोज को प्राप्त करने तथा भुगतान में देरी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भूषण ने कहा कि कई निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों (पीसीवीसी) ने कोरोना टीकों की निर्धारित मात्रा के लिए कोई मांग पत्र नहीं दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कई राज्य सरकारों को पीसीवीसी द्वारा टीके खरीदने की सुविधा देने की आवश्यकता है। उसने कहा, 'राज्यों को दैनिक आधार पर स्थिति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि निजी टीका निर्माताओं को टीकों की निर्धारित मात्रा के लिए जल्द मांग पत्र दिया जाए।' मंत्रालय ने मांगी गई वैक्सीन की डोज और भुगतान के बीच अंतर शून्य रखने की सलाह दी है।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भाग लिया। मंत्रालय ने राज्यों तथा पीसीवीसी के नोडल अधिकारियों को को-विन पर मांगपत्र रखने, टीकों की निर्धारित मात्रा के लिए भुगतान के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की हैं।

'घबराहट पैदा करने के लिए टीकों पर निरर्थक बयान'

- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्यों को यह अच्छी तरह से पता होता है कि उन्हें कब और कितनी डोज मिलेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कुछ राज्यों की तरफ से कोरोना रोधी वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि लोगों में दहशत पैदा करने के लिए आधारहीन बयान दिए जा रहे हैं। राज्यों को यह अच्छी तरह से पता होता है कि उन्हें कब और कितनी डोज मिलेगी।

मांडविया ने कहा कि केंद्र की तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की डोज के आवंटन के संबंध में पहले ही सूचना दे दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राज्य सरकारें जिला स्तर तक टीकाकरण का काम सही योजना बनाकर कर सकें और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो।



मंत्री मांडविया की चेतावनी। फाइल फोटो

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, 'टीके की उपलब्धता के संदर्भ में मुझे विभिन्न राज्य सरकारों और नेताओं के बयान एवं पत्रों से जानकारी मिली है। तथ्यों के वास्तविक विश्लेषण से इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं।' स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों के जरिये टीकाकरण हो सके, इसलिए जून महीने में वैक्सीन की 11.46 करोड़ डोज राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गईं और जुलाई के महीने में इस उपलब्धता को बढ़ाकर 13.50 करोड़ डोज किया गया है। मांडविया ने कहा कि जुलाई में कितनी डोज दी जाएंगी, इसकी जानकारी राज्यों को 19 जून को ही दे दी गई थी। इसके बाद 27 जून व 13 जुलाई को केंद्र की ओर से राज्यों को जुलाई के पहले व दूसरे पखवाड़े के लिए उन्हें हर दिन की टीके उपलब्धता की जानकारी बैच के हिसाब से एडवांस में ही दी गई।

उन्होंने ट्वीट किया, 'अगर केंद्र पहले से ही अपनी तरफ से ये जानकारियां एडवांस में दे रही है और इसके बावजूद भी हमें कुप्रबंधन और टीके लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही हैं तो स्पष्ट है कि समस्या क्या है और वजह कौन है।'

राष्ट्रीय फलक

डेल्टा के वैरिएंट के उससे अधिक संक्रामक होने की संभावना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकाग) ने कहा है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के नए उप-स्वरूपों एवाई.1, एवाई.2 के डेल्टा से अधिक संक्रामक होने की संभावना नहीं है। एवाई.1 को डेल्टा प्लस के रूप में भी जानते हैं।

इंसाकाग ने अपने हालिया बुलेटिन में यह भी कहा कि एवाई.3 को डेल्टा के नए उप-स्परूप के रूप में चिन्हित किया गया है। इस म्यूटेंट के बारे में अभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन इसपर लगातार नजर रखी जा रही है। इंसाकाग ने कहा, 'न तो एवाई.1 के और न ही एवाई.2 के डेल्टा से अधिक संक्रामक होने की संभावना है। भारत में जून से वे उपलब्ध अनुक्रमणों में लगातार एक प्रतिशत से भी कम बने हुए हैं।' जयपुर से जागरण संवाददाता के मुताबिक राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिले हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है।

भौतिकी में भारत के कोहिनूर हैं प्रोफेसर अशोक सेन

बड़ी उपलब्धि

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रयागराज

किसी भी विज्ञानी की हसरत होती है कि उसका शोध दुनिया को नई जानकारी दे या अभूतपूर्व बदलाव की सौगात। इसके साथ ही एक और सपना होता है कि वह शोध इस कदर गुणवत्तापूर्ण हो कि उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाए। विज्ञान जगत में नोबेल पुरस्कार जैसी ही शोहरत देते हैं विज्ञानी के उल्लेखित (साइटेड) किए जाने वाले शोध। जिसका शोध जितना अधिक उल्लेखित है वह उतना ही महान विज्ञानी। सर्वाधिक उल्लेखित भारतीय विज्ञानी में शामिल हैं प्रोफेसर अशोक सेन। वह प्रयागराज स्थिति हरिश्चंद्र शोध संस्थान के लिए किसी कोहिनूर से कमतर नहीं हैं।

गणित व भौतिकी के विश्वस्तरीय शोध के लिए प्रख्यात हरिश्चंद्र शोध संस्थान के

> जब कोई भौतिक विज्ञानी शोध करता है तो उसके शोध के हवाले से सर्वाधिक शोध अथवा पेटेंट करने वाली संख्या से ही यह कामयाबी मिलती है। एक तरह से यह शोध की गुणवत्ता को मापने का भी कार्य करता है। मेरे अब तक करीब 300 शोधपत्र उल्लेखित किए गए हैं।
>
> -प्रो. अशोक सैन

> यह बेहद महत्वपूर्ण है कि किसी विज्ञानी के शोध को पढ़कर कितने अधिक लोग उस पर कार्य करते हैं। या फिर पढ़ने के बाद उस शोधपत्र का उल्लेख करते हुए अपने शोध क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। प्रो. सेन का सर्वाधिक उद्धरण गौरव की बात है।
>
> - प्रो. केएन उत्तम, इलाहाबाद विवि

प्रोफेसर अशोक सेन सर्वाधिक उल्लेखित (साइटेड) किए जाने वाले भारतीय विज्ञानी हैं। इनके शोध पत्रों के हवाले से या उसे आधार बनाकर दुनियाभर में सबसे ज्यादा शोध कार्य और पेटेंट किए गए हैं। प्रसिद्ध शोधपत्र के चलते दुनिया के शीर्ष पांच विज्ञानियों में शामिल प्रो. सेन की स्ट्रिंग थ्योरी में मजबूत पकड़ है।

कोलकाता में 15 जुलाई, 1956 को जन्मे डा. अशोक 1995 से हरिश्चंद्र शोध संस्थान में कार्यरत हैं। इसके अलावा पटना के मूल निवासी डा. केएस वीरभद्र भी ब्लैक होल्स पर एक शोध पत्र के साथ रिनाउंड श्रेणी में प्रवेश कर गए। इस क्रम में वह छठे भारतीय भौतिक विज्ञानी हो गए। डा. वीरभद्र का दावा है कि विज्ञान जगत में सुप्रसिद्ध शोध पत्र की श्रेणी में वह शोध पत्र आता है जिसके 500 से अधिक उद्धरण हों। इस श्रेणी का शोध पत्र होना अत्यंत कठिन है। उदाहरण के लिए भौतिक विज्ञान में भारत ने 13 प्रख्यात शोध पत्र प्रकाशित कर दुनिया के शीर्ष 15 देशों में जगह बनाई है।

एशिया में जापान पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। केवल दो भारतीय संस्थानों के पांच विज्ञानियों की बदौलत भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। इसमें प्रयागराज के झूंसी स्थित हरिश्चंद्र शोध संस्थान के अलावा पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फार एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स शामिल है। इसमें प्रो. अशोक सेन सर्वाधिक उल्लेखित भारतीय विज्ञानी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 1347 बार रोलिंग टैकयान और 1135 बार टैकयान मैटर साइटेड है। दोनों शोध जर्नल आफ हाई एनर्जी फिजिक्स में प्रकाशित हैं।

यह है स्ट्रिंग थ्योरी : जब अणु के विज्ञान को समझना होता है तो क्वांटम फील्ड थ्योरी का सहारा लिया जाता है। सब एटामिक और इलेक्ट्रान और प्रोटान के व्यवहार को समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब विज्ञानी इन दोनों थ्योरी को एक ही थ्योरी में पिरोने की बात करते हैं, ताकि वह हर तरह के विज्ञान के रहस्यों को जान सकें। विज्ञानियों की इसी जिज्ञासा ने स्ट्रिंग थ्योरी को जन्म दिया। स्ट्रिंग थ्योरी एक मात्र ऐसी थ्योरी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है।

40 फीसद सस्ते टिकट बुक कर ही दौड़ेगी तेजस

जासं, लखनऊ

- अधिकतम 30 फीसद महंगा हो सकेगा डायनामिक फेयर, यात्रियों को मिलेगी कैटरिंग की भी सुविधा

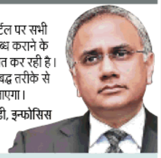
देश की कारपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को चेयरकार और एग्जीक्यूटिव क्लास में 40 फीसद सीटें इकोनोमी फेयर पर मिलेंगी, जबकि इस ट्रेन का अधिकतम किराया सामान्य किराए से 30 फीसद से अधिक नहीं होगा। सात अगस्त से दोबारा शुरू हो रही तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को पहले की तरह खानपान की सभी सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन होस्टेस यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी। बुधवार को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने तेजस एक्सप्रेस के संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को के लिए आइआरसीटीसी 30 दिन पहले एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा देगा। साथ ही, यात्रियों के ट्रेन में सफर करते समय उनके घर पर चोरी हो जाने की दशा में बीमा कवर की सुविधा भी पूर्व की तरह ही रहेगी। आइआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सप्ताह में चार दिन शनिवार, रविवार, सोमवार और शुक्रवार को चलने वाली तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए आन बोर्ड बुकिंग की सुविधा लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर छह पर उपलब्ध होगी, जहां यात्री अपना टिकट बुक करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। यात्रियों का सामान उनके घर से लेकर तेजस एक्सप्रेस तक पहुंचाने और फिर नई दिल्ली में उसकी डिलिवरी दर्ज पते पर करने की योजना बनाई गई है। संचालन के बाद समीक्षा होगी, फिर लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 15 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

बीएसई-कंपनियों का कुल पूंजीकरण 233 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली : बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बुधवार को 2,33,06,440.17 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बुधवार को 134.32 अंक या 0.25 फीसद बढ़कर 52,904.05 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के दौरान बढ़ोतरी देखी गई। इससे बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,33,06,440.17 करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दो कारोबारी सत्रों में निवेशकों की पूंजी 1,42,806.24 करोड़ रुपये बढ़ी है। (प्रेट्र)



नए आइटी पोर्टल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी कड़ी मेहनत कर रही है। सभी मसलों को चरणबद्ध तरीके से जल्द हल कर लिया जाएगा।
— सलिल पारेख, एमडी, इन्फोसिस

सेंसेक्स	52,904.05	▲ 134.32
निफ्टी	15,853.95	▲ 41.60
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 47,024	▲ ₹ 23
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹67,663	▼ ₹399
डॉलर	₹74.59	▲ ₹0.10
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 75.86	

एक नजर में

एसएलसीएम को यूरोपीय अनुदान

नई दिल्ली : कृषि सेक्टर में तकनीकी व वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट (एसएलसीएम) को दालों व दूसरे खाद्यान्नों की क्वालिटी सुधारने वाले अपने एप्लीकेशंस को बेहतर बनाने के लिए यूरोप की एक प्रतिष्ठित एजेंसी से अनुदान हासिल हुआ है। कंपनी ने बताया कि वेयरहाउसिंग कंपनियों की श्रेणी में किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा हासिल किया गया यह सबसे बड़ा व अपनी तरह का अकेला अनुदान है। कंपनी का कहना है कि मोबाइल के जरिये खाद्यान्नों की क्वालिटी जांचने की विश्वस्तरीय तकनीक बनाने में इस अनुदान का उपयोग किया जाएगा। (जाब्यू)

जेएलआर ने 88 लाख में पेश की लैंड रोवर डिस्कवरी

नई दिल्ली : टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली ऑटो कंपनी जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने भारत में लैंड रोवर डिस्कवरी का उन्नत संस्करण पेश किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 88.06 लाख रुपये से शुरू होती है। जेएलआर इंडिया के प्रेसिडेंट व एमडी रोहित सूरी ने कहा कि सात सीटों वाले इस वाहन को पेट्रोल और डीजल इंजन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें एंटरटेनमेंट के विशेष साधनों समेत विलासिता और कुशलता के समावेश है। (प्रेट्र)

एजीईएल को 25,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की अनुमति

नई दिल्ली : अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के शेयरधारकों ने कंपनी को कर्ज के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह सीमा 15,000 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि कर्ज सीमा बढ़ाए जाने के विशेष प्रस्ताव को शेयरधारकों ने 13 जुलाई को मंजूरी दे दी। कंपनी के शेयरधारकों ने इससे पहले नौ जनवरी, 2018 को कंपनी के निदेशक बोर्ड को यह छूट दी थी कि वह समय-समय पर 15,000 करोड़ रुपये तक जुटा सकता है। (प्रेट्र)

मास्टरकार्ड पर आरबीआइ की नकेल

कंपनी अब क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड के नए ग्राहक नहीं बना सकेगी

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक को क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड कार्ड के नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी है। यह रोक 22 जुलाई से प्रभावी होगी। कंपनी पर डाटा संरक्षण नियमों के अनुपालन में विफल रहने का आरोप है। आरबीआइ ने कंपनी से कहा है कि वह कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग कंपनियों को केंद्रीय बैंक के नए नियमों के प्रति आश्वस्त हो जाने को कहे। हालांकि आरबीआइ के आदेश से मास्टरकार्ड के क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड कार्डधारक मौजूदा ग्राहकों को पर कोई विपरीत असर नहीं होगा।

अपने बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी को पर्याप्त वक्त और मौके दिए गए, लेकिन वह पेमेंट सिस्टम डाटा के भंडारण से संबंधित नियमों के पालन में विफल रही है। आरबीआइ द्वारा डाटा भंडारण को लेकर छह अप्रैल, 2018 के एक सर्कुलर में कहा गया था कि सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को छह माह के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान से संबंधित सभी आंकड़ों का भंडारण भारत में ही किया जाए। इस सर्कुलर के अनुसार पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को किसी भी लेनदेन की शुरू से लेकर अंत तक सभी आंकड़ों का भंडारण भारत में करना था। उन्हें इसकी अनुपालन रिपोर्ट आरबीआइ को सौंपनी थी। इसके साथ ही उन्हें सर्ट-इन से मान्यता प्राप्त ऑडिटर की सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, जिसे निदेशक बोर्ड से अनुमोदन हासिल हो, एक निश्चित समय के भीतर सौंपनी थी।

मास्टरकार्ड ऐसी तीसरी बड़ी पेमेंट सिस्टम कंपनी है, जिसे आरबीआइ के पेमेंट सिस्टम डाटा भंडारण नियमों के तहत ऐसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले आरबीआइ ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प तथा डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल को इस वर्ष पहली मई से भारतीय बाजार में नए ग्राहक बनाने से रोक दिया गया था।

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, आरबीआइ के इस कदम से मास्टरकार्ड को बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इस अमेरिकी कंपनी के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। आरबीआइ के 2018 के उस सर्कुलर के खिलाफ अमेरिकी कंपनियों ने बहुत लॉबीइंग की थी। उनका कहना था कि इस फैसले से उनकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत बहुत बढ़ जाएगी और धोखाधड़ी पकड़ने के उनके वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को नुकसान होगा, लेकिन आरबीआइ ने उनकी नहीं सुनी थी।

ऐसे समझें पूरा मामला

क्या हुआ : भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड को 22 जुलाई से क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड का एक भी नया ग्राहक बनाने से रोक दिया।

क्यों हुआ : अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड पर आरोप है कि भारत में काम कर रही उसकी शाखा मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक ने डाटा भंडारण से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया। काफी समय और मौके देने के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक की नहीं सुनी।

क्या हैं नए नियम : वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर पेमेंट सिस्टम कंपनियों को अपने ग्राहकों से की गई लेनदेन की सभी सूचनाओं का भंडारण भारत में ही करने का आदेश दिया था।

कंपनी पर क्या असर होगा : मास्टरकार्ड के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। लिहाजा उसकी बाजार हिस्सेदारी पर सीधा असर होगा। फिर भी, पुराने ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा।



मास्टरकार्ड ● फाइल फोटो

पुरानी इंसेंटिव स्कीम देगी गारमेंट निर्यात को गति

कैबिनेट का फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रोजगारपरक क्षेत्र में शुमार गारमेंट और मेडअप्स निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने पुरानी इंसेंटिव स्कीम को फिर शुरू करने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवी (आरओएससीटीएल) स्कीम फिर लागू करने को मंजूरी दे दी गई। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को आरओएससीटीएल स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसे अब इस साल एक जनवरी से लागू माना जाएगा और यह स्कीम 31 मार्च, 2024 तक मान्य रहेगी। इस स्कीम का फायदा गारमेंट, अपैरल व मेडअप्स के निर्यातकों को मिलेगा। आरओएससीटीएल के फिर से लागू होने से राज्य व केंद्र स्तर पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे कि मंडी शुल्क, बिजली पर लगने वाले शुल्क, स्टांप ड्यूटी जैसे शुल्क भी निर्यातकों को रिफंड हो जाएंगे, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और निर्यातक वैश्विक बाजार में आसानी से दूसरे देशों का मुकाबला कर सकेंगे। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया जैसे देश भारत को गारमेंट निर्यात के बाजार में टक्कर देते हैं।

आरओएससीटीएल स्कीम के तहत निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी पर लगने वाले शुल्क के बराबर की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप दी जाती है। निर्यातक किसी उपकरण के आयात शुल्क को अदा करने के साथ या किसी अन्य जगहों पर शुल्क अदायगी में उस स्क्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

टेक्सटाइल सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया, आरओएससीटीएल स्कीम लागू होने से निर्यातकों की लागत में चार से पांच फीसद तक की कमी आएगी। उन्होंने बताया कि गारमेंट मेडअप्स का निर्यात पिछले कुछ वर्षों से 20-22 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें वृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है। सबसे कम विकसित देशों की सूची में शामिल होने से बांग्लादेश जैसे देशों को यूरोप में शुल्क से छूट है जिससे भारत स्पर्धा में पिछड़ रहा है।

चंदा कोचर मामले में 15 सितंबर तक कार्रवाई से रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने सेबी के न्यायाधिकारी से आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर से संबंधित मामले में 15 सितंबर तक कार्रवाई नहीं करने को कहा है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की एक रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कोचर को जारी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सैट का यह आदेश उसी नोटिस के मामले में है। सैट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

श्रीकृष्ण समिति को आइसीआइसीआइ बैंक में लेनदेन के आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था। समिति ने जनवरी, 2019 में बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में समिति ने कहा कि कोचर ने बैंक की नीतियों और अन्य नियमों का उल्लंघन किया है। कोचर आइसीआइसीआइ बैंक की एमडी व सीईओ थीं। उन्होंने अक्टूबर, 2018 में इस्तीफा दे दिया था। आइसीआइसीआइ बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

यूनिटधारकों की मंजूरी के बाद ही होंगी डेट स्कीम बंद

नई दिल्ली, प्रेट्र : फ्रैंकलिन टेंपलटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम एकाएक बंद नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पहले डेट स्कीम बंद करने के कारणों की पूरी जानकारी के साथ सर्वसाधारण के लिए सूचना जारी करनी होगी। उसके बाद योजना के ट्रस्टी को अधिकांश शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के विषय में सेबी के विभिन्न प्रविधानों की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर ट्रस्टी ऐसी योजनाओं में नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो बाजार नियामक को उसमें दखल देने का पूरा अधिकार है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन को निवेशकों की अनुमति के बिना उसके छह म्यूचुअल फंड स्कीम बंद करने से रोक दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इन योजनाओं के ट्रस्टी द्वारा लिए गए निर्णय में सेबी की दखलअंदाजी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसने यह माना कि अगर सेबी को कहीं से लगता है कि ट्रस्टी ने म्यूचुअल फंड नियमन की किसी धारा का उल्लंघन किया है तो वह दिशानिर्देश जारी करने के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। फ्रैंकलिन टेंपलटन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका समेत इस मामले में दाखिल कई अन्य याचिकाओं पर विचार करते हुए यह फैसला दिया। उल्लेखनीय है कि फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड ने पिछले वर्ष अप्रैल में अपनी छह डेट योजनाएं बंद कर दी थीं।

थोक महंगाई दर में मामूली राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ईंधन एवं बिजली की थोक कीमतों में कमी से जून की थोक महंगाई दर पिछले माह के मुकाबले नरमी के साथ 12.07 फीसद के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि लगातार तीसरे महीने थोक महंगाई दर दहाई अंक के स्तर पर कायम है। इस वर्ष मई में थोक महंगाई दर 12.94 फीसद थी तो इस वर्ष अप्रैल में यह दर 10.74 फीसद थी। जून में खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों में भी राहत मिली है। जून में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद 3.09 फीसद रही जबकि इस वर्ष मई में यह दर 4.4.31 फीसद थी। जून में धान, गेहूं, अनाज व आलू जैसे खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों में पिछले वर्ष जून के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून के बेहतर होने से आने वाले महीनों में थोक महंगाई दर में भी नरमी की उम्मीद की जा सकती है। थोक महंगाई दर में कमी से अगले खुदरा महंगाई दर में भी नरमी आएगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में ईंधन व बिजली की थोक महंगाई दर 32.83 फीसद रही जबकि पिछले यह दर 37.61 फीसद थी। हालांकि इस वर्ष जून में पेट्रोल व डीजल की थोक कीमतों में पिछले वर्ष जून के मुकाबले क्रमशः 59.94 व 59.92 फीसद की बढ़ोतरी रही। एलपीजी के थोक दाम में भी पिछले वर्ष जून के मुकाबले 31.44 फीसद का इजाफा रहा। जून में मैन्यूफैक्चरिंग उत्पाद की थोक महंगाई दर 10.88 फीसद रही, जो इस वर्ष मई के लगभग बराबर है। इस वर्ष मई में यह दर 10.83 फीसद थी। खाने-पीने की चीजों में प्याज और दाल को छोड़ अन्य किसी वस्तुओं की थोक कीमत में दहाई अंक की बढ़ोतरी नहीं रही। आलू के थोक दाम में पिछले वर्ष जून के मुकाबले 30.97 फीसद की गिरावट रही।



आलू और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों में आई बड़ी गिरावट ● फाइल फोटो

- पिछले माह के मुकाबले नरमी के साथ 12.07 फीसद के स्तर पर पहुच गई
- इस वर्ष मई में थोक महंगाई दर 12.94 फीसद थी तो अप्रैल में 10.74 फीसद

टाटा ने तेज की एयर इंडिया की ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया

नई दिल्ली, आइएएनएस : टाटा ग्रुप ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया तेज कर दी है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि टाटा ग्रुप की कंपनियों के अधिकारियों ने एयर इंडिया की विभिन्न साइट का हाल के दिनों में निरीक्षण किया है। इस दल में एयर एशिया इंडिया, टीसीएस और टाटा ग्रुप की इन्य कंपनियों के अधिकारी शामिल रहे हैं। उन्होंने एयर इंडिया की परिचालन और प्रशासनिक साइट्स का निरीक्षण किया है। सूत्रों के अनुसार ग्रुप एयर इंडिया के मानव संसाधन वाले हिस्से पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है।

यह घटनाक्रम इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एयर इंडिया के लिए अंतिम बोली लगाने की अवधि सितंबर में खत्म हो रही है। एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप और खुद के बीच बेहतर समन्वय के लिए विनिवेश इकाई का गठन किया है। कंपनी ने टाटा ग्रुप को अपनी टिकटिंग और चेक-इन काउंटर जैसे आंतरिक परिचालन क्षेत्रों तक भी पहुंच सुनिश्चित की है।

पिछले सप्ताह टाटा ग्रुप की टीम ने कोलकाता के अलावा नई दिल्ली में कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस का भी निरीक्षण किया है। बीते शुक्रवार को टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित एयर इंडिया की विभिन्न साइट का निरीक्षण किया। मुंबई स्थित एक सूत्र ने कहा कि टाटा ग्रुप अपनी दो एयरलाइन कंपनियों एयर एशिया इंडिया और विस्तारा के जरिये एयर इंडिया के तकनीकी पहलुओं की जानकारी ले रहा है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

कुएं में गिरा भालू, ग्रामीणों ने चारपाई के सहारे निकाला बाहर

अंबिकापुर: सूरजपुर जिले के ग्राम धूर में बुधवार तड़के तीन बजे बाबूलाल यादव के घर से लगे कुएं में एक भालू गिर गया। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। करीब चार घंटे चले रेस्क्यू के बाद चारपाई के सहारे भालू को बाहर निकालकर जान बचा ली गई। (नईदुनिया)

जौहर विवि का गेट तोड़ने के मामले में 19 को होगी सुनवाई

रामपुर : सपा सांसद आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय का मुख्य गेट तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के मामले में 19 जुलाई को बहस होगी। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। (जासं)

कोयला तस्करी में फरार विनय मिश्रा को भेजे जा रहे पैसे

कोलकाता : कोयला व गो तस्करी के आरोपित तृणमूल नेता विनय मिश्रा को फरार होने के बाद भी छद्म (शेल) कंपनियों, उसके करीबियों तथा रिश्तेदारों के बैंक खातों के माध्यम से नियमित पैसे भेजे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे 45 बैंक खातों की पहचान की है। सीबीआइ का दावा है कि विनय मिश्रा प्रशांत महासागर के द्वीप वानुअतु में है तथा उसने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली है। (राब्यू)

मप्र में आठ साल से प्रतिदिन 22 बच्चे हो रहे गुमशुदा

भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते आठ साल के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिदिन 22 बच्चे प्रदेश से लापता हुए। इनमें से 30 फीसद बच्चों की बरामदगी नहीं हो पाती है। इनमें बालिकाओं की संख्या करीब ढाई गुना है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मंडला आदि से बच्चों के लापता होने की घटनाएं अधिक हुई हैं। (राब्यू)

पुलिस ने यूपी-विहार के बाल श्रमिकों को मुक्त कराया

हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने छापा मारकर कृष्णा फार्मा और महेश्वरम कस्बे से 20 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। इनमें उप्र, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के बच्चे हैं। (एएनआइ)

राजद्रोह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कानून अभिव्यक्ति पर 'डरावना प्रभाव' डालता है और यह वाक् स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका की एक प्रति अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सौंपने का निर्देश दिया है। मेजर-जनरल (अवकाशप्राप्त) एसजी वोमबटकेरे द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे स्पष्ट रूप से खत्म कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील है कि राजद्रोह की धारा को देखने से पहले, समय के आगे बढ़ने और कानून के विकास पर गौर करने की जरूरत है। इससे पहले, शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने दो पत्रकारों की याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। 27 जुलाई को सुनवाई करेगी।

एफएमपी ने की याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग

नई दिल्ली, एएनआइ : फाउंडेशन आफ मीडिया प्रोफेशनल्स (एफएमपी) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर उस याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की है जिसमें भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। एफएमपी के वकील राहुल भाटिया ने कहा कि फेडरेशन हस्तक्षेप करना चाहता है। राजद्रोह का कानून एक औपनिवेशिक हुक्म है। जिसे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार किया गया था।

पीड़ित ही नहीं, समाज के विरुद्ध भी गंभीर अपराध है जहरीली शराब : हाई कोर्ट

सुनवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज :

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौत की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और कहा कि पैसे की लालच में नकली शराब बेचने वाले लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। विधवाओं और अनाथों को जन्म दे रहे हैं, ये न केवल पीड़ित अपितु समाज के अपराधी हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने संगीता जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए की है।

कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज के फूलपुर की अमिलिया देशी शराब के ठेके से नकली शराब पीने से छह लोगों की मौत व दर्जनों के बीमार होने की घटना गंभीर है। मरने से बचे लोगों को आगे चल कर कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। याची को महिला होने के नाते ऐसे अपराध में राहत नहीं दी जा सकती। जमानत पर छूटने पर पीड़ितों को धमकाये जाने की आशंका है। आबकारी निरीक्षक विजय प्रताप यादव ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अनुज्ञापी याची के पति श्याम बाबू जायसवाल व सेल्समैन जगजीत सिंह को नकली शराब बेचने का आरोपित बनाया गया है। एफआइआर के अनुसार 19 नवंबर, 2020 को लोगों ने ठेके से शराब खरीदी। पीने के बाद बीमार पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छह लोग मर गए और कई बीमार हुए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सेल्समैन जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर नमूना जांच के लिए भेजा गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध : केंद्र

- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इन योजनाओं से हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध हैं और ये असमानता को घटाने पर केंद्रित हैं तथा इनसे हिंदुओं या अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।

केंद्र ने एक याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत में दायर एक शपथ पत्र में यह दलील दी है। इस याचिका में कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का आधार धर्म नहीं हो सकता। यह याचिका नीरज शंकर सक्सेना और पांच अन्य लोगों ने दायर की है।

केंद्र ने अपने शपथपत्र में कहा कि मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों में असमानता को कम करने, शिक्षा के स्तर में सुधार, रोजगार में भागीदारी, दक्षता एवं उद्यम विकास, निकाय सुविधाओं या अवसंरचना में खामियों को दूर करने पर केंद्रित हैं। शपथपत्र में कहा गया, ये योजनाएं संविधान में प्रदत्त समानता के सिद्धांतों के विपरीत नहीं हैं केंद्र ने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं केवल अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर तबकों, वंचित बच्चों, अभ्यर्थियों, महिलाओं के लिए हैं, न कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए। नीरज शंकर सक्सेना और पांच अन्य लोगों की याचिका में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को जो लाभ मिल रहे हैं, उनसे याचिकाकार्ताओं को उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर संवैधानिक रूप से वंचित रखा जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और हिंदू समुदाय के अन्य सदस्यों को इसलिए पीड़ित होना पड़ रहा है क्योंकि वे बहुसंख्यक समुदाय में पैदा हुए हैं।

ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई महबूबा की मां

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। उन्हें सुबह 11 बजे ईडी के स्थानीय कार्यालय में पहुंचना था। उनके पारिवारिक सूत्रों की मानें तो गुलशन नजीर ने ईडी को एक पत्र लिखकर उस पूरे मामले की जानकारी मांगी थी, जिसके संदर्भ में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी ने 15 अप्रैल को भी महबूबा की मां को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस समय वह घर पर क्वारंटाइन होने के कारण हाजिर नहीं हुई थीं। इसके बाद कोविड संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने से उपजे हालात में यह पूछताछ स्थगित हो गई थी। छह जुलाई 2021 को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए परिसीमन आयोग के साथ पीडीपी द्वारा मुलाकात से इन्कार किए जाने के बाद ईडी के अधिकारी नोटिस लेकर उनके सरकारी निवास पर पहुंच गए थे।

ईडी ने गिलानी को 14 लाख रुपये जमा कराने का नोटिस

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को मनी लांड्रिंग के एक मामले में 14 लाख रुपये जमा कराने का डिमांड नोटिस जारी किया है। गिलानी को यह राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत पेनल्टी के तौर पर जमा करनी है। उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है।

देशमुख की पत्नी से भी पूछताछ करेगा ईडी

राज्य ब्यूरो, मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख से पूछताछ करेगा। ईडी ने उन्हें गुरुवार को अपने मुंबई कार्यालय में बुलाया है। वकील कमलेश घुमरे का कहना है कि अनिल देशमुख मानते हैं कि जांच न्यायसंगत नहीं है।

किशोरों को करंट लगाया, चाबुक से पीटा

जागरण संवाददाता, बरेली

मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाकर डेयरी संचालक अवधेश ने छह किशोरों से बर्बरता की। सभी को जबरन घर से खींच लाया। डेयरी में बंधक बनाकर चाबुक से पीटा, करंट के झटके लगाए। सभी नाबालिग खुद को बेकसूर बताकर छटपटाते रहे, बिलखते रहे, मगर आरोपित को तरस नहीं आया। इन किशोरों में एक की मां ने डेयरी में बच्चों को इस हाल में देखा तो दौड़कर थाने पहुंचीं। उनकी तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

बरेली के गंगापुर में चीनी वाली गली में अवधेश कुमार यादव की डेयरी है। पिछले सप्ताह उसका 30 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन चोरी हो गया था, जिसकी तहरीर श्यामगंज पुलिस चौकी में दी गई थी। पुलिस जांच शुरू करती, इससे पहले अवधेश खुद ही विवेचक बन बैठा। शक के आधार पर मंगलवार रात करीब 12 बजे वह साथियों के साथ मेला ग्राउंड में रहने वाले किशोर के घर पहुंचा और जबरन खींच लाया। रात भर उसे पीटा। उससे दोस्तों के नाम पूछे और बुधवार सुबह को कालाबाड़ी कांठ की मठिया से एक किशोर, सिकलापुर के रहने वाले दो किशोर को भी घर से उठा लाया। आरोप है कि चोरी कुबूल कराने के लिए करंट भी लगाया।

पड़ोसी ने दी सूचना, अवधेश कर ले गए अगवा : मेला ग्राउंड में रहने वाले किशोर के स्वजन का कहना है कि वह गर्मी के कारण घर के बाहर बैठा था। वहीं से अवधेश उठा ले गया। परिवार वाले सो चुके थे, इसलिए पता नहीं चला। बाद में मां की आंख खुली, मगर बेटा घर में नहीं था। सुबह पड़ोसियों ने बताया कि उसे अवधेश जबरन खींच ले गया था, जिसके बाद वह डेयरी पर पहुंची। वहां देखा कि बेटे समेत पांच लड़के बंधक हैं। वह तुरंत बारादरी थाने पहुंचीं। इसके बाद पुलिस ने सभी को बंधनमुक्त कराया। हालांकि इससे पहले आरोपित फरार हो चुके थे।

रातभर भूखे रखा, बनाई वीडियो : किशोर ने पुलिस को बताया कि रात में अवधेश उसे डेयरी में लेकर आया और पीटने लगा। उसने मोबाइल चोरी से इन्कार किया तो बंधक बनाकर करंट के झटके दिए। चाबुक से पिटाई की। वह चीखता रहा। आरोपितों ने पानी तक नहीं दिया। चोरी कुबूल कराने के लिए वीडियो बनाया।

प्रत्येक से 25 हजार की मांग : अवधेश का दुस्साहस इस कदर बढ़ा हुआ था कि उसने कहा कि प्रत्येक के स्वजन 25-25 हजार देंगे, तब यहां से जाने दूंगा।

चोरी के शक में बर्बरता

30 हजार का मोबाइल, प्रत्येक से 25 हजार की मांग

किशोर की मां ने बताया कि अवधेश का दुस्साहस इस कदर बढ़ा हुआ था कि जब बच्चों को छोड़ने की बात कही तो कहा कि प्रत्येक के स्वजन 25-25 हजार देंगे, तब यहां से जाने दूंगा। विरोध किया तो पीटने की धमकी दी। इसी के बाद वह डर गई और बारादरी पुलिस को पूरी कहानी बताई।

प्रकरण गंभीर है। नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सभी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। - रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी, बरेली

आगरा में चिकित्सक का अपहरण

जागरण संवाददाता, आगरा : शहर के एत्माद्दौला क्षेत्र से मंगलवार शाम को बदमाशों ने वरिष्ठ चिकित्सक का कार सहित अपहरण कर लिया। डाक्टर अपने हास्पिटल के लिए घर से निकले थे। स्वजन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुधवार दोपहर उनकी कार धौलपुर (राजस्थान) में लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है।

शहर के ट्रांस यमुना कालोनी फेस दो निवासी डा. उमाकांत गुप्ता का एत्माद्दौला क्षेत्र में हाईवे किनारे विद्या नर्सिंग होम है। मंगलवार शाम 7.30 बजे वे रोजाना की तरह हास्पिटल में राउंड लेने घर से निकले। आम दिनों में दस बजे तक घर आ जाते थे, मगर मंगलवार रात 11 बजे तक न आने पर स्वजन चिंतित हुए। उनका मोबाइल फोन स्विच आफ था। डा. उमाकान्त की पत्नी डा. विद्या गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डाक्टर के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया। पता चला कि मोबाइल फोन रात 8.30 बजे से ही बंद था। उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन सैंया क्षेत्र में मिली।

दैनिक जागरण
प्रयास में जितना परिश्रम होगा परिणाम उतना ही अनुकूल निकलेगा

कोरोना काल में कांवड़ यात्रा

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया, उस पर हैरानी नहीं, क्योंकि इन दिनों देश भर में विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन या तो स्थगित किए जा रहे हैं या फिर उन्हें प्रतीकात्मक रूप से आयोजित किया जा रहा है। अभी हाल में जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा निकाली गई तो शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। यही काम अहमदाबाद में भी किया गया। ऐसा कोरोना संक्रमण के कारण किया गया। इस सिलसिले में यह भी ध्यान रहे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि तीर्थ यात्राओं और पर्यटन पर रोक लगाने की जरूरत है। बीते दिनों खुद प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता व्यक्त की कि पर्यटन स्थलों में भारी भीड़ कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करती हुई दिख रही है। उनकी इस चिंता का आशय यही था कि राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थलों में भीड़ को इस तरह जमा होने से रोकें।

एक ऐसे समय जब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका गहराती जा रही है और कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही, तब ऐसे किसी आयोजन से बचने में ही भलाई है, जिसमें भारी भीड़ जुटती हो। चूंकि कांवड़ यात्रा में लाखों शिवभक्त भाग लेते हैं इसलिए संक्रमण फैलने की आशंका तो है ही। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने की बात कही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जरा सी गफलत बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है। इस सिलसिले में हरिद्वार कुंभ के अनुभव की अनदेखी नही की जा सकती, जहां कोरोना जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का संज्ञान इसीलिए लिया, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया। चूंकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका सिर उठाए हुए है इसलिए उचित यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। यह सही है कि यथासंभव श्रद्धालुओं की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए, इसलिए उचित यह होगा कि हर कहीं कांवड़ यात्रा का आयोजन प्रतीकात्मक रूप से किया जाए। इससे दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी-धार्मिक परंपरा का निर्वाह भी हो जाएगा और कोरोना संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सकेगा।

जागने का समय

पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण ही पहाड़ों को प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ रहा है। प्रकृति समय-समय पर चेताती है, पर लोग कोई सबक नहीं लेते हैं। जब हादसा होता है तो हर पक्ष सक्रिय हो जाता है, लेकिन समय के साथ सब निष्क्रिय हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों हटाया जा रहा है। कई जगह से लोगों को हटा दिया गया है जबकि कई लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। गंभीर मंथन का विषय है कि इन लोगों को पहले वहां पर बसने ही क्यों दिया गया? जब निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया? ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब हो गया है। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को लोगों के हितों की रक्षा के लिए चुना जाता है वे भी इस संबंध में खामोश रहते हैं। कई जगह इन सभी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग भी रहता है। पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण हो रहा है। जहां हरेभरे पेड़ होते थे वहां पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या इन क्षेत्रों में भवन निर्माण से पहले भूविज्ञानियों की सलाह ली जाती है? क्या यह पता लगाया जाता है कि इन पहाड़ों की बनावट क्या है और कितने मंजिल का भवन बनाया जा सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ की ढलानों पर भवन निर्माण से पूर्व यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वहां की बनावट कैसी है? राज्य के कई क्षेत्रों में ढलानों पर बनाए गए भवन कुछ ही साल में ध्वस्त हो गए हैं। सरकारी स्तर पर भी इस तरह की लापरवाही होती रही है। ठियोग में बिना प्रयोग किए छात्रावास इसलिए असुरक्षित घोषित किया गया, क्योंकि साथ लगता डंगा धंस गया था। इससे आसपास के घरों को भी खतरा हो गया है। सवाल यही है कि क्या भवन निर्माण से पहले वहां की परिस्थितियों को नहीं देखा जाता है। यदि सभी पहलुओं को देखकर नियोजित तरीके से निर्माण किया जाए तो हादसों की आशंका कम रहती है। विकास जरूरी है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर विकास किया जाए तो नुकसान की आशंका नहीं रहती है।

> हादसा होने के बाद सक्रिय होने से बेहतर है कि पूर्व में ही ऐसे प्रबंध हों कि हादसे की आशंका ही न रहे

सुधार की मांग करती शिक्षा-परीक्षा



तरुण गुप्त

> अगले वर्ष 12वीं की परीक्षा कराने के लिए क्या हमारा तंत्र कहीं और बेहतर तरीके से तैयार नहीं होना चाहिए था?

पिछले एक-डेढ़ साल के कोरोना काल में जीवन का शायद ही कोई अन्य पहलू इतने नाटकीय रूप से प्रभावित हुआ हो, जितना प्रभाव इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है। कोविड महामारी ने स्कूल और कॉलेज के जीवन को एकदम बदलकर रख दिया है। कोरोना वायरस की भयावहता ने पारंपरिक शिक्षा एवं परीक्षाओं की राह बाधित की हुई है। परंपरावादी इससे मायूस हैं। ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति आदर्श तो नहीं, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल सबसे उपयुक्त विकल्प लगती है। वैसे भी ऑनलाइन शिक्षण एवं मूल्यांकन की पद्धतियां अभी विकास के चरण में हैं। शिक्षा तंत्र के विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है कि इसमें कोई कारगर प्रणाली विकसित की जाए। इस पर आए सुझाव कुछ चिंताएं भले ही दूर करते हैं, किंतु कई प्रश्न भी उठाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि अहम मुद्दे अनसुलझे ही हैं।

भारतीय स्कूली छात्र के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही परीक्षा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सबसे स्वीकार्य कसौटी भी है। कोविड के कारण जहां इस साल 12वीं की परीक्षा रद कर दी गई वहीं अगले सत्र के लिए उसका प्रारूप बदल दिया गया। प्रस्तावित परीक्षा दो चरणों में होगी। ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में मूल्यांकन में आंतरिक आकलन और पूर्व परीक्षाओं को भी जोड़ा जा रहा है, मगर स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 12वीं के परिणाम की महत्ता कम नहीं हुई है। यह बिंदु हमें देश में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की वास्तविक समस्या से साक्षात्कार कराता है। कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी दबाव है। उनमें जितने आवेदन आते हैं, उस अनुपात में प्रवेश देना असंभव है। इसका परिणाम निकलता है आसमान छूती कटऑफ सूची में। हर साल कुछ सबसे वांछित कॉलेजों में प्रवेश के लिए अर्हता सूची के 98 प्रतिशत या उससे भी अधिक के बेतुके स्तर पर जाने के समाचार आते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में प्रवेश के इच्छुक छात्र को 12वीं कक्षा में न केवल अंग्रेजी, बल्कि गणित, भौतिकी और अपने अन्य विषयों में भी 98 फीसद अंक लाने होंगे। इस तंत्र से मार खाए कुछ साधनसंपन्न छात्र स्नातक के लिए विदेश चले जाते हैं। असल में प्रतिभा पलायन का अभिशाप स्कूली शिक्षा की समाप्ति के साथ ही शुरू हो जाता है।

उच्च शिक्षा के लिए हमें और गुणवत्तापरक संस्थान चाहिए, जहां औसत अंक पाने वाले मध्यम प्रतिभा वाले छात्रों के लिए भी गुंजाइश हो। वर्तमान परिदृश्य में एक छात्र को प्रवेश मिलता है तो सैकड़ों वंचित रह जाते हैं। इसमें हमारे छात्रों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकतीं। नए कॉलेजों के साथ यह भी उतना आवश्यक है कि वे छोटे और मझोले शहरों में हों ताकि देश भर के छात्रों का जमावड़ा कुछ चुनिंदा मेट्रो शहरों में लगने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। इसमें दूरस्थ डिजिटल शिक्षा पथप्रदर्शक साबित हो सकती है। कनेक्टिविटी और सक्षमता जैसी चुनौतियों के बावजूद ऑनलाइन माध्यम में शिक्षा का कायाकल्प करने की अकूत संभावनाएं हैं।



अवधेश राजपूत

भारतीय स्कूल प्रणाली में कई शिक्षा बोर्ड हैं। प्रत्येक राज्य का अपना बोर्ड है। सीबीएसई जैसा एक अखिल भारतीय बोर्ड भी है। विभिन्न बोर्ड में न केवल पाठ्यक्रम, बल्कि परीक्षा एवं मूल्यांकन के पैमाने भी अलग हैं, जबकि उनके छात्र उच्च शिक्षा के लिए समान सीटों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ राज्य बोर्ड मूल्यांकन के लिए कहीं सख्त मापदंड अपनाते हैं, जहां सबसे मेधावी छात्र भी 90 प्रतिशत से अधिक अंकों के लिए संघर्ष करते हैं। इसके उलट सीबीएसई में शत प्रतिशत अंक प्राप्त करना भी हैरत में नहीं डालता। ऐसे में प्रत्येक बोर्ड में पर्सेंटाइल सिस्टम बराबरी वाली व्यवस्था बनाएगा। यह छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। इसके तहत संभव है कि सख्त मूल्यांकन वाले किसी बोर्ड के 80 फीसद अंकों को भी सीबीएसई जैसे उदार बोर्ड के 90 फीसद से अधिक वरीयता दी जाए। कई विकसित देशों में इसका व्यापक उपयोग जारी है। दुर्भाग्यवश इस आवश्यक मानकीकरण या बराबरी की व्यवस्था को अभी भारत में आजमाया जाना शेष है।

महामारी के कारण पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं के रद होने की स्थिति में सीबीएसई ने छात्रों के मूल्यांकन का नया तरीका तलाशा है। दो चरणों वाली परीक्षा के साथ ही आंतरिक मूल्यांकन और पूर्व परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का प्रस्तावित प्रारूप निष्पक्ष और न्यायोचित नहीं लगता। छात्र किसी पूर्व परीक्षा के मुकाबले 12वीं बोर्ड परीक्षा में कहीं अधिक परिश्रम और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नई व्यवस्था में आंतरिक मूल्यांकन पर स्कूली पूर्वाग्रह हावी होकर पूरी प्रक्रिया को विरुपित भी कर सकते हैं।

सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कटौती और प्रश्न पत्र प्रारूप में परिवर्तन की पेशकश की है। परीक्षाएं वास्तव में छात्र के ज्ञान, समझ और अभिव्यक्ति के भाव को परखने के लिए होती हैं। नई प्रस्तावित योजना के बहु-विकल्पीय प्रश्नों में अभिव्यक्ति तो निश्चित रूप से नहीं परखी जा सकेगी। एक कटु सत्य यह है कि अधिकांश प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय सीबीएसई को उच्च मानकों के अनुरूप नहीं पाते। ऐसे में नई व्यवस्था से उसकी प्रतिष्ठा और घटेगी।

हम मान सकते हैं कि 2020-21 असामान्य साल रहा, लेकिन अगले वर्ष 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने के लिए क्या हमारा तंत्र कहीं और बेहतर तरीके से तैयार नहीं होना चाहिए था? महामारी ने भले ही प्रत्यक्ष परीक्षा की राह रोक दी हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऑनलाइन मूल्यांकन प्रस्तावित व्यवस्था से कहीं बेहतर होता। यदि संसाधनहीन छात्रों को इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कुछ धनराशि खर्च भी करनी पड़े तो यह राज्य द्वारा किया गया सार्थक खर्च होगा। इसमें प्रश्न पत्रों को रचनात्मक रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि यह ओपन बुक परीक्षा जैसी होगी। साथ ही गड़बड़ियों को रोकने के लिए नकल रोधी सॉफ्टवेयर और निगरानी के अन्य तौर-तरीकों की मदद ली जा सकती है। ऐसा प्रचलन कई विकसित देशों में बहुत आम है।

इन आमूलचूल परिवर्तन वाले प्रस्तावों के पीछे आधारभूत विचार यही है कि छात्रों को तनाव से मुक्ति वाला परिवेश प्रदान किया जाए। इस बीच यह स्मरण रहे कि बेचैनी की सबसे बड़ी वजह अनिश्चितता होती है। अकादमिक परिदृश्य से संदेह के बादल अभी तक छंटे नहीं हैं। यदि हमने तत्परता से प्रभावी कदम नहीं उठाए तो शिक्षा-दीक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता होना तय है। चीजों को सरल बनाने के उत्साह में क्या हम मूल तत्व की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं?

response@jagran.com

सहकारिता के क्षेत्र में नई पहल



अरविंद मिश्रा

> सहकारी समितियों की कार्यकुशलता बढ़े, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय को पहले उन्हें पारदर्शी बनाना होगा

केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश में सहकारिता से जुड़ी करोड़ों जिंदगियों के लिए सुखद संदेश है। मालूम हो कि सहकारी संस्था अमूल की कारोबारी सफलता ने लाखों जिंदगियों को गुणवत्ता प्रदान करने का कार्य किया है। दुग्ध क्रांति के साथ ही इसने किसानों को आय का एक स्थायी स्रोत मुहैया कराया है। शहर से लेकर गांव तक सहकारी बैंकों ने उस तबके तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है, जो अर्थव्यवस्था में अंतिम पायदान पर खड़ा है। दूध और चीनी से लेकर दैनिक जरूरत की हर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहकारी समितियां आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 2019-2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सहकारी डेयरी ने 1.7 करोड़ सदस्यों से प्रतिदिन 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा। चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी मिलों की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक देश में 8 लाख 54 हजार 355 सहकारी समितियां थीं। इनमें सदस्यों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियां किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने से लेकर कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मुहैया कराने का कार्य करती हैं। मत्स्य पालन, चाय बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों से लेकर बुनकरों की जिंदगी को सहकारी समितियां संवार रही हैं। हमारी जिंदगी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले 55 क्षेत्रों में आज सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में सहकारिता की बुनियाद पर स्वास्थ्य क्षेत्र की भी आधारभूत संरचना खड़ी हो रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आयुष्मान सहकार योजना संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलने के लिए सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराया जाना है। सहकारी गतिविधियों पर आधारित उद्यम अब अंतरराज्यीय स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। देश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी की संख्या भी करीब डेढ़ हजार हो चुकी है। सहकारिता के इतने व्यापक क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रशासनिक नियमन और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने की मांग चल रही थी।

दरअसल सहकारिता मानव जीवन के उत्थान के लिए नैसर्गिक रूप से व्यवहार में लाई गई वह कार्यसंस्कृति है, जिसमें सबकी भागीदारी को वरीयता दी जाती है। इस व्यवस्था में अभावग्रस्त और शोषित वर्ग को मालिकाना हक के साथ आर्थिक प्रकल्प संचालित करने की सुविधा मिलती है।



अमित शाह को मिली सहकारिता की अहम जिम्मेदारी। फाइल

हालांकि सहकार आधारित उद्यम की ये गतिविधियां पूरी तरह साफ-सुथरी और दोषरहित हैं, ऐसा नहीं है। सहकारिता के 120 वर्ष की विकास यात्रा का अध्ययन करने से पता चलता है कि वित्त, मानव संसाधन और नीतिगत स्पष्टता का अभाव इस क्षेत्र की बड़ी चुनौती है। सहकारी संस्थाओं में निर्णय लेने की स्वतंत्रता ने इस क्षेत्र के अवसरों को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यविधि तथा प्रोन्नति संबंधी नीतियों में यहां कई तरह की विसंगतियां हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा विपणन व्यवस्था बाधित होने की समस्या से जूझ रहे हैं। जाहिर है, यह सब सरकारी निगरानी के अभाव का परिणाम है। येन केन प्रकारेण कुछ ही परिवार और समूह के सदस्य इन संस्थाओं में निर्वाचित तो कभी मनोनीत होते हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो, ये एक दूसरे को खूब उपकृत करते हैं। कई राज्यों में राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) और संस्थाएं तो अब सिर्फ नेताओं के राजनीतिक पुनर्वास का जरिया बन गई हैं। सहकार जब अपकार में तब्दील हो जाए तो सहकारी संस्था के भविष्य का आकलन सहज ही किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को सबसे पहले सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी बनाने पर जोर देना होगा। इससे सहकारी समितियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। अब तक केंद्र में सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय के अधीन था। कृषि मंत्रालय चूंकि स्वयं में एक बड़ा मंत्रालय है इसलिए सहकारिता क्षेत्र में उस पर आवश्यक रूप में ध्यान नहीं दिया जा सका, जिसकी उम्मीद वास्तविक सहकारों को थी।

संवैधानिक रूप से सहकारिता राज्य की सूची का विषय है। 2011 में संविधान के 97वें संशोधन के जरिये केंद्र और राज्यों में सहकारी गतिविधियों को एकरूपता देने का प्रयास हुआ। इसी तरह 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के जरिये सहकारी संस्था के एक से अधिक राज्यों में परिचालन गतिविधियों से जुड़ा कानून बना। जाहिर है अब इस क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए कानून और नीति निर्माण की जरूरत होगी। सवाल है कि क्या सहकारिता के बढ़ते कदमों को राज्यों के अलग-अलग कानूनों और पेचीदगियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। सहकारिता मंत्रालय के गठन का विरोध कर रहे कुछ नेता इसे संघवाद पर कथित हमला तो करार दे रहे हैं, लेकिन कानून और नियमन के बिना सहकारिता की सेहत कैसे सुधरेगी, इस पर खामोश हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को करीब से देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने जिस गुजरात मॉडल को विकसित किया, उसमें सहकारी संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही। दुर्भाग्य से सहकारिता संबंधी गतिविधियां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के अलावा देश के अन्य हिस्सों में उस रूप में सफल नहीं हो सकीं, जिस स्तर पर होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव और अनावश्यक सियासी दखल इसकी बड़ी वजह है। ऐसे में मोदी द्वारा सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा गृहमंत्री अमित शाह को सौंपना इस क्षेत्र में व्यापक सुधारों का भावी संकेत है। उम्मीद है कि सहकारिता की दुनिया में एक नई सुबह आएगी, जो सहकार के आत्मा यानी संस्कार, सर्वोदय और समन्वय के जरिये वंचित वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उद्धार पर केंद्रित हो।

(लेखक स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भय से रहित है आत्मा

हम अपने जीवन में बहुत चीजों से डरते हैं। विद्यार्थी जीवन में हम परीक्षाओं से डरते हैं। माता-पिता के रूप में हमें यह डर होता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा या नहीं और एक अच्छा इंसान बनेगा या नहीं। एक कारोबारी होने के नाते हमें अपने काम-धंधे की चिंता रहती है। सामान्यतः ये डर हमारे शारीरिक, मानसिक और इस दुनिया के बाहरी पहलुओं से जुड़े हैं। इसके विपरीत हमारे असल स्वरूप को कोई डर नहीं होता, जो शारीरिक नहीं, अपितु आत्मिक है।

याद रखें हमारा आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते सत्य है और पूर्ण रूप रूप से जागृत है। पूर्णतया सत्य होने के कारण आत्मा को कोई भय नहीं होता है, वह निर्भय है। इंसान में डर के चार प्रमुख कारण हैं। पहला शक, दूसरा कोई गलत काम करने, तीसरा कमजोर होने और चौथा सत्य को पहचानने की असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इन सबके अलावा हम सबको मृत्यु का भी डर होता है। हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु हमारे अस्तित्व का अंत है। यह डर हमेशा कई तरीकों से हमें परेशान करता रहता है। संत-महापुरुष हमें बताते हैं कि जो मरता है वह हमारा भौतिक शरीर है, जो कि जड़ पदार्थ से बना है। किंतु हमारा सच्चा स्वरूप, जो कि हमारा आत्मा है, वह सदा-सदा के लिए जीवित रहता है। इस संसार में जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह केवल हमारे इस भौतिक शरीर की मृत्यु है। आत्मा के लिए यह मृत्यु सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना है।

इसलिए पहली चीज जो हमें समझनी है वह यह कि हमारा आत्मा अमर है। यह सृष्टि की शुरुआत में भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए आत्मा के नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। अपने इस भौतिक जीवन को जीते हुए हमें अपने आत्मा को उसके असली स्रोत परमात्मा में मिलाना होगा। ध्यान-अभ्यास के जरिये जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे तो हम जीवन में सभी तरह के डर से मुक्त हो जाएंगे।

संत राजिंदर सिंह जी महाराज

कैंसर से भी खतरनाक है दहेज कुप्रथा

चंदन कुमार चौधरी

> दहेज एक सामाजिक बुराई है। यह कभी भी अकेले नहीं आती है, बल्कि अपने साथ भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी जैसी कई अन्य बुराइयों को भी लाती है

विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत के गांवों-शहरों में दहेज कुप्रथा बदस्तूर जारी है। शोधकर्ताओं ने 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों का अध्ययन किया और पाया कि 95 प्रतिशत शादियों में दहेज दिया गया। यह हालात तब है जब देश में 1961 में ही इसे गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके दहेज लेने और देने की कुप्रथा बदस्तूर जारी है, जिसका खामियाजा समाज के एक बड़े वर्ग को उठाना पड़ रहा है। दहेज के कारण आज भी समाज में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण होता है और उनके साथ घरेलू हिंसा होती है। ऐसे में कई बार उनकी मौत भी हो जाती है या उन्हें जान से मार दिया जाता है।

समझना होगा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। यह बुराई कभी भी अकेले नहीं आती है, बल्कि अपने साथ भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी जैसी कई अन्य बुराइयों को भी लाती है। ऐसे में हमें इस समस्या को किसी न किसी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास करने ही होंगे जिससे इन बुराइयों का सफाया किया जा सके। ऐसा नहीं है कि भारत में दहेज कुप्रथा का चलन किसी एक ही वर्ग, जाति या संप्रदाय के बीच है, बल्कि यह भारत में सभी प्रमुख धर्मों में प्रचलित है। हां, यह हो सकता है कि दहेज लेने और देने के स्वरूप में अंतर हो। ईसाई और सिख समाज में भी हिंदू और मुस्लिम समाज के जैसे ही दहेज लिया और दिया जाता है। कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रह गया है। हाल के दिनों में दहेज लेने और देने के नए तौर-तरीके भी निकाल लिए गए हैं। अब यह जरूरी नहीं रह गया है कि दहेज नकद की दिया जाए। वह जेवर, गाड़ी और प्रोपर्टी के रूप में कुछ भी हो सकता है। इस कुप्रथा के कारण ही एक पिता जीवन भर अपनी बेटी की शादी के लिए पूंजी जमा करता रहता है। उसे लगता है कि जब वह अच्छा दहेज देगा तो उसकी लड़की की अच्छे घर में शादी हो सकेगी। ऐसे में लड़की के अच्छे संस्कार, गुण-शील का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ दहेज का कि कितना लिया और कितना दिया।

निश्चित रूप से दहेज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बढ़ कर है। ऐसे में इसे खत्म करने के लिए समाज को मिलकर सामूहिक प्रयास करने ही होंगे। यह कुप्रथा एक सामाजिक बुराई है तो ऐसे में इसमें कानून, प्रशासन और सरकार की बहुत बड़ी भूमिका नजर नहीं आती है। इस बुराई को खत्म करने के लिए समाज में जन-जागरूकता लानी होगी और लोगों को यह अहसास कराना होगा कि यह अच्छाई नहीं, बल्कि बुराई है। जब लोग इस बात को समझने लगेंगे तो संभव है कि समय के साथ यह कुप्रथा धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विनाश का निमित्त बनता है अहंकार

'सत्ता के नशे में चूर शी चिनफिंग' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में विजय क्रांति ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के अहंकारी उद्बोधन और दिवास्वप्न को लेकर जो विश्लेषण किया है वह सत्यता के काफी करीब है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह में उनके द्वारा विश्व को दी गई चेतावनी उनके विनाश का कारण बन सकती है। वह जिस ताकत के बल पर चीनी जनता में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। वह यह तो जानते ही होंगे कि चीनी जनता या कम्युनिस्ट सेना उनकी दमनकारी नीतियों को सहज स्वीकार नहीं कर रही होगी। चीनी समाज भी विश्व के दूसरे लोगों की तरह एक खुले वातावरण में सांस लेने की इच्छा अवश्य रखता होगा। शी चिनफिंग यह भी अवश्य जानते ही होंगे कि अत्यधिक कठोरता या खिंचाव किसी भी वस्तु के टूटने में सहायक होता है। लचीलापन ही किसी वस्तु या व्यवस्था का चिर जीवन होता है। लेखक ने पूर्व सोवियत संघ एवं निकिता ख्रुश्चेव के मदांध बयान को लेकर जो कहा है वह चीन के संदर्भ में सत्य साबित हो सकता है। चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाया तभी आज वह एक वैश्विक ताकत बन पाया है। यदि उसने यह व्यवस्था न अपनाई होती तो आज वह सिर कुचलने जैसी बातें करने की स्थिति में नहीं होता। अपने आप को सर्वकालिक चीनी शासक बनाने की चिनफिंग की अभिलाषा हो सकती है, परंतु इसके लिए वह विश्व को एक बहुत बड़े संकट में डालने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। शेष विश्व से इस तरह शत्रुता पालकर वह अपने आपको कितने दिनों तक स्थिर रख पाएंगे, इस पर उन्हें अवश्य मंथन करना चाहिए। उस समय जनता भी उनके विरुद्ध होगी और सेना भी बंटी हुई नजर आएगी। अच्छा है कि चीन जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, वह मानव धर्म को स्वीकार करते हुए सभी के सुख की कामना करे। अति महत्वाकांक्षा सदैव पतन को ही आमंत्रित करती है।

डीडी सिंघल, फरीदाबाद

परहेज में भलाई

उत्तराखंड के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा रद किए जाने पर अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सामूहिक धार्मिक और राजनीतिक सभा से परहेज करना ही इस समय हितकर है। कांवड़ लेकर पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि कई प्रदेशों से आवागमन करने वाले भक्तों के सैलाब से कोरोना वायरस के सामाजिक संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अप्रैल महीने में आयोजित कुंभ मेले में शारीरिक दूरी और कोविड नियमों का पालन नहीं होने का खामियाजा दूसरी लहर के रूप में भुगतना पड़ा। हाल में ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के लिए आए कुछ सैलानियों ने भी कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन कर संक्रमण के खतरे को और बढ़ा दिया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं वर्तमान परिस्थितियों में सरकार व प्रशासन से टकराव मोल लेने के बजाय कांवड़ यात्रा से परहेज कर देशहित पर ध्यान दें।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री की नसीहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलिंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खिलाड़ियों से साफ कहा कि अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, वे केवल अपना बेहतरीन प्रदर्शन दें। 23 जुलाई से ओलिंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हम सब की यही मंगलकामना है कि हमारा देश खेलों की महाशक्ति के रूप में अपना स्थान स्थापित करे। 21वीं सदी का भारत इतना आत्मनिर्भर और विकसित हो रहा है कि उसने खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब जैसी खेल से जुड़ी मान्यताओं को भी उलट दिया है। उम्मीद है कि ओलिंपिक खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे।

हरीश कुमार शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

33 प्रतिशत वैट, साढ़े चार रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क और एक प्रतिशत सेस लगता है पेट्रोल पर मध्य प्रदेश में, जबकि 23 फीसद वैट, तीन रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क और एक प्रतिशत सेस लगता है डीजल पर इस राज्य में।

आजकल

सरकारी नौकरी के लिए साझा पात्रता परीक्षा

केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में कहा है कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए वर्ष 2022 से पूरे देश में केवल एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शुरू में रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आइबीपीएस) तथा कर्मचारी चयन आयोग जैसी तीन एजेंसियों की परीक्षा को कॉमन बनाया जा रहा है, जबकि आने वाले समय में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नई व्यवस्था वर्तमान बोझिल प्रक्रिया को आसान बना पाएगी। इस पहल से करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे जो वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं



कैलाश बिश्नोई
शोध अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय



भर्ती की नई व्यवस्था से खर्च के अलावा नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। फाइल

केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए प्रतियोगी छात्रों को में केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग लगभग 20 भर्ती बोर्डों की परीक्षाएं देनी होती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार की करीब सवा लाख वेकेंसी के लिए हर साल ढाई से तीन करोड़ छात्र आवेदन करते हैं। छात्रों को सामान्यतया केंद्र सरकार में एसएससी, बैंक और रेलवे जैसी परीक्षाओं में हर साल 10-15 फॉर्म अलग-अलग भरने पड़ते हैं। प्रत्येक बार युवाओं को तीन-चार सौ रुपये से लेकर आठ-नौ सौ रुपये तक की फीस भरनी पड़ती है। हर बार अलग-अलग प्रतियोगिता परीक्षा भी देनी पड़ती है। हर भर्ती की परीक्षा तिथियां अलग-अलग होती हैं और आवेदन प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है। कई बार एक से अधिक परीक्षाओं की तारीखें एक ही दिन पड़ने से अभ्यर्थियों को कोई एक एग्जाम छोड़ना पड़ता है। अक्सर यह देखने में आता है कि कई बार जब दो-तीन परीक्षा करानी होती है, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कई जगहों पर नकल की आशंका भी बढ़ जाती है। परीक्षा के दौरान केंद्रों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को अलग से अधिकारियों और पुलिस को तैनात करना पड़ता है। बार-बार परीक्षाएं होने से बार-बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ने के साथ-साथ भर्ती की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लंबे समय से ऐसी किसी भर्ती एजेंसी की मांग हो रही थी जो सभी नौकरियों के लिए कॉमन हो। इसके लिए अब सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है। लिहाजा यह ऐतिहासिक सुधार है जिसके जरिये भर्ती, चयन और नौकरी तीनों में आसानी होगी। इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जो दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। इसकी एक खासियत यह भी है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदत्त सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों आदि के साथ साझा किया जा सकेगा ताकि अन्य क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।

भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश : प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने की वर्तमान में जो व्यवस्था है, इसके तहत उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। इससे युवाओं का धन, श्रम और समय ज्यादा लगता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को काफी कठिनाई होती है। शहर में आकर रहने और आवाजाही के लिए उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, विभिन्न भर्ती बोर्डों को भी तारीखों का चयन करने में समस्या होती है, लेकिन अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आने से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। अब परीक्षाएं कम होंगी, तो उम्मीदवारों को तारीखों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस लिहाज से सरकार का एक कॉमन परीक्षा का कदम सराहनीय है। लेकिन सरकार को पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ही इस योजना को अमलीजामा पहनाना चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कहीं यूपीएससी परीक्षा में हिंदी बनाम अंग्रेजी जैसा विवाद न खड़ा हो जाए, कहीं मैथ्स या फिर अंग्रेजी भाषा को तरजीह का सवाल न खड़ा हो जाए, आखिर ये करोड़ों युवाओं के करियर का सवाल है।

भर्ती की नई व्यवस्था से उम्मीदवारों को मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने का तनाव नहीं होगा और वे आसानी से एक परीक्षा दे पाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं। वर्तमान में एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में एकरूपता नहीं होती है। यह परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षाओं और उनके अलग-अलग ढंगों के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी।

इस तरह परीक्षा की नई व्यवस्था से उम्मीदवारों के साथ-साथ विभिन्न भर्ती बोर्डों को लाभ होगा। इससे इनका पैसा और समय दोनों बचेगा। अगर कोई भर्ती बोर्ड एक साल में 20 परीक्षाओं का आयोजन करता है तो इसका मतलब है कि उसे 20 बार परीक्षा केंद्र बनाने पड़ते हैं। इसमें पैसा और समय दोनों अधिक लगता है। सीईटी से यह लाभ होगा कि भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाले मौजूदा तंत्र पर दबाव कम होगा। लेकिन खतरा यह है कि भर्ती एजेंसियों का दबाव कम करने की यह कवायद कहीं देश की नौजवान पीढ़ी पर दबाव और ज्यादा बढ़ा न दे। हमें इस मोर्चे पर विशेष सावधानी बरतना होगा। अच्छी बात यह है कि सीईटी द्वारा आयोजित परीक्षा में उम्मीदवार कितनी भी बार परीक्षा दे सकेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवार की आयु सीमा में भी कुछ छूट दे सकती है। यही नहीं, सीईटी काफी हद तक लंबे भर्ती चक्र को कम कर देगा, क्योंकि कुछ भर्ती विभागों ने अपने स्तर-2 या दूसरे स्तर की परीक्षा को छोड़ने का फैसला किया है। ये एजेंसियां प्रारंभिक स्तर की परीक्षा यानी सीईटी स्कोर के आधार पर भर्ती के लिए आगे बढ़ेंगी और उसके बाद शारीरिक परीक्षण व चिकित्सा परीक्षण होगा। इससे अभ्यर्थियों को नौकरी देने में लगने वाले समय में कमी आएगी और यह भर्ती चक्र को भी काफी कम करेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के पैटर्न में मानकीकरण भी आएगा।

इस सिस्टम से नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है। एक बात और, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी के साथ यह भी उचित होगा कि केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पड़े करीब सात लाख से अधिक पदों को समय रहते भरने में तत्परता का परिचय दिया जाए। इसके साथ ही स्वीकृत पदों को वास्तविक जरूरत के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को राज्य सरकारें अपने लिए अनुकरणीय उदाहरण समझें। कुछ ऐसा ही निर्णय उन्हें भी लेना चाहिए। वर्तमान में कुल सरकारी नौकरियों की बात करें तो केवल 14 प्रतिशत सार्वजनिक रोजगार केंद्र (मुख्य रूप से रेलवे और रक्षा में) के दायरे में आते हैं, जबकि शेष भर्ती परीक्षाएं राज्यों के दायरे में आती हैं।

नवगठित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनटीए केवल प्राथमिक स्तर (प्रारंभिक परीक्षा) की ही परीक्षा आयोजित करवाएगी, अर्थात इससे नौकरी के लिए इच्छुक प्रतियोगी छात्र केवल अगले स्तर की परीक्षा देने हेतु पात्र माने जाएंगे, न कि सीधे रूप से नौकरी मिल जाएगी। साथ ही, अभी भी विभिन्न भर्ती बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने से केवल प्रारंभिक परीक्षाओं से ही निजात मिली है, अगले चरण की परीक्षाओं के लिए आवेदन तथा परीक्षाओं में शामिल होने की जरूरत अभी भी रहेगी। यहां एक सुझाव यह है कि सरकार को अगले स्तर की परीक्षाओं को करवाने का जिम्मा भी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को सौंपे जाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके अलावा, ग्रुप सी तथा डी की सरकारी नौकरियों में बहुस्तरीय परीक्षा करवाने का विकल्प हटा देना चाहिए। इससे समय, धन और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती है। अगर इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाता है तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ कीमती समय और संसाधनों की भी बचत होगी।

निश्चित समयावधि में पूरी हो भर्ती की प्रक्रिया

पिछले कुछ वर्षों से लाखों युवाओं को नौकरी इसीलिए भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद दो-तीन वर्षों तक परीक्षा नहीं होती। मसलन 1.35 लाख पदों पर होने वाली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा के विज्ञापन को जारी किए हुए दो साल से अधिक वक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का पहला चरण भी पूरा नहीं हो पाया है। अजीब विडंबना है कि देश में या तो भर्ती वक्त पर नहीं निकलती, निकलती है तो परीक्षा होने में समय लग जाता है, फिर प्रतियोगी छात्र प्रवेश पत्र से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की मुसीबतों को झेलता है। फिर कभी पेपर लीक होने की खबर आ जाती है तो कभी धांधली की। कई बार परीक्षा से पहले ही सारे प्रश्न इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो जाते हैं।

हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जो दुर्गति है, उसका खमियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ता है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात, रिश्वत, रसूख, सिफारिश वगैरह का बोलबाला छिपी बात नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार की इंतिहा ने देश की शिक्षा व परीक्षा प्रणाली को मजाक बनाकर रख दिया है। वर्तमान में रोजगार की कमी युवाओं को पहले से ही बेचैन किए हुए है, ऊपर से चयन प्रक्रिया से उनका भरोसा भी उठ जाए तो इसके घातक नतीजे हो सकते हैं। आम लोगों में यह विश्वास या धारणा बन जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निराशाजनक है कि बिना सिफारिश के हमारे देश में सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। हालांकि केंद्रीय सेवाओं की नौकरियों के मुकाबले राज्यों के भर्ती आयोगों द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार होने की खबरें अधिक आती हैं।

एक सुझाव यह है कि नौकरियों में फर्जीवाड़ा करके युवाओं से छल करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए भी फास्ट ट्रैक अदालतों में मामले निपटा कर उन्हें तुरंत कड़ा दंड देने का प्रविधान किया जाए। एक नियम यह अवश्य बनना चाहिए कि किसी भी सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ यह तय हो कि भर्ती कितने समय में पूरी होगी। सरकार यह तो कड़ाई से सुनिश्चित कर ही सकती है कि परीक्षाएं समय पर हों, और जो छात्र परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले। आशा है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की मांगों पर ध्यान देंगी, ताकि आगे से सृजन वाली शक्ति रोजगार मांगने, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने और फॉर्म भरने के बाद नौकरियों के इंतजार में जाया नहीं होगी।

खरी-खरी

लहर में रोटी खोजती निगाहें

सुधीर कुमार चौधरी

इन दिनों जीवन लहरों पर सवार हो गया है। हर जगह लहर की ही चर्चा है। वायरस के कंधों पर सवार हो पहली लहर आई, जिसने जीवन में जहर घोल दिया। फिर दूसरी लहर मौत का कहर बनकर आ धमकी। अब तीसरी लहर की आशंका में सहमे हुए जीवन का सफर जारी है।

वो समय हवा हुए जब नदियों में लहरें उठा करती थीं। अब उनमें लहरें उठने लायक पानी बचा ही नहीं है। समुद्र की लहरें जरूर यदा-कदा तूफान पैदा कर देती हैं। लेकिन सागर से ज्यादा व्यापक लहरें राजनीति में उठा करती हैं। इन दिनों राजनीति कम लहरनीति ज्यादा हो रही है। सेवा करने से ज्यादा लहर पैदा करना राजनीति का उद्देश्य हो गया है। हर राजनीतिक दल का मकसद प्रत्येक वोटर के सीने में अपने पक्ष में लहर पैदा करना हो गया है।

हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार की भीषण लहर चली। इस लहर में कई दिग्गजों की कुर्सियां बह गईं तो कई की नैया मझधार से किनारे लग गई। उधर, विपक्ष हताशा, परिवारवाद, जनता से कटाव, छिछली भाषा जैसी लहरों पर सवार होकर गर्त से और गर्त में चला जा रहा है। इधर, जनता के भाग्य में तो महंगाई की लहर बदी है। इस लहर पर सवार होकर पेट्रोल-डीजल भी शतक मारने लगते हैं। आम आदमी की खाने की थाली तक इसमें डूबने लगती है। विकास की लहर उठने के दावे तो आजादी से अब तक बहुत किए जाते रहे हैं, लेकिन यह हमेशा अदृश्य ही रही। इसे केवल सरकारी चश्मा लगाकर ही देखा जाता रहा है। आम आदमी के हिस्से में कभी कोरोना की लहर आती है तो कभी उसे चुनावी लहर पर सवार कर दिया जाता है।

सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 23 हजार करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित कर दिया है। इसमें से इलाज के अभाव में दम तोड़ते आदमी तक कितना पहुंचेगा और कितना दुर्व्यवस्था का ब्लैक होल निगल लेगा, यह तय करना मुश्किल है। आम आदमी सचमुच परेशानी में है। बाहर कोरोना, महंगाई, राजनीति की लहर है और उसके भीतर भूख, भय, वेदना की लहर दौड़ रही है। इन लहरों से मुक्ति पाने का शाश्वत संघर्ष जारी है।

ट्वीट-ट्वीट

इतने कयास तो मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर भी नहीं लगे, जितने प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से बैठक को लेकर लग रहे हैं। कोई कहता है कि बैठक पंजाब के बारे में थी, तो कोई कहता है कि पवार को राष्ट्रपति बनाने के बारे में और कोई कह रहा है कि कांग्रेस में शामिल होंगे पीके।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

किसी भी देश को कोविड से इतना फायदा नहीं पहुंचा, जितना उसके जन्मदाता देश चीन को मिला है। कोविड बाद के दौर में चीन का निर्यात लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल जून में उसके निर्यात में 32.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney



भारत में तकरीबन रोज 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका में 11000, चीन में 44000, ऑस्ट्रेलिया में 9000, ब्राजील में 8000 और रूस में 5000 बच्चे रोजाना जन्म लेते हैं। इस लिहाज से भारत में साल भर के दौरान ढाई करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। क्या हम हर साल ढाई करोड़ रोजगार सृजित कर रहे हैं? जनसंख्या पर राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।

चित्रा त्रिपाठी@chitraaum

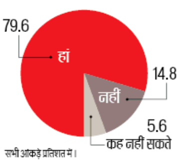
झरनों से इतना मधुर संगीत कभी सुनाई नहीं देता, अगर उनके रास्ते में पत्थर न होते।

रजत शर्मा@RajatSharmaLive

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तालिबान पर भरोसा न करने की भारत की नीति सही है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मौजूदा माहौल में कांवड़ यात्रा होनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

योगी जी की नीति से सहमत शरद पवार,
बेहतर होता है सदा छोटा ही परिवार।
छोटा ही परिवार सुखी जीवन की कुंजी,
रहे सुखी घरबार यही तो सच्ची पूंजी।
भले न समझें बात मानसिक जो हैं रोगी,
पर कहते हैं बात पते की हरदम योगी।

– ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

तंगहाल अर्थव्यवस्था ने बढ़ाई चुनौती



संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

कोरोना संकट ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। सरकार के पास विकास एवं कल्याण के बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए धन नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि सरकार का खजाना खाली है, लेकिन वह कोई भी जरूरी काम रुकने नहीं देंगे। वह बार-बार दोहरा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी राशि जुटाई जाएगी और कोई अन्य काम भी ठप नहीं होने पाएगा। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब खजाने में धन ही नहीं है तो विकास एवं कल्याण के कार्यक्रम संचालित होंगे तो कैसे?

दरअसल, कोरोना संकट की वजह से राज्य में राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। यही वजह है कि सरकार सिर्फ उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रही है जो बेहद जरूरी हैं और जो अर्थव्यवस्था को गति देने वाले हैं। चाहे किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दो-दो हजार रुपये जमा करना हो या फिर पथ विक्रेताओं को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता देनी हो, सरकार ने इसके लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सहित चिकित्सा संबंधी व्यवस्था को सरकार ने प्रभावित नहीं होने दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उपायों पर अब भी काम चल रहा है। लोक कल्याण के जरूरी कार्यों की गति भी सरकार बनाए रखना चाहती है, लेकिन यह सच है कि इसके लिए बड़े और कड़े निर्णय की जरूरत पड़ेगी।

राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस समय राजस्व संग्रह बढ़ाना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर



संकट काल में पेट्रोल-डीजल ही बना हुआ है सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया। फाइल

अतिरिक्त आय के उपायों पर जोर देने के लिए कह रहे हैं। प्रदेश पर ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। कोरोना संकट को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने करीब 55 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया था। केंद्र सरकार ने विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में दो फीसद अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी थी। इसमें करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपये बिना शर्त ऋण लेने की अनुमति मिली थी। शेष ऋण के लिए शर्तों को पूरा करना था, जिसे सरकार ने सबसे पहले पूरा किया है। इसमें 'वन नेशन वन राशन कार्ड' शुरू करने, बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार आदि शामिल हैं। सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए ऐसी अनुपयोगी परिसंपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की है जिन पर अतिक्रमण है और सरकार को कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। इसके तहत सड़क परिवहन निगम, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहित कई विभागों की परिसंपत्तियों को नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है। लोक निर्माण विभाग करीब 500 करोड़ रुपये का प्रबंध अपने स्तर से कर रहा है।

सरकार ने तय किया है कि विकास की गति सुधारने के लिए आर्थिक गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री लगातार उन विभागों की समीक्षाएं कर रहे हैं जिनसे राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व देने वाले विभागों की व्यवस्थाओं में सुधार करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। खनिज, आबकारी, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा सहित कई विभागों में सुधार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आबकारी में कर चोरी को रोकने के लिए भी 2021-22 की नीति में प्रविधान किए गए हैं।

संकट के समय में पेट्रोल-डीजल से होने वाली आय सरकार का सबसे बड़ा सहारा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की बात करें तो इस दौरान पेट्रोल-डीजल से सरकार को करीब 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। वर्ष 2020-21 में इससे 12 हजार 130 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2019-20 में यह राशि 10 हजार 806 करोड़ रुपये थी। मतलब यह कि एक साल के अंदर खजाने में 1,680 करोड़ रुपये का इजाफा पेट्रोल-डीजल के माध्यम से हुआ। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33 फीसद वैट, साढ़े चार रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क और एक फीसद सेस लगता है। डीजल पर 23 प्रतिशत वैट, तीन रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क और एक फीसद सेस लगता है। हालांकि इसे कम करने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन राज्य की सुरक्षित आय का सबसे बड़ा माध्यम होने की वजह से सरकार फिलहाल इसे कम करने के पक्ष में नहीं है।

वित्तीय संकट से निकलने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री ने आय बढ़ाने के साथ-साथ खर्चों में कटौती पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें करके विभिन्न स्तरों पर आवागमन में होने वाला व्यय कम किया है। आगे के लिए भी एक व्यवस्था बना दी गई है कि विभागीय बैठकों के लिए अब जिलों से अधिकारियों को भोपाल आने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की यह कोशिश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मददगार होगी।

हिमाचल प्रदेश डायरी

कहीं ये मानव निर्मित आपदा तो नहीं



नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

उसे खाना बनाना नहीं आता है, मैं ही कुछ देर के लिए दुकान छोड़ कर घर जाता हूं। कांगड़ा जिले की मनोरम वादी बोह के तहत रुलेहड़ पंचायत में एक दुकानदार सुभाष ने तीन दिन पहले ऐसा कहा और घर की तरफ निकल गए। वहां उनका पुत्र शिव कुमार खाना बनाने पहले ही गया था। खाना तो नहीं बना, अचानक ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट कर आ गिरा हो। बुधवार को 32 साल के शिव कुमार का शव मलबे से निकाला गया है। उसके पिता सुभाष अब तक लापता हैं। शिव कुमार का दो साल का अबोध पुत्र श्मशानघाट पर था, प्राकृतिक आपदा की समझ से दूर। घर के बाकी लोग इसलिए बचे, क्योंकि शिव कुमार की पत्नी को प्रसव के लिए डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में दाखिल करवाया था।

मैक्लोडगंज से सटे भागसूनाग में जिस तरह पानी ने रौद्र रूप दिखाया और वाहन बहाए, वह रहस्य नहीं है। नदियों के किनारे बने घर जिस तरह लापता हुए हैं, वह भी छिपा नहीं है।

क्या 'प्राकृतिक आपदा' इसके लिए ठीक शब्द है? दरअसल, नदी, पहाड़ और पेड़ के मन में झांकना सबसे सरल कार्य है और त्रासदी यह है कि इसी से हर पक्ष बचता है। पक्ष कौन हैं? एक पक्ष है जिसे नदी के किनारे घर बनाना है, कुछ जमीन सरकार की कब्जानी है। एक पक्ष वह है जिसे नालों का रास्ता रोक कर अपनी ताकत दिखानी है। एक पक्ष वह है जिसके सामने छोटी पहाड़ी नहरों, नालों पर कब्जा होता है और वह कई कारणों से चुप रहता है। एक पक्ष वह है जिसे नियोजन करना है, लेकिन फाइलें हमेशा 'सब ठीक है' कहती हैं। एक पक्ष को कोरोना काल में भी पहाड़ देखने हैं। एक पक्ष वह है जिसे जितने पेड़ विकास के लिए कटे, उतने पौधे रोपने की फुर्सत नहीं है।

भूकंप को प्राकृतिक आपदा में गिना जाए। चार अप्रैल, 1905 का भूकंप क्या कम था सिखाने को? एक शताब्दी पहले तो घर भी उतने नहीं रहे होंगे, भवन निर्माण शैली पर कंक्रीट का कब्जा उतना नहीं रहा होगा। पिछली शताब्दी क्यों, वर्ष 2000 के बाद की आपदाएं कम थीं सिखाने के लिए? हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष एक से डेढ़ हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। जनहानि अलग है और मवेशी कितने बहते हैं, यह अलग। वर्ष 2005 में सतलुज में आई बाढ़ पारछू झील से जोड़ी जाती है, क्या उसे कोई भूल सकता है? फिर नदियों, नालों और खड्डों के किनारे घर बनाने वाले कौन हैं, जिन्हें यह आपदा प्राकृतिक प्रतीत होती है? वर्ष 2015 में 68, वर्ष 2016 में 24 और वर्ष 2017 में 289 लोग बाढ़ या भूस्खलन की जद में आए थे। बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। गज खड्ड ने जिस प्रकार अपना रुख बदला और पुल को ध्वस्त कर पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित किया है, वह केवल उदाहरण है। ऐसा क्यों हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही अवैध खनन का हिसाब रखना पड़े? आखिर प्रदेश में अपने भी कुछ निगरानी प्रतिष्ठान हैं। ऊना में स्वां या सोमभद्रा का दुख दिल्ली के बजाय, ऊना और शिमला में भी तो सुना जा सकता है। वर्ष 2017 का मंडी जिले में कोटरोपी हादसा कैसे भुलाया जा सकता है, जहां करीब 50 लोग बसों समेत मलबे में बह गए थे। सवाल यह है कि सीखा क्या? भला हो आइआइटी मंडी का जिसके विद्यार्थियों ने पहाड़ पर सेंसर लगा दिए हैं। जब भी मलबा गिरने लगता है, चेतावनी मिल जाती है।

प्रदेश का आपदा प्रबंधन प्रस्ताव इतना प्रभावशाली था कि एक समय अन्य राज्यों से कहा गया था कि इससे सीख लें, इसे अपने यहां भी लागू करें। अब भी है जो बादल फटने, भूस्खलन होने और बर्फ को हटाने में दिखता है, लेकिन जब तक पूर्व आपदा प्रबंधन स्कूली पाठ्यक्रम के विषय के रूप में बचपन से नई पौध को नहीं समझाया जाएगा, तब तक कोई अपेक्षा करना बेमानी है। खड्डों में उतर कर सेल्फी लेने वाले अब भी हैं, जबकि कुछ वर्ष पहले ही तेलंगाना के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का ब्यास नदी में बह जाना इतनी छोटी घटना भी नहीं थी। रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना के किनारे से ऐसी कितनी सूचनाएं बरसात के मौसम में विचलित करती हैं, इसका सरकारी आंकड़ा भी होता है। लेकिन अब भी भीड़ देखी जा सकती है। एक सर्वेक्षण



कांगड़ा के भागसूनाग क्षेत्र में पानी ने अपना रास्ता कुछ इस तरह बनाया। जागरण आर्काइव

यह भी हो जाए कि कितने राजमार्ग कई कस्बों से जब गुजरते हैं तो नाराजमार्ग प्रतीत होते हैं। एक सर्वेक्षण यह भी हो कि कितने घरों की नींव के पत्थर पानी को रोक कर जमे हैं।

एक विभाग का नाम शहरी विकास मंत्रालय है। इसी के साथ नगर नियोजन भी नत्थी है। वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं को अप्राकृतिक बनाने से बचना है, तो यह जरूरी है कि मतदाताओं को रिटेंशन पालिसी के लोभ से दूर रखें। पहले मानकों को ताक पर रख दें और बाद में उसके नियमन के लिए गुहार लगाएं, यह दलील प्रकृति नहीं सुनती। प्रकृति को कब्जे हटाने आते हैं। शिमला हो या धर्मशाला, मैक्लोडगंज हो या मनाली, ढलानदार जमीन पर कंक्रीट का जंगल खड़ा करने से पहले यह अवश्य विचारना चाहिए कि लोग भूकंप से नहीं, मलबे में दब कर मरते हैं। याद रखें कि यह क्षेत्र संवेदनशील है। जिस शिमला के रिज मैदान में वर्षों से आई दरार के लिए रुड़की के इंजीनियर योजना बना रहे हैं, उसी शिमला की आपस में सटी इमारतों की तस्वीर डराती है। हिमाचल प्रदेश वास्तव में हरियाली के लिए जाना जाता शांत प्रदेश है जिसके पर्यटन को बागवानी के साथ मिल कर खुशहाली के रास्ते खोलने हैं। हादसे बता कर नहीं आते, लेकिन ऐसा भी न हो कि कहीं हादसों के लिए हर पक्ष स्वयं जमीन तैयार कर रहा हो। काबिल अजमेरी का कहा याद आ रहा है :

वक्त करता है परवरिश बरसों
हादसा एकदम नहीं होता।

1.25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन जेनरेशन पायलट प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी है लेह में। पर्यावरण बचाने के लिए लद्दाख में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग होगा। आम लोगों को भी मिलेगी ग्रीन एनर्जी।

बंगाल

राज्य में भाजपा के तीखे तेवर

ममता बनर्जी सरकार की ओर से बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष पद मुकुल राय को बैठाए जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के तेवर काफी तीखे होते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने विधानसभा की आठ समितियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों के एक दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलकर पूरी हालत की जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विधानसभा के अंदर और बाहर गणतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इसके खिलाफ वे लोग जल्द ही राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। इस्तीफा और संवैधानिक प्रमुख से मुलाकात यह बताने को काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मुकुल राय के मसले पर चुप नहीं बैठने वाला है। सुवेंदु अधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मुकुल राय के खिलाफ यदि दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि वह भाजपा के विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना ही तृणमूल में शामिल हो गए और ममता सरकार उन्हें पीएसी के अध्यक्ष पद पर बैठा दिया। राज्य सरकार के लेखा और वित्त के खर्चों पर पीएसी नजर रखती है। विधानसभा से लेकर संसद तक में यही परंपरा रही है कि सरकार के कामकाज पारदर्शी रहे इसके लिए पीएससी का अध्यक्ष पद विरोधी दल के विधायक एवं सांसद को दिया जाता है। परंतु वर्ष 2016 से इस परंपरा को ममता सरकार ने तोड़ते हुए अपने ही किसी नेता को उस पर बैठा दे रही हैं। यह हमारे देश की गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि कोई सरकार इस तरह अपने नेता को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त कर देगा तो फिर उसकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? उसके कामकाज और खर्चों की पारदर्शी तस्वीर तो जनता के समक्ष कभी आएगी ही नहीं।

> इस्तीफा और संवैधानिक प्रमुख से मुलाकात यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मुकुल राय के मसले पर चुप नहीं बैठने वाली है

उल्लेखनीय है कि पारदर्शिता लोकतंत्र की जान होती है। इस पर ममता बनर्जी सरकार को विचार करना चाहिए। भले ही थोड़ी देर के लिए इसे अपनी जीत मान कर खुश हुआ जा सकता है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। क्योंकि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक पार्टी की हर समय राज्य या फिर देश में सरकार नहीं रह सकती है। अगर ममता सरकार की तरह ही हर दल की सरकारें ऐसा करने लगेंगी तो इससे अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि सत्तारूढ़ दल को वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए। अन्यथा गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है।

पंजाब

हड़ताल से हलकान जनता



हड़ताल के कारण जनता को मिलने वाली सेवाएं नहीं होनी चाहिए प्रभावित। फाइल

> हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना होगा। सरकार को भी वाजिब मांगों पर तत्काल विचार करना चाहिए

प्रदेश में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की सरकार से नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की ओर से आए दिन की जा रही हड़ताल से आम जनता त्रस्त है। कभी परिवहन विभाग के कर्मचारी बस सेवा ठप कर देते हैं तो कभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। मिनिस्टीरियल स्टाफ और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आम जनता की मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई हैं। इस माह मिनिस्टीरियल स्टाफ की हड़ताल के कारण डीसी दफ्तरों में जनता का कोई काम नहीं हो सका है। अनेक लोग बड़ी उम्मीद के साथ दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन निराश होकर लौट जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में इस माह अब तक पांच दिन ओपीडी सेवाएं बंद हो चुकी हैं। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय तक ओपीडी सेवाएं पहले से ही बंद थीं। पिछले माह शुरू हुईं तो कुछ राहत मिली, लेकिन अब फिर से मरीज परेशान हैं। ज्यादातर विभागों के कर्मचारी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर नाराज हैं। डॉक्टरों ने तो धमकी दे दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 19 जुलाई से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और आपातकालीन सेवाएं भी ठप कर सकते हैं। नगर निगम, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कर व आबकारी आदि विभागों में जब हड़ताल की वजह से काम प्रभावित हो रहा है तो प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

सरकार को यह भी समझना होगा कि अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि कर्मचारियों की नाराजगी दूर नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और ज्यादा होंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक आने पर ऐसा होता ही है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कर्मचारी संगठनों के साथ बात करके वाजिब मांगें मानने का भरोसा दिया जाना चाहिए। हड़ताल करने वालों के लिए भी अड़ियल रवैया छोड़कर सरकार के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना ही बेहतर रहेगा। उनको अपने हित के साथ परेशान हो रही जनता के बारे में भी सोचना होगा। समझना होगा कि अधिकारों की लड़ाई लड़ने के साथ ही अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।

उत्तर प्रदेश

छोटे अपराधों पर नियंत्रण



घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को दिखानी होगी गंभीरता। फाइल

> पुलिस का असल इकबाल तभी स्थापित हो पाएगा, जब उसका मुखबिर तंत्र मजबूत होगा और वह छोटी-छोटी सूचनाओं पर तत्काल सक्रियता भी दिखाएगी

कानून-व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा है। होना भी चाहिए क्योंकि सामान्य आदमी का इसी से सीधा वास्ता रहता है। उसे इससे बहुत मतलब नहीं कि किसी माफिया पर क्या और कैसी कार्रवाई हुई। यद्यपि माफिया पर शिकंजा भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वह बड़े फलक पर समाज विरोधी षड्यंत्र रचकर ही धन-संपदा जुटाता है। इसलिए माफिया को समाप्त करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी छोटे-मोटे झगड़े और अपराधों को रोकना भी है। नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकुल गोयल भी मानते हैं कि छोटे अपराधों को काबू किया जाना अधिक आवश्यक है क्योंकि वे कानून व्यवस्था पर बड़ा असर डालते हैं। 90 फीसद जनता इन्हीं घटनाओं से प्रभावित होती है, पर अभी अधिकांश जिलों की थाना पुलिस छोटे अपराधों को बहुत महत्व नहीं दे रही। उसका जोर अपराध रोकने से ज्यादा छिपाने पर रहता है। सरेराह हुई लूट को भी वह चोरी या गुमशुदगी में दर्ज कराने का दबाव बनाने से नहीं हिचकती।

वैसे अपराधों पर पुख्ता नियंत्रण और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के चार जिलों (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतमबुद्ध नगर) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी है। राज्य सरकार का यह निर्णय बेहतर रहा और इससे पुलिस के अधिकार तो बढ़े ही हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या भी अधिक हुई है। फिर भी कमिश्नर प्रणाली अभी अपने शैशवकाल में ही है। वहीं सरकार ने बेहतर पुलिसिंग के लिए अब सब इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज देने का निर्णय ले लिया है। इससे तेज-तर्रार दारोगा भी थानेदार बन सकेंगे। हालांकि पुलिस का असल इकबाल तभी स्थापित हो पाएगा, जब उसका मुखबिर तंत्र मजबूत होगा और वह छोटी-छोटी सूचनाओं पर तत्काल सक्रियता भी दिखाएगी। ऐसे भी उदाहरण हैं, जबकि पुलिस ने कोई बात मामूली मानकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई और बाद में इसी कारण बवाल हो गया। अगर छोटी वारदात की रोकथाम पर पुलिस गंभीरता दिखाए तो अधिकांश घटनाएं बड़ा रूप ले ही नहीं सकतीं।

उत्तराखंड

संक्रमण रोकने के लिए उचित निर्णय

उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आ रही कमी और तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने उम्मीद के मुताबिक कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू में तमाम तरह की ढील पहले ही दी जा चुकी हैं, इस बार पर्यटक स्थलों पर बढ़ रही भीड़ के मद्देनजर सप्ताहांत में कोविड कर्फ्यू को लेकर निर्णय का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है। यह निर्णय व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। वजह यह है कि प्रत्येक जिले का भूगोल और वहां का सामाजिक व्यवहार अलग-अलग हैं। इतना ही नहीं पर्यटकों की तादाद अलग-अलग पयर्टक स्थलों पर एक जैसी नहीं है। मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में सैलानियों की आवाजाही अन्य इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा है। ऐसे में जिलाधिकारी ज्यादा कारगर तरीके से कोविड कर्फ्यू को लेकर फैसला कर पाएंगे। पिछले दिनों उत्तराखंड में जिस प्रकार सैलानियों का सैलाब उमड़ा उसने उच्च न्यायालय से लेकर केंद्र सरकार तक की चिंता बढ़ा दी। इससे प्रदेश का आम जन भी सहमा हुआ है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई सामाजिक संगठन भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश भर के विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में इस चिंता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पिछले दिनों सरकार ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए होटल की बुकिंग के साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया। नई मानक प्रचालन विधि (एसओपी) के अनुसार अब जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में इस मामले में फैसला कर सकेंगे। जरूरत यह है कि वे बिना किसी दबाव में आए स्थितियों का विश्लेषण कर फैसला करें और राजनेताओं का भी दायित्व है कि हालात के अनुसार प्रशासन का सहयोग करें। तस्वीर के एक और पहलू पर गौर करने की जरूरत है। सरकार ने एसओपी तो जारी की है, लेकिन उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना आवश्यक है। एसओपी के अनुसार उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच जरूरी है, लेकिन राज्य की सीमाओं पर इसकी पुख्ता व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी आए हैं कि लोग फर्जी रिपोर्ट दिखाकर राज्य में प्रवेश कर गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार पर्याप्त इंतजाम करेगी। इसके अलावा जो पर्यटक दी गई कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं, उनको कोई परेशानी न हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

> सप्ताहांत में कोविड कर्फ्यू को लेकर सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्णय लेने का अधिकार देकर व्यावहारिक फैसला किया है

बिटिया को कहानी ऐसी भायी, शब्दों की जादूगर बन गई माई

शाहजहांपुर की आशा शुक्ला लिख चुकीं हैं 185 कहानियां, मोबाइल एप के जरिये लाखों पाठकों तक पहुंचाईं रचनाएं

जागरण विशेष

अंबुज मिश्रा • शाहजहांपुर



आशा का परिवार। प्रथम पंक्ति में (बायें से) पिता श्याम नारायण अवस्थी, आशा शुक्ला व उनके पति बृज किशोर शुक्ला। पीछे खड़े बेटे-बेटियां • जागरण

दुल्हन के जोड़े में आशा ससुराल पहुंचीं तो, उम्र थी सिर्फ 15 साल। किताब-कापियों के पन्ने इतने ही पलटे थे कि चिट्ठी-पत्री पढ़ लेती थीं। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं रही। परंतु, पढ़ाई की लगन थी तो एक रास्ता खुला। तीन साल पहले बिटिया ने एक आइडिया दिया। बस, यहीं से जीवन में नई आशा जागी और 30 माह में सफलता की नई कहानी लिख चुकी हैं। वह 177 कहानियां साहित्य से जुड़े एक मोबाइल एप के लिए लिख चुकी हैं। 48.61 लाख लोग उनकी रचनाओं को आनलाइन पढ़ चुके हैं। आठ पुस्तकें एक वेबसाइट पर बिक्री के लिए आ चुकी हैं।

शाहजहांपुर के बंथरा गांव की आशा आठवीं तक पढ़ सकी थीं, तभी पिता ने शादी तय कर दी। 1987 में हरदोई के बृजकिशोर शुक्ला से शादी हो गई। कुछ साल बाद पति को व्यापार में घाटा हुआ तो नौकरी करने दिल्ली चले गए। पिता श्याम नारायण अवस्थी के कहने पर आशा चार बच्चों को लेकर मायके आ गईं।

चार बच्चों की परवरिश के साथ फिर शुरू की पढ़ाई: मायके आने के बाद आशा को लगा कि बिना पढ़ाई जिंदगी में अंधेरा है। ऐसे में नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया। सुबह स्कूल जातीं, दोपहर से बच्चों को संभालती थीं। आशा का साथ उनके पति और पिता दे रहे थे। स्नातक तक की शिक्षा की सीढ़ी वह चढ़ती गईं। इस दौरान कहानी पढ़ने का शौक लग गया। 2018 की बात है, बड़ी बेटी दामिनी स्नातक कर रही थी। उसे क्लास के प्रोजेक्ट में कहानी लिखते देखा, उसे सुधारने लगीं। बेटी ने कहानी की दिशा बदली देखी तो बोली- मां, क्यों न तुम कहानी लिखो। बात पसंद आई। बेटी ने मोबाइल पर 'प्रतिलिपि' एप दिखाया। उसी साल पांच दिसंबर को आशा ने बेटी की जिद पर कहानी लिखकर अपलोड कर दी। इसमें उन्होंने जिंदगी के अपने अनुभव लिखे, जिसे खूब पसंद किया गया। इसके बाद यह पन्ना आगे खुलता गया।

वेबसीरीज के लिए चल रही चर्चा

प्रतिलिपि एप आशा की 35 कहानियों के अधिकार ले चुकी है। सेना के शहीद जवान की पत्नी के जीवन के संघर्ष पर उन्होंने कहानी लिखी-छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। दिल्ली के भावना प्रोडक्शन ने वेबसीरीज बनाने के लिए एक महीने पहले संपर्क किया था। टीम उनसे मिलने घर आई थी। आशा कहती हैं, इसको लेकर प्रोडक्शन हाउस से बातचीत चल रही है।

रोज चार-पांच घंटे लेखन: इस बीच पति बृजकिशोर दिल्ली से लौट आए। आशा अब रोज चार-पांच घंटे लेखन करती हैं। शहादत एक इबादत, जिद जीत की, दो टूक जिंदगी कविताएं साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। दहेज प्रथा व बेमेल शादी पर उपन्यास 'जल बिच मीन प्यासी प्रकाशित होने वाला है।

इस तरह आते हैं विचार: आशा की कहानियों के विषय आम जीवन से जुड़े होते हैं। एक छात्रा को केरोसिन डालकर जलाने की घटना पर उन्होंने कहानी लिखी-गुनाहगार कौन। जातिप्रथा पर भी लिख चुकी हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर भी लिखा है। आशा की कहानियां 30 पुरस्कार जीत चुकी हैं। पति बृजकिशोर कहते हैं कि वह जब भी बाहर जाते, उनके लिए साहित्यिक पुस्तक जरूर लाते हैं। उनकी सफलता पर गर्व है।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

हर गांव में संघ के होंगे तीन-तीन प्रशिक्षित कार्यकर्ता

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

चित्रकूट में चिंतन

- 2025 से पहले योजना पर होगा अमल, जमीन पर काम के लिए मंथन
- मध्य क्षेत्र के क्षेत्र व प्रांत प्रचारकों ने कई दौर की चर्चा की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हर गांव में तीन-तीन प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करेगा। इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। वैसे, इसे शताब्दी वर्ष में पूरा करना है, लेकिन काम बड़ा माना जा रहा है, इसलिए गहनता से विचार-विमर्श हो रहा है।

चित्रकूट में मध्य प्रदेश के सतना जिला अंतर्गत दीनदयाल शोध संस्थान के प्रकल्प आरोग्यधाम में मध्य क्षेत्र (महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्य भारत व मालवा प्रांत) के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य से साथ बैठक में बुधवार को क्षेत्र व प्रांत प्रचारकों ने साल भर की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया। इसमें गांव स्तर पर तीन-तीन कार्यकर्ता तैयार करने पर सहमति बनी। यह काम कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के पहले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। इसलिए संघ की शाखा विस्तार और गांव स्तर पर कार्यकर्ता बनाने को कैसे जमीन में उतरकर काम हो, इसके लिए प्रांत प्रचारकों ने कई दौर की चर्चा की है। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि अखिल भारतीय कमेटी की बैठक में जो निर्देश दिए जाते हैं, उनको लेकर ही क्षेत्र के पदाधिकारी अनुपालन बैठक करते हैं। चित्रकूट मध्य क्षेत्र का अंग है। अखिल भारतीय बैठक में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। इसलिए क्षेत्र की बैठक यहां पर ही कर ली गई है। क्षेत्र की योजना तैयार की जा रही है। गुरुवार को भी बैठक होगी।

गुरुग्राम में लगी देश की पहली ग्रेन एटीएम

प्रयोग

- बैंक एटीएम के जैसे करेगा काम, अगूंठा लगाकर मशीन से निकलेगा अनाज
- प्रयोग सफल रहा तो हरियाणा के दूसरे जिलों में भी लगेंगी मशीनें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

अब सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को न तो लंबी कतार में लगना होगा और न ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन एटीएम स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया गया है।

जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता ओर राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी है। चौटाला का कहना है कि ग्रेन एटीएम लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस मशीन को लगाने का मकसद 'राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी' है। यानी वास्तविक लाभपात्रों को अनाज की पूरी मात्रा मिले और समय से हासिल हो। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपो पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा। सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। चौटाला ने बताया कि ये मशीनें न सिर्फ डिपो संचालकों के लिए अनाज वितरण में सहायक साबित होंगी, बल्कि इससे उनका समय भी बचेगा। गुरुग्राम जिले के फर्रुखनगर में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इन अन्न आपूर्ति मशीनों को प्रदेश भर में सरकारी डिपो पर लगाने की योजना है।



गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम से राशन निकालती महिला। सौ. जजपा कार्यालय

ऐसे काम करती है ग्रेन एटीएम : यह स्वचालित मशीन बैंक एटीएम की तर्ज पर कार्य करती है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की जानी वाली इस मशीन को आटोमेटिड, मल्टी कमोडिटी, ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा गया है। इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी अंकित सूद का कहना है कि अनाज के मापतोल को लेकर इसमें त्रुटि न के बराबर है और एक बार में यह मशीन 70 किलोग्राम तक अनाज पांच से सात मिनट में निकाल सकती है। मशीन में लगी टच स्क्रीन के साथ बायोमीट्रिक मशीन भी लगी है, जहां पर लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। बायोमीट्रिक से सुनिश्चित करने पर सरकार द्वारा निर्धारित अनाज स्वतः मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भर जाएगा। इस मशीन के माध्यम से गेहूं, चावल और बाजरे का वितरण किया जा सकता है। फिलहाल फर्रुखनगर में स्थापित ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू कर दिया गया है।

राजीनामे के आधार पर महिला को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते

अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को पिता की संपत्ति में हिस्से के उसके अधिकार से महज ऐसे राजीनामे के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता जिस पर उसने अपना अधिकार छोड़ने के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हों।

जस्टिस एवाई कोजे की पीठ ने भावनगर की महिला रोशन डेराइया की याचिका पर यह आदेश दिया। रोशन ने जिला प्रशासन के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने राजीनामे को स्वीकार करते हुए जमीन के राजस्व रिकार्ड में उनका नाम शामिल करने से इन्कार कर दिया था। रोशन व उनकी बहन हसीना ने अक्टूबर, 2010 में पिता की मृत्यु से पहले उनके समक्ष राजीनामे पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने जमीन के अपने हिस्से पर अधिकार तीन भाइयों के समर्थन में छोड़ दिए थे। इसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड से उनके नाम बाहर कर दिए गए थे। पिता की मृत्यु के बाद जमीन याचिकाकर्ता के भाइयों के नाम पर हस्तांतरित की गई तो उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से संपर्क किया और उस राजीनामे के आधार उनका नाम राजस्व रिकार्ड से बाहर करने पर सवाल उठाया जिस पर उन्होंने पिता के जीवित रहते हस्ताक्षर किए थे। लेकिन डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, देरी के आधार पर राजस्व विभाग ने भी जून, 2020 में उनकी अपील ठुकरा दी। सोमवार को उपलब्ध कराए गए आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि मृत्यु के बाद जमीन पर पिता के हिस्से के उत्तराधिकार के लिहाज से याचिकाकर्ता के अधिकार की पड़ताल की जानी चाहिए थी।

आरएसएस को नजदीक से जाना तो पादरी से बन गए संघ के प्रचारक

संजय कुमार, रांची

- 1984 में भारत आए थे राबर्ट सॉलोमन, बुंदेलखंड के उरई जिले में हुई थी पहली पदस्थापना
- मतांतरण के काम में लगे सॉलोमन ने आरएसएस के काम को जाना तो दूर हो गई सारी गलतफहमी
- हिंदू दर्शन व चिंतन से प्रभावित होकर स्वयं बन गए सुमन कुमार

कभी मतांतरण के काम में लगे पादरी राबर्ट सॉलोमन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा व पदाधिकारियों से मिले प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि संघ प्रचारक बन गए। नाम मिला डा. सुमन कुमार। संघ ने भी इंडोनेशिया से भारत भेजे गए पादरी को अपनाया।

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्गेनिक रसायन में शोध के दौरान ही डा. सुमन कुमार पादरी बन चुके थे। 1982 से उनका चेन्नई आना-जाना शुरू हुआ। 1984 में ईसाई मिशनरियों ने उन्हें भारत भेज दिया। तब उनकी उम्र 25 वर्ष थी। उनकी पहली पदस्थापना बुंदेलखंड के उरई जिले में हुई। दैनिक जागरण से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके घर के पास ही संघ की शाखा लगती थी। तभी वह उप्र के क्षेत्र प्रचारक जयगोपाल और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के संपर्क में आए।

तीन महीने में ही मिशनरी को भेज दी रिपोर्ट: डा. सुमन कुमार बताते हैं कि मेरे साथ भाषा की समस्या थी इसलिए संघ के विचारों को गहराई से समझने में परेशानी हो रही थी। विहिप के संगठन मंत्री ओंकार भावे ने अंग्रेजी में लिखी संघ की पुस्तकें दीं। स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा और तीन माह में ही मिशनरी को रिपोर्ट भेज दी।

मंतातरण के बदले राष्ट्रांतरण हो जाता है: सुमन कुमार ने बताया भारत भेजने से पहले बताया गया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के लोग चर्च को तोड़ देते हैं। बाइबिल जला देते हैं। पादरियों पर हमला करते हैं, परंतु मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तब मिशनरियों को भेजी गए अपनी रिपोर्ट में मैंने लिखा कि जिनका आप मतांतरण कराते हैं उनका राष्ट्रांतरण हो जाता है। ईसा मसीह का प्रचार करो परंतु मतांतरण मत करो।

कानपुर में गुजरा लंबा वक्त

- वर्ष 1986 में गोरखपुर में हुई प्रचारक बैठक में संघ प्रचारक घोषित किया गया। हिंदू जागरण मंच की भी जिम्मेदारी दी गई।
- कानपुर के करवालो नगर कार्यालय में रहकर काम किया। संभाग प्रचारक रामशीष, सह प्रांत प्रचारक बालकृष्ण त्रिपाठी ने मदद की।
- यहीं रहते हुए हिंदू जागरण मंच का महानगर, विभाग, संभाग एवं प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व संभाला।
- वर्ष 2000 में अवध प्रांत के संगठन मंत्री बने और कार्यक्षेत्र का केंद्र प्रदेश की राजधानी लखनऊ था।
- वर्ष 2004 में सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने झारखंड भेजा और प्रांत के संगठन मंत्री बने।
- वर्ष 2015 से बिहार-झारखंड के संगठन मंत्री के बतौर संघ का काम संभाल रहे हैं।

कार्डिनल से मिली चुनौतियों का किया सामना



डा. सुमन कुमार। जागरण

सुमन कुमार बताते हैं कि जब मैं झारखंड आया तो सिमडेगा व गुमला में तेज गति से मतांतरण चल रहा था। रांची के ओरमांझी में आदिवासी जमीन पर बनाए जा रहे चर्च को ध्वस्त करवाया। जनजातियों को बताना शुरू किया कि सरना और सनातन एक मां के पुत्र हैं। अब तक 8000 लोगों की घर वापसी करवा चुका हूं।

संघ प्रचारकों ने पुत्र की तरह रखा

आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डा. अशोक वार्ष्णेय कहते हैं कि सुमन कुमार को उस समय के प्रचारकों ने पुत्र की तरह पाला। हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री ठाकुर रामगोविंद सिंह तो उनको पुत्र मानने लगे थे। वर्तमान अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन से उन्हें भाषा सीखने में मदद मिली।

1.05 करोड़ एशियाई मूल के लोग थे अमेरिका में वर्ष 2000 में। 2019 में इनकी संख्या 1.89 करोड़ हो गई। वर्ष 2060 तक इनकी संख्या 3.58 करोड़ होने का अनुमान है।

तालिबान ने पाक सीमा पर व्यापारिक शहर पर किया कब्जा

अफगानिस्तान में संघर्ष ▸ अहम है यह शहर, हर रोज 900 ट्रकों की आवाजाही, दूसरे शहरों पर भी नियंत्रण के लिए तालिबान ने तेज की जंग

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान में तालिबान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान को जाने वाले अहम राज मार्ग और पाक सीमा से लगे व्यापारिक शहर स्पिन बोल्डक पर उसका कब्जा हो गया है। इसके साथ ही कंधार, तालुकान, कुंदुज, काला-ए-नव जैसे शहरों पर कब्जे के लिए उसने संघर्ष तेज कर दिया है।

तालिबान ने कहा, पाकिस्तान आने-जाने वाले अहम रास्ते और सीमा के व्यापारिक शहर स्पिन बोल्डक पर उसका नियंत्रण हो गया है। इस व्यापारिक शहर से राजमार्ग के जरिये पाक का रास्ता है। यहां से हर रोज सीमा पार नौ सौ से ज्यादा ट्रकों की आवाजाही होती है। दोनों देशों के बीच व्यापार के लिहाज से यह महत्वपूर्ण शहर है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने व्यापारिक शहर पर कब्जे की पुष्टि की है। वही, अफगान सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। जनता का कहना है कि दोनों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। यह कहना मुश्किल है कि किसका कब्जा हो गया है। यह शहर कंधार प्रांत में आता है। जानकारों का मानना है कि तालिबान के कब्जे से अफगान सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी हानि होगी।

आइएएनएस के अनुसार तालिबान ने कई प्रांतों की राजधानी की भी घेराबंदी कर ली है। कंधार शहर पर संघर्ष जारी है। ताखर प्रांत की राजधानी तालुकान, कुंदुज प्रांत की राजधानी कुंदुज और बादगीस प्रांत की राजधानी काला-ए-नव पर दोनों ओर से भीषण संघर्ष चल रहा है। गजनी को लेकर भी घमासान जारी है। कंधार में छोटे बच्चे भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। मीरवाइज अस्पताल के एक डाक्टर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 घायल लोग आए हैं। इनमें नौ बच्चे हैं। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि तालुकान शहर पर कब्जा करने का तालिबान का प्रयास विफल हो गया है। यहां 12 आतंकियों के शव छोड़कर तालिबानी आतंकी भाग गए हैं। तालिबान ने बामियान और गजनी प्रांत के तीन जिलों पर कब्जा कर लिया है।

दोहा में तालिबान और अफगान सरकार में वार्ता : एपी के अनुसार कतर की राजधानी दोहा में एक बार फिर तालिबान के साथ अफगान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता शुरू होने वाली है। इस वार्ता में अफगान सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाग लेंगे। वार्ता में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के भाग लेने की भी संभावना है।


अफगानिस्तान से पाकिस्तान को जाने वाले अहम राज मार्ग और उसकी सीमा से लगे व्यापारिक शहर स्पिन बोल्डक पर तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद झंडा फहराते समर्थक। एएफपी

हिंसा बढ़ी तो 35 लाख से ज्यादा लोगों का हो सकता है पलायन

प्रेट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था (यूएनएचआरसी) ने कहा है कि जनवरी से लेकर अब तक पौने तीन लाख से ज्यादा अफगानी नागरिक पलायन कर गए हैं। हिंसा की यही स्थिति रही तो शरणार्थियों की संख्या 35 लाख से ज्यादा हो जाएगी।

अलकायदा के संपर्क में है तालिबान

एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के सलाहकार वाहिद उमर ने कहा है कि तालिबान के अलकायदा से मजबूत संबंध हैं। दोनों मिलकर सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। यह अमेरिका-तालिबान के बीच हुए समझौते का खुला उल्लंघन है।

जार्ज बुश ने की सेना वापसी की आलोचना

एपी के अनुसार, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने सेना वापसी की आलोचना की है। उन्होंने जर्मन मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा, इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं।

अलकायदा व अन्य आतंकी संगठनों से दूर रहे तालिबान

प्रेट्र के अनुसार चीन ने कहा है कि तालिबान को अलकायदा व अन्य आतंकी संगठनों से दूर रहना चाहिए। चीन की चिंता अलकायदा से संपर्क रखने वाले शिनजियांग प्रांत में सक्रिय उइगर मुस्लिम उग्रवादी संगठन को लेकर है। दुशांबे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध से बचा जाना चाहिए। इस स्थिति को टालने के लिए सभी पक्षों के बीच वार्ता होना बेहद जरूरी है।

गूगल मीट पर फ्री यूजर्स को एक घंटे से ज्यादा की वीडियो कॉल पर देनी होगी फीस

वाशिंगटन, एएनआइ : तकनीक में बादशाहत रखने वाले गूगल ने फ्री जीमेल एकाउंट्स पर गूगल मीट की अनलिमिटेड ग्रुप वीडियो कॉलों के युग को खत्म कर दिया है। अब वह मुफ्त खाते वाले यूजर्स को केवल एक घंटे के लिए ही मुफ्त ग्रुप वीडियो कॉल करने की सुविधा देगा। इससे पहले यह सेवा सभी को 24 घंटे निशुल्क उपलब्ध थी। तीन या उससे अधिक यूजर्स वाली गूगल मीट की ग्रुप वीडियो कांफ्रेंस निजी जीमेल खातों के लिए सिर्फ एक घंटे मुफ्त रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गूगल ने यह कैप पिछले साल सितंबर में ही हटा दी थी। पिछले एक साल में फ्री गूगल मीट यूजर्स के निजी खाते भी इस मंच से ग्रुप कॉलों का लाभ ले रहे थे।

वैश्विक महामारी के चलते गूगल मीट ने इस कैप को सितंबर, 2020 में वापस ले लिया था। लेकिन अब वसूली के नियम को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। पिछले कुछ सालों से जीमेल के फ्री यूजर्स भी इस मंच का भरपूर उपयोग कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा और उन्हें एक घंटे से अधिक इसका इस्तेमाल करने पर इसका एक निश्चित शुल्क अदा करना होगा।

अमेरिकी संसद में पेश भारत समेत हिंद-प्रशांत देशों को सशक्त करने का बिल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के संबंधों को प्रशांत महासागरीय देशों खासकर भारत, आस्ट्रेलिया और जापान से संबंध मजबूत करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) में एक बिल पेश किया गया है। अमेरिका अपने राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों को साधने के लिए प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को मान्यता दे रहा है।

अमेरिकी सांसद जैक्वीन कास्ट्रो ने हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक समीक्षा अधिनियम को बुधवार को पेश किया है। अमेरिका-भारत संबंधों को समझौतों, संचार और नेविगेशन के जरिये नियमित सुरक्षा और सहयोग दिया जा रहा है। इस बिल के मुताबिक अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपना कार्य-व्यवहार बढ़ाने की नीति अपनानी होगी। इसके लिए हिंद महासागर क्षेत्र की सरकारों समेत सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्रों के साथ अमेरिका की राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा। इस विधेयक को टेक्सास से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने पेश किया। वह चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी साझेदार देश जैसे जापान व आस्ट्रेलिया के अलावा बड़े रक्षा सहयोगी भारत और नाटो देशों के साथ क्षेत्र में नियम आधारित कार्य-व्यवहार करना होगा।

गुलाम कश्मीर में इमरान सरकार का व्यवहार विदेशी आक्रांताओं जैसा

गिलगित, एएनआइ : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता सेना के अत्याचार के साथ ही अब सरकार की नीतियों का भी शिकार हो रही है। इमरान सरकार ने 2021 के बजट में गुलाम कश्मीर को सबसे कम धन आवंटित किया है। इससे सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों और जनता दोनों के ही तेवर तीखे हो गए हैं। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्षियों के साथ अत्याचार से पीड़ित जनता भी उठ खड़ी हुई हुई है।

डान अखबार के अनुसार 2021 के बजट में गिलगित-बाल्टिस्तान को सबसे कम धन आवंटित होने के कारण पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जनता के सहयोग से यहां बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। विपक्षी दल के साथ हजारों लोगों ने गिलगित, स्कार्दू और गांचे जिलों समेत कई स्थानों पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया। टायरों में आग लगाकर जनता ने काराकोरम राजमार्ग सहित कई स्थानों पर रास्ता जाम कर दिया। यहां के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान के खिलाफ नारेबाजी की। गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) विधानसभा में विपक्ष के नेता अमजद हुसैन ने कहा कि जीबी में अगर विकास के लिए उचित धन आवंटन नहीं किया गया तो विरोध और तेज किया जाएगा।

पाक पीएम के भतीजे ने किया पूर्व गवर्नर की विधवा पर हमला

इस्लामाबाद, एएनआइ : बलूचिस्तान प्रांत के पूर्व गवर्नर नवाब अकबर बुगती की विधवा शहजादी नरगिस ने पीएम इमरान खान के भतीजे और पेशे से वकील हसन खान नियाजी के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

नरगिस का आरोप है कि केंद्र सरकार की एजेंसी ने उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। इसी संबंध में वह अदालत को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए गई थीं। वहां इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी और कई अन्य लोग पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट परिसर में ही पहले गालियां दीं और बाद में गला दबाकर मारने की कोशिश की। इस संबंध में हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नरगिस ने पंजाब बार काउंसिल में भी शिकायत दर्ज की। इस पर सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ने नियाजी का वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं, नियाजी का कहना है कि यह मुकदमा उन पर ईश निंदा के मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बनाने को किया गया है।

यूएई ने इजरायल में पहला दूतावास खोला

तेलअवीव, रायटर : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। यूएई ने इजरायल के तेलअवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजरायल में कोई दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग भी मौजूद रहे।

ईरान के असहज होने के बाद भी अमेरिका के प्रयासों से पिछले साल यूएई और बहरीन ने अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों के सामान्य करने की शुरुआत की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के सूडान और मोरक्को के साथ संबंध सामान्य करने में भी योगदान दिया।

इजरायल के यूएई में एक माह पहले दूतावास खोलने के बाद अब तेलअवीव के स्टाक एक्सचेंज में यूएई का दूतावास खोला गया है। यूएई के राजदूत मोहम्मद अल खाजा ने अपने देश का झंडा इमारत पर फहराकर इसकी शुरूआत की। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक ने इस अवसर पर कहा कि यह दिन इजरायल और यूएई के संबंधों के लिए मील का पत्थर है। एक साल पहले तक यूएई का इजरायल में झंडा फहरना एक सपना था, जो आज पूरा हो रहा है।

पाकिस्तान में बस में धमाका, नौ चीनी नागरिकों समेत 13 की मौत

▸ 28 चीनी नागरिक भी घायल, चीनी सरकार ने घटना को लेकर जताई चिंता

▸ ज्यादातर मरने वाले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू बांध पर काम करते थे

पेशावर, रायटर : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को एक बस में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें नौ चीनी नागरिक थे। अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोट इतना तेज था कि बस खाई में जाकर गिरी। बस में चीनी इंजीनियर, सर्वेयर और मैकेनिकल स्टॉफ भी था, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू बांध पर कार्य कर रहा था। इस बांध का निर्माण कार्य चल रहा है।

एक स्थानीय अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ब्लास्ट के बाद बस के इंजन में आग लग गई और वह खाई में जा गिरा। इस घटना में 28 चीनी नागरिक घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में दो पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह बेहद तीव्रता वाला धमाका था, लेकिन विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं लगा है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब चीन लगातार पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर इमरान खान सरकार को आगाह करता रहा है। चीन पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड के अलावा बिजली और बांध निर्माण की कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें हजारों की संख्या में चीनी इंजीनियर और अन्य स्टाफ कार्य करते हैं। पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफी बंदोबस्त किए हैं, फिर भी यह घटना सामने आई है।

पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने भी घटना की पुष्टि की है। उसने कहा कि पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं में नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई चीनी नागरिकों की मौत हुई है। उसने चीनी कंपनियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। चीन ने पाकिस्तान की कई परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा समेत कई सीमावर्ती इलाकों में आतंकी संगठनों की मौजूदगी उसके लिए खतरा बनती रही हैं। इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चीन सरकार ने विस्फोट के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पाकिस्तान सरकार से की है।


पाकिस्तान के पूर्वोत्तर कोहिस्तान जिले में बुधवार को बस में हुए बम विस्फोट के बाद घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़। यह बस दसू बांध का निर्माण कर रहे कर्मचारियों को लेकर जा रही थी। इसमें चीन के नागरिक भी सवार थे। एपी

विश्व में एक हफ्ते में कोरोना के 30 लाख नए मरीज

▸ सात दिनों में 10 फीसद नए मामले बढ़े

▸ डेल्टा वैरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता

जेनेवा, एपी : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह में दुनिया में तीस लाख कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले हैं। संगठन की ओर से कहा गया है कि मरीजों की संख्या में करीब दस फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौत के आंकड़े भी तीन फीसद बढ़े हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संक्रमण के नए मामले ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया व ब्रिटेन में बढ़े हैं। मरीजों के बढ़ने का कारण डेल्टा वैरिएंट है। यह वैरिएंट अब तक 111 देशों में फैल चुका है। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने आशंका जताई है कि डेल्टा वैरिएंट के पूरी दुनिया में प्रभावी होने की आशंका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का प्रभाव उन लोगों पर सबसे ज्यादा होगा, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ज्ञात हो सभी देश टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं।

ब्रिटेन : आइएएनएस के अनुसार यहां पिछले 24 घंटे में 36 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक 90 वर्षीय महिला अल्फा और बीटा दोनों ही वैरिएंट से संक्रमित हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई।

आस्ट्रेलिया : रायटर के अनुसार सिडनी में मरीज बढ़ने के बाद 14 दिनों का लाकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब यह 30 जुलाई तक प्रभावित रहेगा।

इंडोनेशिया : एपी के अनुसार यह देश एशिया में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पाट बन रहा है। यहां एक दिन में 54 हजार से ज्यादा नए मामले आए। यह देश वर्तमान में रोजाना आने वाले मामलों में भारत से भी आगे निकल गया है।

रूस : रायटर के मुताबिक कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक यहां एक दिन में पहली बार सबसे ज्यादा 786 लोगों की मौत हुई है।

सिंगापुर : रायटर के अनुसार तीन हजार यात्रियों को ले जाने वाले क्रूज पर एक यात्री संक्रमित मिला है। इसके बाद सभी यात्रियों को केबिन में ही क्वारंटाइन कर दिया। क्रूज सिंगापुर वापस लौट आया।

अमेरिका वैक्सीन देने को तैयार, भारत की कानूनी समीक्षा से देरी

वाशिंगटन, प्रेट्र: भारत को कोविड वैक्सीन देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है लेकिन इसमें देर भारत सरकार की ओर से ही हो रही है। वाशिंगटन की ओर से कहा गया कि कोरोना वैक्सीन के निर्यात की पूरी तैयारी कर ली गई है लेकिन वैक्सीन डोनेशन के लिए कानूनी प्रविधानों की समीक्षा को लेकर भारत को समय चाहिए।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया, 'हमें भारत सरकार से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है क्योंकि हम वैक्सीन निर्यात के लिए तैयार हैं।' बाइडन प्रशासन ने एलान किया है कि भारत समेत दुनिया भर के देशों को वैक्सीन की आठ करोड़ खुराक दी जाएंगी। हाल में ही अमेरिका से वैक्सीन की खेप पाकिस्तन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश समेत दुनिया भर के कई देशों में भेजी गई। भारत में आपातकालीन आयात से जुड़े कुछ कानूनी प्रविधान हैं जिसके पूरा होते ही वैक्सीन की खेप अमेरिका से पहुंच जाएगी।

अमेरिका की ओर से भारत को 30-40 लाख मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन मिलने का इंतजार है। बता दें कि मॉडर्ना वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में आपात इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। वहीं फाइजर की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन नहीं किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि जिन देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी जा रही है। वहां कानून और वैक्सीन लेने के लिए जरूरी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इससे आसानी से उन्हें यह मदद की जा सकेगी। नेड प्राइस ने यह भी कहा कि भारत अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को देख रहा है ताकि अमेरिका से वैक्सीन को भेजना आसान हो। उन्होंने कहा, 'हमने दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को वैक्सीन की लाखों खुराकें भेजी हैं। दुनिया भर में अब तक लगभग चार करोड़ खुराक वितरित की जा चुकी हैं।'


अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइज। जागरण आर्काइव

पोप फ्रांसिस आपरेशन के 10 दिन बाद वेटिकन लौटे


इलाज के बाद स्वस्थ्य होने पर लोगों का अभिवादन करते पोप फ्रांसिस। एपी

वेटिकन सिटी, रायटर : पोप फ्रांसिस 10 दिन के बाद बुधवार को अपनी आंत का आपरेशन करवाकर लौट आए हैं। उनकी आंत का एक हिस्सा निकाले जाने के बाद उन्हें दो हफ्ते के लिए पूरी तरह से आराम करना है। पोप फ्रांसिस ने गत चार जुलाई को सर्जरी कराई थी। फ्रांसिस के 2013 में पोप बनने के बाद से यह उनकी पहली सर्जरी है। वेटिकन के प्रवक्ता मैटियो ब्राउनी ने कहा कि पोप फ्रांसिस प्रार्थना के लिए रोम बेसिल्का गए थे। वहां उन्होंने ईश्वर के समक्ष आभार व्यक्त किया। वह 12 से 15 सितंबर के बीच हंगरी और स्लोवास्किया जाएंगे।

बाइडन ने दो भारतीय अमेरिकी डाक्टरों को दी अहम भूमिका

▸ डा. राहुल गुप्ता 'नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' कार्यालय के निदेशक बने

▸ अतुल गवांडे इंटरनेशनल डेवलपमेंट हेल्थ ब्यूरो के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और एक सर्जन को अपने प्रशासन ने अहम भूमिकाओं के लिए नियुक्त किया है। वेस्ट वर्जीनिया के पूर्व स्वास्थ्य आयुक्त डा. राहुल गुप्ता को मंगलवार को 'नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' के कार्यालय के अगले निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वहीं सर्जन और प्रसिद्ध लेखक अतुल गवांडे को अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ब्यूरो आफ हेल्थ के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किया है।

गुप्ता पिछले 25 सालों से प्राथमिक इलाज कर रहे हैं। वह वेस्ट वर्जीनिया के दो गवर्नरों के अधीन काम कर चुके हैं और उन्हें स्वास्थ्य कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बतौर अमेरिका के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी उन्होंने 'ओपियाड' संकट का प्रभावशाली इलाज किया है। ओपियाड मारफीन जैसे तत्व का समूह है जो तंत्रिकातंत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काम आता है। गुप्ता ने जिका की कार्ययोजना को विकसित करने और इससे निपटने की तैयारियों में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने यह उल्लेखनीय कार्य ईबोला वायरस के बेतहाशा फैलने के दौरान किए थे। वह कई संगठनों के सलाहकार भी हैं और जनस्वास्थ्य नीति को लेकर उन्होंने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कार्ययोजनाएं बनाई हैं। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की है। वहीं, 55 वर्षीय गवांडे ने न्यूयार्क टाइम्स की बेस्ट सेलर घोषित चार किताबें लिखी हैं। इन किताबों के नाम :- कंप्लीकेशंस, बेटर, द चेकलिस्ट मेनिफेस्टो और बीइंग मार्टल हैं। गवांडे ने अपने ट्वीट में कहा कि वह यूएसएआइडी में नामित होने के लिए आभारी हैं।


डा. राहुल गुप्ता (फाइल)। एपी


डा. अतुल गवांडे (फाइल)। एपी

चीन में दो साल का अगवा बेटा पिता को मिला 24 सालों बाद

बीजिंग, प्रेट्र : एक चीनी पिता को अपना खोया हुआ बेटा 24 साल बाद मिला है। यहां गौर करने वाली बात ये है कि पिता ने बच्चे के खोने पर उसे ढूंढने के लिए सालों तक पूरे देश में पांच लाख किमी से अधिक का सफर तय किया। 26 साल का बेटा अब अध्यापक बन गया है।

चीन के शेनडोंग प्रांत में रहने वाले गुओ गैंगटन के बेटे को मानव तस्कर उनके घर से अगवा करके ले गए। इस दौरान उनके बेटे की उम्र महज दो साल थी। गुए गैंगटन के बेटे के गायब होने से मिली प्रेरणा पर 2015 में एक फिल्म भी बनाई गई। इसमें हांगकांग के सुपरस्टार एंडी लाउ ने अभिनय किया। चीन में बच्चों को अगवा किया जाना एक बड़ी समस्या है। हर साल हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डीएनए टेस्टिंग के जरिये गुओ गैंगटन के बेटे की पहचान हुई और इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। चाइना न्यूज के मुताबिक, दोनों संदिग्ध उस समय एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। उन्होंने ये सोचकर बच्चे को अगवा किया कि उसे बेचकर पैसा कमाया जाएगा। घर के बाहर अकेले खेलते हुए देख दोनों ने उसे अगवा किया और फिर उसे हैनान प्रांत लेकर चले गए। इसके बाद उन्होंने बच्चे को बेच दिया। गुओ गैंगटन का बेटा 1997 में अगवा किया गया था। इसके बाद गुओ ने अपने बेटे की तलाश में मोटरबाइक पर 20 प्रांतों की खाक छानी। इस दौरान कई दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें उनकी हड्डियां टूट गईं, जबकि उनके साथ लूटपाट भी हुई। 10 मोटरबाइक भी इस पूरे समय टूट गईं।

हर साल 20 हजार बच्चे होते हैं अगवा

इस तलाश के दौरान गुओ गैंगटन ने अपने बच्चे की तस्वीरों को बैनर की शक्ल दी। उन्होंने अपने बेटे को ढूंढ़ने में सारा जीवन लगा दिया। वह पुलों के नीचे सोते और पैसे खत्म होने पर लोगों से भीख तक मांगते। इस दौरान गुओ चीन में लापता होने वाले लोगों के संगठन में एक अहम सदस्य भी बने। इस दौरान उन्होंने कम से कम सात बच्चों को अपने माता-पिता से मिलवाया। चीन में बच्चों का अपहरण और उनकी तस्करी दशकों पुरानी समस्या है। 2015 में लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक, चीन में हर साल 20 हजार बच्चों को अगवा किया जाता है। इनमें से अधिकतर बच्चों को बेच दिया जाता है।

वाट्सएप और टेलीग्राम के जरिये बढ़े फिशिंग के मामले

नई दिल्ली, आइएएनएस : वाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप के जरिये फिशिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत इस मामले में दुनिया के टॉप तीन देशों में है। कैस्परस्की इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर एंड्रॉयड की ओर से जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

फिशिंग इंटरनेट पर धोखाधड़ी का वह तरीका है, जिसमें फर्जी ईमेल और मैसेज के जरिये यूजर से संवेदनशील जानकारियां पाने की कोशिश की जाती है। अक्सर लॉटरी या इनाम मिलने, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट के बदले कैश पाने जैसे संदेशों के जरिये यूजर को लुभाने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर, 2020 से मई, 2021 के बीच हैकर्स ने फिशिंग के 89.6 फीसद मामलों को वाट्सएप से, 5.6 फीसद को टेलीग्राम से और 4.7 फीसद को वाइबर से अंजाम दिया। देश के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 46 फीसद फिशिंग अटैक रूस में हुए। 15 फीसद के साथ ब्राजील दूसरे और सात फीसद के साथ भारत तीसरे स्थान पर है।

ट्रंप को सताने लगी अपनी कंपनियों की साख बचाने की चिंता

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▸ अभियोग दर्ज होने के बाद कई पदों से मुक्त किए कंपनी के सीएफओ, निवेशकों और पार्टनरों के बीच हो रही थी मुश्किल

न्यूयार्क : ट्रंप आर्गनाइजेशन और उसकी सहयोगी कंपनियों के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पर कर चोरी के मामले में आपराधिक अभियोग दर्ज होने के बाद इन कंपनियों की साख तेजी से गिर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इन कंपनियों को जांच के असर से बचाने के लिए सीएफओ को कंपनी के कई पदों से मुक्त कर दिया है।

ट्रंप ने 38 साल पुराने सहयोगी और सीएफओ एलन वीसेलबर्ग से किनारा करना शुरू कर दिया है। ट्रंप आर्गनाइजेशन और उनकी सहयोगी कंपनियों में वीसेलबर्ग आपराधिक अभियोग दर्ज होने से पहले प्रमुख पदों पर थे। अब स्काटिश गोल्फ कोर्स, पेरोल आपरेशन, ट्रंप आर्गनाइजेशन के व्यापार से संबंधित अन्य पदों से वीसेलबर्ग को मुक्त कर दिया गया है।

ज्ञात हो कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनियां कर संबंधी अपराधों में घिरी हुई हैं। इनकी मैनहट्टन के डिस्ट्रक्ट अटार्नी साइरस वेंस और न्यूयार्क की अटार्नी जनरल लेटिटिआ जेम्स के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों ट्रंप आर्गनाइजेशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पर आपराधिक अभियोग दर्ज किया था। इसके बाद सीएफओ वीसेलबर्ग ने डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के यहां समर्पण कर दिया था। अभियोग में ट्रंप को अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अभियोजकों ने कहा है कि जांच चल रही है। अब देखना ये है कि क्या ट्रंप वीसेलबर्ग को सीएफओ के पद से भी हटाएंगे या कंपनी से दूर करने के लिए कोई अन्य उपाय करेंगे।

नेपाल में देउबा को 30 दिनों में हासिल करना होगा विश्वास मत

काठमांडू, प्रेट्रः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 30 दिनों के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। वर्तमान में 75 वर्षीय देउबा की नेपाली कांग्रेस के पास केवल 61 सदस्य हैं। उन्हें अन्य दलों का सहयोग प्राप्त है। अगर देउबा विश्वास मत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें सरकार चलाने के लिए 18 महीने मिल जाएंगे। उसके बाद उन्हें चुनाव कराने होंगे। यदि वे विश्वास मत हासिल करने में असफल होंगे तो देश में अगले छह माह में चुनाव हो जाएंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार देउबा को अभी 149 संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसमें यूएमएल के माधव नेपाल गुट के 26 सदस्य भी शामिल हैं। मौजूदा समय में निचले सदन में 271 सदस्य ही हैं। ऐसी स्थिति में उनको बहुमत जुटाने के लिए 136 मतों की आवश्यकता होगी।



फिटनेस भारतीय हाकी टीम की सबसे बड़ी पूंजी है और इसका फायदा टीम को टोक्यो ओलिंपिक में मिलेगा।
– धनराज पिल्लै, पूर्व हाकी खिलाड़ी

बांग्लादेश के रहीम जिंबाब्वे के शेष दौरे से बाहर

हरारे, आइएएनएस : बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशिफकुर रहीम निजी कारणों के चलते जिंबाब्वे के शेष दौरे से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। मुशिफकुर के माता-पिता के कोरोना पाजिटिव पाए जाने के बाद घर वापस जाने का फैसला किया। बीसीबी ने कहा कि बल्लेबाज मुशिफकुर पारिवारिक कारणों की वजह से जिंबाब्वे के शेष दौरे से बाहर रहेंगे।



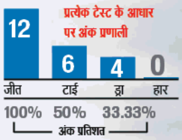
नए रूप में नजर आएगी डब्ल्यूटीसी–2

आइसीसी ने की पुष्टि, जीत पर मिलेंगे 12 अंक, भारत–इंग्लैंड सीरीज से शुरू होगा दूसरा चक्र

दुबई, प्रेट्र : भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के दूसरे चक्र में भी पाकिस्तान से नहीं खेलेगा और उसे अगले दो वर्षों में तीन दौरे करने हैं जिसकी शुरुआत अगले महीने इंग्लैंड सीरीज के साथ हो रही है। आइसीसी ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि डब्ल्यूटीसी-2 के दौरान जीत दर्ज करने पर 12 अंक, ड्रा पर चार अंक और मैच टाई होने पर छह अंक दिए जाएंगे।

डब्ल्यूटीसी कैलेंडर में नौ देशों को अपनी पसंद के छह देशों के खिलाफ खेलना है और 2021-2023 चक्र में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बजाय श्रीलंका से खेलेगी। भारतीय टीम चार अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से डब्ल्यूटीसी अभियान शुरू करेगी। टीम को दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी करना है, फिर उसे नवंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उसकी ही सरजमीं पर सीरीज खेलनी है। इनके अलावा भारत इस साल नवंबर में दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड और फरवरी से मार्च 2022 तक श्रीलंका की मेजबानी करेगा। आइसीसी ने आगे कहा कि जीते गए अंकों के प्रतिशत का उपयोग 2021-23 के चक्र में स्थानों का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा। इससे पहले प्रत्येक टेस्ट सीरीज के लिए 120 अंक तय किए गए थे जिससे असमानता पैदा होती थी।

जून 2023 में समाप्त होने वाले डब्ल्यूटीसी-2 में पांच टेस्ट की केवल दो सीरीज शामिल हैं। इनमें भारत-इंग्लैंड सीरीज के अलावा इस साल आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली एशेज सीरीज शामिल है। आस्ट्रेलिया के अगले साल के भारत दौरे में चार टेस्ट मैच खेले जाएंगे। यह नए चक्र में चार मैचों की एकमात्र सीरीज होगी।



डब्ल्यूटीसी–2 (2021–2023) के तहत होने वाली सीरीज

नोट : ब्रैकेट में मैच हैं।

टीमें (मैच)	घरेलू सीरीज	विदेश में खेली जाने वाली सीरीज
आस्ट्रेलिया (18)	इंग्लैंड (05)-वेस्टइंडीज (02)-दक्षिण अफ्रीका (03)	पाकिस्तान (02)- श्रीलंका (02)- भारत (04)
बांग्लादेश (12)	पाकिस्तान (02)-श्रीलंका (02)-भारत (02)	न्यूजीलैंड (02)- दक्षिण अफ्रीका (02)- वेस्टइंडीज (02)
इंग्लैंड (22)	भारत (05)-न्यूजीलैंड (03)- दक्षिण अफ्रीका (03)	आस्ट्रेलिया (05)-वेस्टइंडीज (03)- पाकिस्तान (03)
भारत (19)	न्यूजीलैंड (02)- श्रीलंका (03)- आस्ट्रेलिया (04)	इंग्लैंड (05)- दक्षिण अफ्रीका (03)- बांग्लादेश (02)
न्यूजीलैंड (13)	बांग्लादेश (02)- दक्षिण अफ्रीका (02)- श्रीलंका (02)	भारत (02)-इंग्लैंड (03)-पाकिस्तान (02)
पाकिस्तान (13)	आस्ट्रेलिया (02)- न्यूजीलैंड (02)- इंग्लैंड (03)	वेस्टइंडीज (02)-बांग्लादेश (02)- श्रीलंका (02)
दक्षिण अफ्रीका (15)	भारत (03)- बांग्लादेश (02)- वेस्टइंडीज (02)	न्यूजीलैंड (02)-इंग्लैंड (03)- आस्ट्रेलिया (03)
श्रीलंका (13)	आस्ट्रेलिया (02)- पाकिस्तान (02)- वेस्टइंडीज (02)	बांग्लादेश (02)-भारत (03)- न्यूजीलैंड (02
वेस्टइंडीज (13)	पाकिस्तान (02)- इंग्लैंड (03)- बांग्लादेश (02)	दक्षिण अफ्रीका (02)- श्रीलंका (02)- आस्ट्रेलिया (02)

प्रत्येक टेस्ट सीरीज में उपलब्ध अधिकतम अंक

सीरीज में टेस्ट	अंक
2	24
3	36
4	48
5	60

4 अगस्त 2021 से शुरू होगा डब्ल्यूटीसी–2 का आयोजन, जो भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज से शुरू होगा

9 टेस्ट खेलने वाली टीमें आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज डब्ल्यूटीसी–2 में भाग लेंगी

3 टेस्ट खेलने वाली टीमें अफगानिस्तान, आयरलैंड व जिंबाब्वे इस बार डब्ल्यूटीसी–2 का हिस्सा नहीं होंगी

6 सीरीज खेलेगी प्रत्येक टीम, जिसमें तीन घरेलू सीरीज होंगी और तीन उसे विदेशी धरती पर खेलनी होंगी। प्रत्येक सीरीज में न्यूनतम दो टेस्ट और अधिकतम पांच टेस्ट होंगे

3 टेस्ट मैचों की कुल सात सीरीज खेली जाएंगी

5 मैचों की भारत–इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के साथ डब्ल्यूटीसी–2 की होगी शुरुआत। इस बार पांच मैचों की सिर्फ दो सीरीज होंगी, जिसमें एशेज भी शामिल है

2 टेस्ट मैचों की 17 सीरीज खेली जाएंगी, जो कि सबसे ज्यादा हैं

4 टेस्ट मैचों की सिर्फ एक सीरीज खेली जाएगी इस बार, जिसमें भारत अगले साल आस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा



सभी को एकजुट और खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण : धवन

कहा, भारतीय टीम का कप्तान बनना बड़ी उपलब्धि, हमारे पास अच्छी टीम और शानदार सहयोगी स्टाफ

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम की कमान संभाल रहे शिखर धवन का मानना है कि नेतृत्वकर्ता का काम सभी को एकजुट और मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में रखना है। धवन की कप्तानी में भारत का श्रीलंका दौरा 18 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें टीम को तीन वनडे और इतने ही टी-20 मैच खेलने हैं। धवन ने कहा, 'यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैं भारतीय टीम का कप्तान बना हूं। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं चाहता हूं कि सभी एकजुट और खुश रहें। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारे पास अच्छी टीम, शानदार सहयोगी स्टाफ है और हमने पहले भी एक साथ काम किया है।'

धवन ने कहा कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, जिन्हें श्रीलंका दौरे के लिए टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। धवन ने कहा, 'जब मैंने रणजी ट्राफी खेलना शुरू किया तो मैं उनके खिलाफ खेला और तभी से उन्हें जानता हूं। जब मैं भारत-ए की ओर से खेला तो मैं कप्तान था और वह कोच थे, इसलिए बातचीत होती थी। जब वह एनसीए (राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी) के निदेशक बने तो हम लगभग 20 दिन के लिए वहां जाते थे, इसलिए काफी बात होती थी और अब हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं। अब हमें छह मैच एक साथ खेलने का मौका मिला है, इसलिए काफी मजा आएगा और मुझे लगता है कि हम सभी एक साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे।' चयनकर्ताओं ने रुतुराज गायकवाड़ और चेतन सकारिया जैसे कई उभरते हुए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है और धवन चाहते हैं कि ये युवा खिलाड़ी अपने सफर का लुत्फ उठाएं। उन्होंने कहा, 'टीम में युवाओं के होने और उनके सपने को साकार होते हुए देखकर खुश हूं। यह बड़ी चीज है कि ये युवा अपने शहरों से कुछ सपने लेकर निकले और उनके सपने पूरे हो रहे हैं।'

एक नजर में

800 मीटर रेस में उतरे बोल्ट

किंग्सटन : दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने संन्यास के बाद एक बार फिर मैदान पर वापसी की। मंगलवार को जमैका में एक प्रदर्शनी दौड़ के लिए वह एक दिन के लिए अपने संन्यास को तोड़कर बाहर आए व 800 मीटर रेस में भाग लिया। 100 मीटर व 200 मीटर में विश्व रिकार्ड बनाने वाले और आठ बार के ओलिंपिक स्वर्ण विजेता बोल्ट ने 2:40 मिनट के अनौपचारिक समय में 800 मीटर की रेस आरामदायक, मजेदार माहौल में पूरी की, लेकिन उन्होंने रेस को पूरी करने में काफी समय भी लिया। (एएनआइ)

ओलंपियाड 13 अगस्त से

चेन्नई : दूसरी आनलाइन शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 13 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने इसका एलान किया। 31 जुलाई से पहले प्रत्येक महासंघ इसके लिए अपना आवेदन कर सकता है। पिछले साल पहली फिडे आनलाइन शतरंज में भारत व रूस संयुक्त विजेता बने थे। प्रतियोगिता को लेकर पिछले साल जो नियम तय किए गए थे, वही इस बार भी होंगे। (आइएएनएस)

हाकी फाइव्स टूर्नामेंट स्थगित

लुसाने : अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआइएच) ने कोरोना के कारण इस साल होने वाले पहले एफआइएच विश्व हाकी फाइव्स टूर्नामेंट को बुधवार को 2022 तक स्थगित कर दिया। एफआइएच हाकी फाइव्स लुसाने 2021 प्रतियोगिता का आयोजन इस साल सितंबर में करने की योजना थी। अगले साल प्रतियोगिता प्लेस डि ला नेविगेशन में आयोजित होगी। प्रतियोगिता के लिए प्रवेश मुफ्त होगा और सीधा प्रसारण दुनिया भर में किया जाएगा। (प्रेट्र)

इंग्लैंड ने किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ

तीसरा वनडे तीन विकेट से जीत इंग्लैंड ने सीरीज 3–0 से कब्जाई, कार्स ने पांच विकेट झटके, विन्स की शतकीय पारी

बर्मिंघम, एपी : पाकिस्तान को बेन स्टोक्स की अगुआई वाली इंग्लैंड की दूसरे दर्जे की मानी जा रही इंग्लैंड की टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जेम्स विन्स के शतक की मदद से इंग्लैंड ने यहां तीसरे और अंतिम वनडे मैच में तीन विकेट से जीत दर्ज की और पाकिस्तान का सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया।

विन्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले शतक की मदद से इंग्लैंड ने 48 ओवर में सात विकेट पर 332 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। विन्स के 95 गेंदों पर 102 रन बनाए। उनके सामने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 158 रन की पारी फीकी पड़ गई। आजम के शतक की मदद से पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर नौ विकेट पर 331



सीरीज जीतने के बाद ट्राफी के साथ इंग्लिश टीम के खिलाड़ी • रायटर

रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने उसे बौना साबित कर दिया।

पाकिस्तानी पारी का आकर्षण बाबर का शतक व मुहम्मद रिजवान (74) के साथ उनकी 179 रन की साझेदारी रही। इंग्लैंड की तरफ से ब्रेडन कार्स ने 61 रन देकर पांच विकेट, जबकि सादिक महमूद ने 60 रन देकर तीन विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड का स्कोर 24 ओवर के बाद पांच विकेट पर 165 रन था। इसके बाद विन्स ने लुइस ग्रेगरी (77) के साथ महत्वपूर्ण 129 रन जोड़े। विन्स को हैरिस रऊफ (4/65) ने कैच कराया, जबकि ग्रेगरी भी गेंद हवा में लहरा गए। तब इंग्लैंड लक्ष्य से 29 रन पीछे था। इसके बाद क्रेग ओवरटन (नाबाद 18) और ब्रेडन कार्स (नाबाद 12) ने इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचाया। कुछ खिलाड़ियों के कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अपनी मूल टीम के क्वारंटाइन में चले जाने के बाद इंग्लैंड को इन तीन मैचों की इस सीरीज में पूरी तरह से नई टीम उतारनी पड़ी थी।



किम शर्मा संग लिएंडर पेस

महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और अभिनेत्री किम शर्मा गोवा में साथ वक्त गुजार रहे हैं। पेस और युवराज की पूर्व दोस्त की नजदीकियां बढ़ी हैं। दोनों की गोवा की फोटो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुई हैं • इंस्टाग्राम

अश्विन ने लिए छह विकेट

लंदन, प्रेट्र : भारतीय आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए खेलते हुए दूसरी पारी में 27 रन देकर छह विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया और पांच टेस्ट की सीरीज से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चेतावनी भी दे दी। अश्विन के इस मैच का रुख मोड़ने वाले स्पैल से सरे ने समरसेट को दूसरी पारी में 69 रन पर समेट दिया।

अश्विन गुरुवार को डरहम में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। उससे पहले उन्होंने कुछ अभ्यास हासिल करने के लिए सरे की ओर से मैच में 58 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 127 रन देकर सात विकेट झटके। अश्विन ने दूसरी पारी के दौरान पिच से मिले अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी कैरम बाल और आफ ब्रेक का सूझबूझ से इस्तेमाल किया। नई ड्यूक गेंद से उनके शानदार प्रदर्शन और बायें हाथ के स्पिनर डैन मोरियाटी के चार विकेट से समरसेट की टीम 29.1 ओवर में महज 69 रन पर सिमट गई, जबकि पहली पारी में टीम ने 429 रन बनाए थे। सरे की टीम पहली पारी में 240 रन ही बना सकी थी और अब उसे 258 रन के लक्ष्य का पीछा करना है।

मोर्गन ने विश्व कप फाइनल को बताया सबसे नाटकीय मैच

नाटिंघम, प्रेट्र : इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने 2019 विश्व कप फाइनल को क्रिकेट का सबसे नाटकीय मुकाबला करार दिया है जिसका वह हिस्सा रहे हैं। जीत की दूसरी वर्षगांठ पर मोर्गन ने कहा, 'फाइनल क्रिकेट का सबसे नाटकीय मुकाबला और सर्वश्रेष्ठ मुकाबला था जो अब तक खेला गया।'

खिलाड़ियों को खुद ही अपने गले में डालना होगा पदक

टोक्यो, एपी : टोक्यो ओलिंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाए रखने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे।

अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) के अध्यक्ष थामस बाक ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए बहुत अहम बदलाव की जानकारी बुधवार को दी। बाक ने कहा, 'पदकों को गले में डालकर नहीं दिया जाएगा। पदक खिलाड़ी को ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति ट्रे में पदक रखेगा, वह दस्ताने पहनकर ही इन्हें ट्रे में रखेगा ताकि सुनिश्चित हो कि किसी ने भी पदकों को छुआ नहीं हो।'



टोक्यो में एक नाव के ऊपर लगाए गए ओलिंपिक रिंग्स • रायटर

ओलिंपिक डायरी

ओलिंपिक में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए काफी सतर्कता बरती जा रही है जबकि यूरो कप फुटबाल में यूएफा के अध्यक्ष एलेक्सांद्र सेफेरिन ने हाल के हफ्तों में प्रतिस्पर्धा के फाइनल्स में खुद ही खिलाड़ियों के गले में पदक पहनाए थे। सेफेरिन ने तो इटली के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर जियालुइगी डोनारूम्मा से रविवार को लंदन में यूरो 2020 पदक और ट्राफी प्रदान करने के समारोह के दौरान हाथ भी मिलाए थे।

बाक ने बुधवार को भी पुष्टि की कि टोक्यो में समारोह के दौरान कोई भी एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा और न ही कोई किसी को गले लगाएगा।

खेल मंत्री ने ओलिंपिक दल का गाना लांच किया

नई दिल्ली, जेएनएन : केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के ओलिंपिक दल का चीयर4इंडिया गीत बुधवार को लांच किया और लोगों से टोक्यो ओलिंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों का समर्थन करने की अपील की। संगीतकार एआर रहमान और युवा गायिका अनन्या बिरला ने मिलकर टोक्यो ओलिंपिक के लिए भारतीय दल के आधिकारिक गीत तैयार किया जिसका शीर्षक 'चीयर4इंडिया : हिन्दुस्तानी वे' है। ठाकुर ने कहा, 'मैं सभी देशवासियों से इस गीत को सुनने और साथियों से इसे शेयर करने तथा टोक्यो ओलिंपिक के लिए पूरे भारतीय दल के लिए यह दिखाने के लिए चीयर करने का भी अनुरोध करता हूं कि हम आपके साथ हैं।'

बार्सिलोना संग फिर जुड़ सकते हैं मेसी

मैड्रिड, रायटर : सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी स्पेनिश फुटबाल क्लब बार्सिलोना के साथ ही जुड़े रह सकते हैं और पांच साल के लिए नया करार कर सकते हैं। इस नए करार में वह अपने वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती करने के लिए भी तैयार हैं। एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है।

बार्सिलोना के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले अर्जेंटीना के कप्तान मेसी का पिछले महीने ही क्लब के साथ करार खत्म हुआ था और अब वह किसी भी क्लब के साथ करार करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब से जोन लापोर्ता ने बार्सिलोना के अध्यक्ष का पद संभाला है तब से क्लब मेसी को बनाए रखने और उनके वेतन को कम करने की कोशिश में जुटा है।

हालांकि मेसी भी अपने वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती कराने के लिए



लियोन मेसी • फाइल फोटो, एएफपी

तैयार हैं और क्लब आगामी सप्ताह में मेसी के साथ करार की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। 2014 में क्लब के साथ करार करने वाले मेसी अभी तक अपने क्लब करियर में बार्सिलोना के साथ ही खेले हैं। पेरिस सेंट जर्मन, इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और इटली के इंटर मिलान ने भी मेसी के साथ कराने करने में अपनी रुचि दिखाई थी। यदि मेसी बार्सिलोना के साथ अगले पांच साल तक जुड़े रहते हैं तो वह 39 वर्ष के हो जाएंगे। हाल ही में मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय ट्राफी कोपा अमेरिका के रूप में जीती थी जब मेसी की टीम ने फाइनल में ब्राजील को हराकर खिताब जीता था।

2017 में मेसी ने करीब 49 अरब रुपये में बार्सिलोना के साथ पांच साल का करार किया था। अगर वह आधी कीमत पर नया करार करते हैं तो यह राशि 24.5 अरब रुपये होगी। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 778 मैच खेले व 672 गोल किए हैं

आजादी के बाद हमने जीता पहला स्वर्ण



दूसरे विश्व युद्ध के चलते अगले ओलिंपिक खेल 12 वर्ष बाद 1948 में आयोजित हो सके। लंदन में हुए खेलों के इस महाकुंभ ने आजाद भारत को हाकी में पहला स्वर्ण दिया। आजाद भारत के लिए यह बड़ी खुशखबरी थी।



लंदन ओलिंपिक (1948)

29 जुलाई से 14 अगस्त

4104 एथलीट | **59** देश | **17** खेल 136 मुकाबले

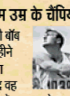


नीदरलैंड्स की 30 साल की धावक फैनी ब्लैंकर्स कोएन इस ओलिंपिक की सबसे चर्चित खिलाड़ी रहीं। उन्होंने चार स्वर्ण जीते। दो बच्चों की मां फैनी को द फ्लाइंग हाउसवाइफ कहा गया।

तालिका में शीर्ष पांच देश

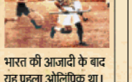
देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	38	84
स्वीडन	16	44
फ्रांस	10	29
हंगरी	10	27
इटली	08	27

बॉब सबसे कम उम्र के चैंपियन



17 वर्षीय अमेरिकी बॉब मथायस ने चार महीने ही डेकाथलन खेला था। इसके बावजूद वह पीला तमगा जीतने में सफल रहे। वह ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में सबसे कम आयु में पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बने।

भारतीय हॉकी का स्वर्णिम चौका



भारत की आजादी के बाद यह पहला ओलिंपिक था। हाकी टीम में कई बदलाव किए गए थे। पूरी टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था, जिसे ओलिंपिक का अनुभव हो। इसके बावजूद भारतीय टीम के प्रदर्शन में गिरावट नहीं हुई। भारत ने आस्ट्रेलिया को 8–0 से धोकर धमाकेदार आगाज किया। फाइनल में ब्रिटेन को 4–0 से हराकर भारतीय टीम ने ओलिंपिक में लगातार चौथा स्वर्ण जीता। यह स्वर्ण इसलिए भी खास था क्योंकि आजादी के बाद भारत ने अपने ऊपर राज करने वाले को हराकर इसे हासिल किया।



हेलसिंकी ओलिंपिक (1952)

19 जुलाई से 03 अगस्त

4955 एथलीट | **69** देश | **17** खेल 149 मुकाबले





विश्व में खराब राजनीति हालात और कोल्ड वार के बीच इजरायल, चीन और सोवियत संघ ने पहली बार ओलिंपिक खेलों में हिस्सा लिया।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	40	76
सोवियत संघ	22	71
हंगरी	16	42
स्वीडन	12	35
इटली	08	21

बेटे ने पूरी की बाप की हसरत

1924 में अमेरिकी खिलाड़ी बिल हेवंस ओलंपिक में भाग नहीं कर सके, क्योंकि उनकी पत्नी मां बनने वाली थी। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटा फ्रैंक जवान हुआ। जन्म के ठीक 28 वर्ष बाद हुए खेलों के इस महाकुंभ की कैनोइंग स्पर्धा में फ्रैंक ने स्वर्ण जीतकर पिता की कसक को दूर किया।

बलबीर के नौ गोल

आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स जैसी दिग्गज टीमों को रौंदते हुए भारतीय हाकी टीम ने लगातार पांचवीं बार ओलिंपिक का पीला तमगा जीतकर नया इतिहास रचा। फाइनल में नीदरलैंड्स को बुरी तरह धोते हुए टीम ने 13 गोल किए, जिसमें बलबीर सिंह सीनियर ने नौ गोल दागे।



भारतीय हॉकी टीम



मेलबर्न ओलिंपिक (1956)

22 नवंबर से 08 दिसंबर

3314 एथलीट | **72** देश | **17** खेल 151 मुकाबले



तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
सोवियत संघ	37	98
अमेरिका	32	74
ऑस्ट्रेलिया	13	35
हंगरी	09	26
इटली	05	20

हंगरी पर सोवियत संघ के हमले के विरोध में स्विट्जरलैंड, स्पेन व नीदरलैंड्स ने खेलों में भाग नहीं लिया।

सह आयोजक

ब्यूनस आयर्स के मुकाबले एक वोट से मेलबर्न को मेजबानी मिली लेकिन संक्रामक रोगों के खिलाफ आस्ट्रेलियाई कानून इतने सख्त थे कि विदेशी घोड़ों का प्रवेश मुश्किल हो गया। घुड़सवारी की सभी प्रतियोगिताएं जून में स्वीडन के स्टॉकहोम में खेली गईं।

हमारा प्रदर्शन

हाकी टीम ने अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाते हुए स्वर्णिम छक्का लगाया। फुटबॉल टीम आस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। कांस्य के लिए मैच में बुल्गारिया ने हमें हराया।



रोम ओलिंपिक (1960)

25 अगस्त से 11 सितंबर

5338 एथलीट | **83** देश | **17** खेल 150 मुकाबले



नंगे पैर फतह की मैराथन : इथियोपिया के एबेबे बिकिला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। उन्होंने नंगे पैर मैराथन फतह की थी।

तालिका में शीर्ष पांच देश

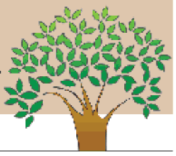
देश	स्वर्ण	कुल पदक
सोवियत संघ	43	103
अमेरिका	34	71
इटली	13	36
जर्मनी	12	42
ऑस्ट्रेलिया	08	22

पहली बार ओलिंपिक गान को स्वीकार किया गया। 18 यूरोपीय देशों में खेलों को लाइव दिखाया गया। कनाडा, अमेरिका, जापान में इसे थोड़े अंतराल पर दिखाया जा सका।

मिल्खा की वो दौड़ : उड़न सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलिंपिक कीर्तिमान तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन पदक से वंचित रह गए। इस दौड़ के दौरान उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया जो लगभग 40 साल बाद जाकर टूटा। हाकी टीम भी अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी नहीं रख सकी। लिहाजा उसे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा।



दैनिक जागरण
सप्तरंग
संयम और संकल्प का
गुरुवार, 15 जुलाई, 2021



जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको खुशियां ढूंढ़ने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। खुशी खुद आपके पास आएगी और आपमें समा जाएगी। महामारी ने हमें सिखा दिया कि हम सभी बराबर हैं। सकारात्मक सोच, संयम और दूसरों के लिए दिल में दया का भाव हमें खुशी के दरवाजे पर पहुंचा सकता है। ऐसे में हमें अपनी खुशियों के लिए अपने ही तरीके ढूंढ़ने हैं। छोटी-छोटी कोशिशें हमें दे सकती हैं बड़ी खुशी, बस जरूरत है शुरुआत करने की...

दयालुता से मिलेगी खुशी



उजाले की ओर



बिंदिया मुरगई
फाउंडर-हीलिंग हाइड अवे व मेंटल फिटनेस एंड माइंडफुलनेस कोच

अगर आपकी बिल्डिंग में कोई बुजुर्ग रहते हैं और कंप्यूटर व स्मार्ट फोन चलाना न जानने के कारण अपना सामान खुद नहीं मंगा सकते तो हम अपना सामान मंगवाते समय उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर पास में बीमार या दिव्यांग रहते हैं और उनके घर खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो हम कुछ बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हमारे पास रहने वालों के बच्चे छोटे हैं तो दिन में आधे घंटे हम उनके बच्चे की देखभाल करके उनकी मुश्किलें कम कर सकते हैं। हम किसी को कोरोना का टीका लगवाने के लिए उसका पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त अवसाद में है, अपना जीवन खत्म करने की सोच रहा है, ऐसे में यदि आपने फोन कर उसका हौसला बढ़ाया तो आप एक जीवन बचा सकते हैं। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। ये सब छोटी-छोटी पहल हैं, जिनसे हमें जो खुशी मिलेगी, वह स्थायी होगी।

दया का नहीं कोई मोल : अगर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरों की मदद कैसे करें, तो हम गलत हैं। किसी को पैसा नहीं, हमारा समय, हमारा सहारा चाहिए। अपने समय को लोगों के हित में लगाइए। जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो उसका फायदा हमें भी होता है। इस महामारी ने बता दिया कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, सफल हैं, असफल हैं, लेकिन महामारी के सामने सब बराबर हैं।

व्यवस्थित करें दिनचर्या: 'वर्क फ्राम होम' में समय की कोई सीमा ही नहीं रही है। इससे कामकाजी लोगों में निराशा बढ़ रही है। सामाजिक मेलजोल न हो पाने के कारण उनमें हाइपरटेंशन और डिप्रेशन बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे पहले अपनी सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। समय से काम खत्म करें और दफ्तर में भी अपनी समय सीमा की जानकारी दे दें। घर में दफ्तर का काम करने की जगह तय कीजिए। अगर आपके लिए अलग कमरा नहीं है तो बीच में पर्दा लगाकर ही कुर्सी पर बैठकर काम कीजिए। बिस्तर पर बैठकर काम मत कीजिए। आप सुबह उठकर बाकायदा तैयार होकर अपना काम कीजिए। काम के बीच ब्रेक लेकर आफलाइन एक्टिविटी करें।

खुद के लिए निकालें वक्त : घर संभालने वाली महिलाओं यानी होममेकर को भी अपने लिए समय नहीं मिल रहा। उनसे लगातार मांगें की जा रही हैं। बच्चे किसी से मिल नहीं पा रहे। सिर्फ आनलाइन पढ़ाई से उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा। इससे उनमें भी तनाव बढ़ रहा है। उनके सीखने की क्षमता घट रही है। ऐसे में होममेकर अपने लिए थोड़ा-सा समय अलग रखें। केवल 30 मिनट का 'मी टाइम' रखिए। उसमें संगीत सुनिए या किताब पढ़िए। इससे संबंध अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि चौबीस घंटे साथ रहने पर भी संबंधों में दरार पड़ रही है। उन दोस्तों से बात कीजिए, जिनसे बात करके हल्का महसूस करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो मैसेज के बजाय वीडियो या आडियो काल करें। बच्चों को भी रचनात्मक कार्यों में व्यस्त करें। खुशी पाने की युक्ति आप खुद निकाल सकते हैं।

व्यायाम है दवा : घर का हर सदस्य 30 मिनट शारीरिक व्यायाम जरूर करे। इससे शरीर तो ठीक रहेगा ही, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारी मानसिक सेहत को भी अच्छा करेंगे। इससे तनाव कम होगा और खुशी बढ़ेगी। व्यायाम से सेरोटेनिन नियंत्रित होता है। व्यायाम के साथ सिर्फ दस मिनट का ध्यान तनाव खत्म कर सकता है।

प्रकृति से निकटता: मैं और मेरे पति दिल्ली, मुंबई की व्यस्त जिंदगी छोड़ नीलगिरि के पहाड़ों के बीच रहने आ गए हैं। मेरा प्रोडक्शन हाउस 'ब्ल्यू मैंगो फिल्म्स' था। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर रहते समय मैंने बहुत लोगों से बात की। पिछले पंद्रह साल से मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श देती रही हूं। सुबह चार बजे से नौ बजे तक मैं प्रोडक्शन हाउस में होती थी और फिर मेंटल हेल्थ पर परामर्श देती थी। छोटी उम्र में मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गई थी। धर्मशाला जाती, तो दलाई लामा की प्रार्थना सभा में शामिल होती। 18 साल पहले मैं और पति हिमालय में स्पीति जाया करते थे। वहां हमने पुराने बौद्ध मठों का पुनर्निर्माण कराया। उनकी संस्कृति को फिल्मों में दिखाया। आज भी हम हर साल वहां एक-डेढ़ महीना बिताते हैं। मैं युवा बौद्ध अनुयायियों की कक्षाएं लेती हूं। उनसे संस्कृति और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करती हूं। मैं शुरू से ही प्रतिबद्ध थी कि हमें अपनी आंतरिक शांति के लिए काम करना है। प्रकृति के करीब रहना है। मानवता की सेवा करनी है।

पैसा नहीं, जिंदगी चुनी: हमने पहाड़ों में जाकर आराम करने की बात नहीं सोची। मुझे आर्गेनिक खेती का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब हम यहां आर्गेनिक सब्जियां आलू, ब्रोकली आदि उगाते हैं। मैंने इसे सीखा। हमने पक्षियों के लिए पानी के स्रोत बनाए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पक्षी आएं। हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। मधुमक्खियां पाली हैं। अगर हम दिल्ली में होते तो बहुत पैसा कमाते, लेकिन हमने जिंदगी और पैसे के बीच जिंदगी चुनी। जिंदगी बदलने के लिए पैसा नहीं, सोच चाहिए। महामारी ने हमें कहीं से भी काम करने का अवसर दिया है, हम इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं।

प्रस्तुति : यशा माथुर

मानसिक स्वास्थ्य है बहुत महत्वपूर्ण



लोग मानसिक स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है। मैं सभी से कहती हूं कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करें। मैं इसके लिए समाधान भी बताती हूं। मेरा फोकस डिजिटल एडिक्शन को लेकर भी है। लोग समझते नहीं या समझना नहीं चाहते हैं कि डिजिटल हेल्थ से उनकी मेंटल हेल्थ पर कितना फर्क पड़ रहा है। मैं स्कूलों के लिए वर्कशाप करती हूं। एक स्कूल के लिए काम करती हूं। इसके अलावा एक ऐसे संगठन के साथ काम करती हूं, जो कैदियों, विशेषकर महिला कैदियों को रिसाइकल प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम आजीवन कारावास के कैदियों के साथ काम करते हैं, ताकि वे थोड़े पैसे कमा सकें।

हर बदलाव घर से शुरू होता है। मैं अपनी निजी जिंदगी में माइक्रो लेवल पर भी पर्यावरण को बचाने के प्रयास करती हूं। हम भारतीय पौधे लगाते हैं। प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। मैं किसी एनजीओ के साथ नहीं जुड़ती हूं, स्वयं ही अपने स्तर पर कोशिशें करती हूं और आंतरिक खुशी प्राप्त करती हूं।



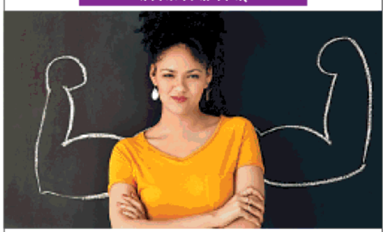
जिंदगी में दुख तो हैं, पर आप सिर्फ खुशियां चुनिए



दीपा मलिक
खेल रत्न विजेता पैरालंपियन

जिंदगी एक ऐसा त्योहार है, जिसे हम रोज मना सकते हैं। अपने दिन को उदासीनता के हवाले करें या खुशियों के, यह हमारे हाथ में है। मैं खुशियां चुनती हूं। कुछ बुरा होता है तो सोचती हूं कि यह अच्छे के लिए हो रहा है। खुश रहना और अच्छा सोचना तो अपने ही हाथ में है। मेरे माता-पिता ने मुझे सकारात्मक सोच रखने वाली लड़की बनाया। यही सोच मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी दी है। जब किसी स्कूल या कारपोरेट में जाकर मोटिवेशनल स्पीच देती हूं और अगर 400 लोग मुझे सुनते हैं तो मैं सोचती हूं कि इनमें 10 लोगों का माइंडसेट भी बदल जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। अब मैं अपने शरीर को दिव्यांगता या अपंगता या लकवा नहीं कहती, बल्कि समझती हूं कि ईश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि इस शरीर के जरिए लोगों की सोच बदलो। चुनौतियां हर एक के जीवन में हैं। कारण का निवारण ढूंढ़िए, उस पर रोइए मत। समाज सेवा के लिए मेरी बड़ी बेटी देविका ने मुझे प्रेरित किया है। हमने 'व्हीलिंग फाउंडेशन' संस्था बनाई, जिसके तहत हम दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद करते हैं। उन्हें परामर्श देते हैं। व्हील चेयर या स्पोर्ट्स डाइट देते हैं। दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करके हमें बहुत खुशी मिलती है।

सकारात्मकता की राह



आत्मनिश्चय के साथ बढ़ें आगे

टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले भारतीय तैराक साजन प्रकाश कहते हैं, 'मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे अपने प्रशिक्षण पर पूरा विश्वास था। उसी से सफलता मिली।' सच है कि जब हम अपनी क्षमता, मेहनत या परिस्थितियों पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। निश्चय, भरोसा अथवा आत्मविश्वास आपको स्वयं से, जीवन से और प्रकृति से जोड़ता है। मां के गर्भ में शिशु बिल्कुल अंधेरे में रहता है। वह रौशनी की चिंता नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे विश्वास होता है कि वह गर्भ में सुरक्षित है। जब उपयुक्त समय आता है, तो वह जीवन का आलिंगन करने के लिए तैयार रहता है। जैसे वारेन बफेट मानते हैं कि इंसान हों या पशु, वे वृक्ष की छांव में इसलिए आराम कर पाते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत पहले इस विश्वास के साथ पौधा लगाया होगा कि एक दिन वह विशाल वृक्ष बनकर दूसरों को छांव देगा।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक गगनदीप कौर कहती हैं, 'स्वयं में, अपने कर्म में, हुनर में, संबंधों में निश्चय रखने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। उनका आत्मविश्वास उनके चरित्र एवं चेहरे से दिखाई पड़ता है।' महान वैज्ञानिक थामस अल्वा एडिसन को हजारों बार विफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उनके निश्चय को डिगा नहीं सकी। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वह 10 हजार बार विफल हुए, तो उससे सबक लिया कि उन तरीकों व रास्तों से कैसे किनारा करना है। उद्यमी रंजीत पुंज की मानें, तो हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर चलना होता है। वह कहते हैं, 'मैं सभी परेशानियों को समेटने की कोशिश करता हूं। दौड़ने, मोटरसाइकिल चलाने या साइक्लिंग करने निकल पड़ता हूं। परिवार संग समय बिताता हूं। ध्यान-साधना करता हूं। इससे अधिक स्पष्टता से सोच पाता हूं।' अमेरिका के जैंडर फ्रायर एक बड़ी टेक्नोलाजी कंपनी के लिए काम करते थे। एक दिन उन्हें लगा कि यह काम उनके लिए नहीं है। उनके वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, 'आप क्या करेंगे, अगर आप कभी विफल ही न हों?' जैंडर ने तत्काल उत्तर दिया, 'मैं दूसरों को प्रशिक्षित करूंगा।' यह आत्मविश्वास की शक्ति थी। जैंडर आज आथर, सक्सेस कोच एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कारपोरेट स्पीकर भी हैं।

अंशु सिंह

विश्वास से चमत्कार

- तनाव एवं मुश्किल हालात में भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं।
- जीवन में संतुलन होता है।
- संबंधों में मधुरता आती है।
- दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

मनोदशा



डा. साक्षी गुप्ता
बाल मनोचिकित्सक

समझें व्यवहार में बदलाव



फोटो : इमेजेज बाजार

मेरे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। लड़ाई कर रहे थे। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं उन पर चिल्ला बैठी।' यह कहना है एक कामकाजी मां का, जो इन दिनों वर्क फ्राम होम कर रही हैं। दरअसल, कई बार अभिभावक यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनका बच्चा क्यों एक खास प्रकार से व्यवहार करने लगता है? क्यों वह क्रोध करता है या बड़ों की बातों को अनसुना करता है? अभिभावक बिना गहराई में गए बच्चों के ऐसे व्यवहार को दुर्व्यवहार की श्रेणी में डाल देते हैं। वे यह जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चा शायद कुछ कहना चाह रहा हो...। उसके व्यवहार में अनचाहा परिवर्तन कहीं न कहीं इस बात का सूचक है कि वह अपने पैरेंट्स से संतुष्ट नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे, माता-पिता का उन्हें पर्याप्त समय न दे पाना, उनकी बातें न सुनना, साथ न खेल पाना आदि।

वर्तमान समय किसी के लिए भी सहज नहीं है। परिवारों की दिनचर्या बदल गई है। जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ गया है। संतुलन न बना पाने के कारण पैरेंट्स का धीरज खत्म हो रहा है। खुद का तनाव बच्चों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा। वे बिना रोक-टोक के मोबाइल फोन या टीवी देखने में अपना अधिकतम समय व्यतीत कर रहे हैं। इसका उन पर एक अलग प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक असर हो रहा है, जिसे छोटे बच्चे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं आने या मनचाही चीज न होने से उनका क्रोध एवं चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। अभिभावकों को इस मनःस्थिति को समझना होगा। जब बच्चों का रूटीन निर्धारित होता है और उनसे अपेक्षाएं स्पष्ट होती हैं, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के व्यवहार पर पैनी नजर रखें। जब वे अपने बच्चों की बातों को सुनेंगे, तो उनकी भावनाओं को समझना आसान होगा यानी अभिभावक बच्चों पर ध्यान देकर उनके बदले व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हवाई उड़ान के समय कहा जाता है कि पहले अपना आक्सीजन मास्क पहन लें, वैसे ही सर्वप्रथम पैरेंट्स को भी अपना खयाल रखना होगा। इसके अलावा, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है...

- बच्चा अच्छी नींद, पौष्टिक आहार ले रहा है और रोजाना शारीरिक व्यायाम व योग कर रहा हो।
- बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना होगा। उनके साथ बातें करें, खेलें, साथ पढ़ें, टहलें।
- जब कभी बच्चा अच्छा व्यवहार या काम करे, तो उसकी प्रशंसा करें।
- बच्चों की एक दिनचर्या निर्धारित करें। स्क्रीन टाइम तय करें।

बचें चरम वृत्तियों से

जीने की राह



स्वामी विवेकानंद

एक बार जब मैं बोस्टन में था, तो एक नवयुवक मेरे पास आया। मेरे हाथ पर उसने एक कागज का टुकड़ा रख दिया। उस पर उसने किसी व्यक्ति का नाम-पता लिखा था और आगे यह वाक्य था - 'दुनिया की सारी दौलत और सारा सुख तुम्हें मिल सकता है, पर सिर्फ उसे पाने की तरकीब तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें वह तरकीब सिखा दूंगा। फीस सिर्फ पांच डालर।' चिट्ठी देकर उसने मुझसे पूछा- आपकी क्या राय है? मैंने उत्तर दिया- 'कम से कम इसे छपवाने के लिए कुछ पैसा तो कमा लो। तुमने तो यह हाथ से लिखा है।' मेरे कहने का आशय वह नहीं समझ सका। वह इसी विचार में मस्त था कि बिना कोई काम किए उसे तमाम सुख और पैसा मिल जाएगा। हम इस दुनिया में मनुष्यों में दो प्रकार की चरम वृत्तियां पाते हैं। पहली है चरम आशावादी वृत्ति, जिसमें हर एक वस्तु हमें सुंदर, हरी-भरी और अच्छी प्रतीत होती है। दूसरी है चरम निराशावादी वृत्ति, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी बातें हमारे मन के प्रतिकूल ही हैं। जब हम नौजवान और शक्तिवान होते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सारी भोग की चीजें हमारे लिए ही पैदा की गई हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम खांसते-खांसते एक कोने में जा बैठते हैं और फिर दूसरों के उत्साह पर भी ठंडा पानी फेरने लगते हैं। कम मनुष्यों को इसका ज्ञान है कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख लगा हुआ है। सुख और दुख जुड़वां भाई हैं। जिसकी बुद्धि संतुलित है, उसे दोनों का ही त्याग करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष जानता है कि विषय भोग निस्सार हैं और सुख-दुख का कोई अंत नहीं।

पुस्तक 'आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग' से साभार

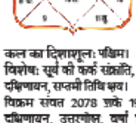
अपनी राय हमें जरूर बताएं :
feature@jagran.com

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 15 जुलाई, 2021 गुरुवार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पंचमी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक।
आज का दिशाशूल: दक्षिण।
आज का पर्व एवं त्योहार: कुमार षष्ठी।

कल 16 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
विशेष: सूर्य की कर्क संक्रांति, सूर्य दक्षिणायन, सप्तमी तिथि क्षय।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी 06 घंटे 07 मिनट तक, तत्पश्चात् सप्तमी हस्त नक्षत्र तत्पश्चात् चित्रा नक्षत्र परिघ योग 09 घंटे 42 मिनट तक, तत्पश्चात् शिव योग कन्या में चंद्रमा।

मेष: सूर्य का परिवर्तन व्यावसायिक मामलों में सुखद होगा। पारिवारिक समस्याओं में न्यूनता आएगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

वृष: रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद हो सकती है।

मिथुन: सूर्य का परिवर्तन आर्थिक मामलों में आशातीत सफलता देगा, लेकिन नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कर्क: सूर्य का परिवर्तन आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

सिंह: सूर्य का परिवर्तन नेत्र विकार दे सकता है। अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। व्यर्थ की उलझनें और भागदौड़ रहेगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

कन्या: शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सूर्य का परिवर्तन उत्तम होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक मामलों में आशातीत प्रगति होगी।

तुला: व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति कष्टकारी हो सकती है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य फलदायी होगा।

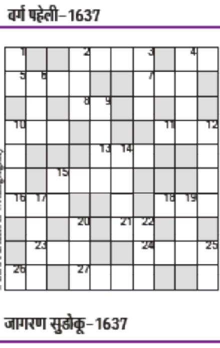
धनु: व्यावसायिक दृष्टि सूर्य का परिवर्तन सुखद होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा से बचें। जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा।

मकर: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।

कुंभ: विरोधी परास्त होंगे। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

मीन: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

वर्ग पहेली-1637



कल का हल



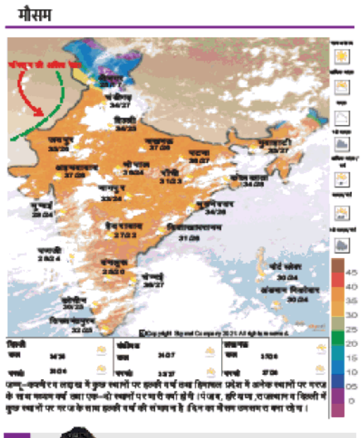
जागरण सुडोकू-1637

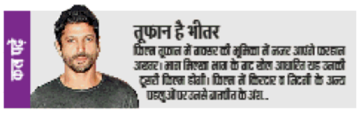
				9		8		3
9	4				6			
		1	8			9		
3				2		5		1
	8	6	9		7		2	
2	5			1				8
8		9		6		4	3	
		2		4		1		
4			1		9			6

कल का हल

3	1	4	9	7	8	5	6	2
2	9	8	6	4	5	3	7	1
7	6	5	3	1	2	8	9	4
4	5	6	1	2	3	7	8	9
9	8	7	4	5	6	1	2	3
1	2	3	7	8	9	4	5	6
5	7	9	2	3	1	6	4	8
8	3	2	5	6	4	9	1	7
6	4	1	8	9	7	2	3	5

मौसम





तूफान है भीतर

बांबे में पहली बार लोगों ने बस में किया सफर

1926 में आज ही के दिन अफगान चर्च से क्रॉफर्ड मार्केट के बीच बांबे (अब मुंबई) में पहली बस सेवा शुरू हुई थी। टैक्सी ड्राइवरों ने इसका भारी विरोध किया था। हालांकि, लोगों को यह पहल काफी पसंद आई और उस साल करीब छह लाख लोगों ने बस में यात्रा की थी।



विमान निर्माण की दुनिया को बोइंग ने दी नई ऊंचाई



1916 में आज ही के दिन अमेरिका के विलियम बोइंग ने वाशिंगटन में एयरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना की थी। यह मुख्य रूप से कॉमर्शियल प्लेन, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल और सेटेलाइट बनाती है। तकनीकी दक्षता के दम पर इसने विमान निर्माण को नई ऊंचाई दी है।

भारतीय राजनीति के पहले 'किंगमेकर' कहे जाते थे के कामराज

आजाद भारत के पहले 'किंगमेकर' कहे जाने वाले कुमारस्वामी कामराज का जन्म 1903 में आज ही के दिन तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था। 16 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल होने वाले के कामराज पिछली सदी के छठे दशक में कांग्रेस पार्टी में सुधार के लिए 'कामराज योजना' लाने के लिए जाने जाते हैं। इसके तहत उन्होंने खुद तमिलनाडु का सीएम पद छोड़ दिया था, साथ ही करीब आधे दर्जन केंद्रीय मंत्रियों और इतने ही मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा था। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में भी भूमिका निभाई थी।

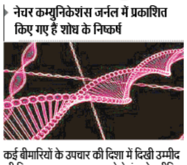


तंत्रिका संबंधी समस्याओं को दूर करेगी नवीन जीन थेरेपी

ओहियो, एएनआइ : दुनिया में कुछ दुर्लभ बीमारियां ऐसी हैं, जिनका इलाज या तो बहुत महंगा है या फिर अभी उनका इलाज तलाशा ही नहीं जा सका है। ऐसी ही एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है एरोमेटिक एल-एमिनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज (एएडीसी), जो बच्चों में होती है। इसके कारण बच्चों को कई गंभीर शारीरिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और उनके विकास में बाधा भी आती है। अब इसके उपचार की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने जीन थेरेपी की एक ऐसी नवीन विधि विकसित कर ली है, जिससे इस दुर्लभ आनुवंशिक विकार का उपचार किया जा सकता है। इस नई विधि से इस बीमारी से पीड़ित कुछ बच्चों का उपचार किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इस शोध के निष्कर्ष नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस नई विधि से केवल एएडीसी ही नहीं, ऐसी दूसरी बीमारियों का उपचार भी तलाशा जा सकता है।

ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी वेक्सनर मेडिकल सेंटर और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज आफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में की गई इस खोज ने ऐसी लाइलाज आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई है। इस शोध में बताया गया है कि इस नवीन जीन थेरेपी की यह विशेषता है कि एएडीसी से ग्रस्त न्यूरोजेनेटिक बीमारी वाले बच्चों के मस्तिष्क का उपचार किया

नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं शोध के निष्कर्ष



कई बीमारियों के उपचार की दिशा में दिखी उम्मीद की किरण। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

जा सकता है। इस बीमारी में डोपामाइन और सेरोटोनिन नहीं बनता है।

दुनिया भर में अब तक केवल 135 बच्चे ऐसे पाए गए हैं, जिनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में डोपामाइन पैदा करने वाला एंजाइम नहीं पाया गया है। दरअसल, यह ही मस्तिष्क में भावनाओं को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस एंजाइम की अनुपस्थिति से बच्चों का उनकी मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो जाता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। मसलन वे बोल नहीं पाते या खाना नहीं खा पाते। इसके अलावा उन्हें ऑक्यूलोजिरिक क्राइसिस नामक दौरे भी आते हैं, जो घंटों तक रह सकते हैं।

यह मिली सफलता : ओहियो स्टेट कॉलेज आफ मेडिसिन में न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के प्रोफेसर और इस अध्ययन के सह लेखक डा. क्रिस्टोफ बैंकिविज के मुताबिक, हमारी इस जीन थेरेपी की मदद से वे दौरे बंद हो गए और दोबारा नहीं आए। हमने जिन मरीजों को यह थेरेपी दी उनकी महीनों तक निगरानी की, जिनमें सुधार देखने को मिला। न केवल उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, बल्कि उनके मूड में भी सुधार हुआ। साथ ही उन्होंने बोलना यहां तक कि चलना भी शुरू कर दिया। शोधकर्ताओं ने यह जीन थेरेपी सात बच्चों को दी थी, जिनकी आयु चार से नौ वर्ष के बीच थी। छह बच्चों का उपचार सेन फ्रांसिस्को के यूसीएसएफ बेनिओफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया गया, जबकि एक का ओहियो स्टेट वेक्सनर मेडिकल सेंटर में।

जगी है उम्मीद : डा. क्रिस्टोफ बैंकिविज के मुताबिक, हमें जो परिणाम देखने को मिले हैं उससे ऐसी ही अन्य बीमारियों के उपचार तलाशने की राह भी खुली है। हमें उम्मीद है कि ये इस जीन थेरेपी की विधि पर और अध्ययन कर ऐसी ही अन्य बीमारियों का इलाज तलाशा जा सकेगा।



पुरातन कलाकृतियां...

यरुशलम स्थित सिटी आफ डेविड नेशनल पार्क में इजरायल के पुरातत्वविदों ने उत्खनन में मिली कई पुरातन कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। उन्होंने पुरातन यरुशलम शहर में की एक लापता दीवार की खोज की है, जिसे शहर की सुरक्षा के लिए लगभग 2700 साल पूर्व बनाया गया था। यहीं से ये पुरातात्विक कलाकृतियां मिली हैं। एएफपी

इधर-उधर की

सबसे महंगी फ्रेंच फ्राइज का गिनीज बुक में नाम दर्ज



करीब 15 हजार रुपये है एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज की कीमत। इंटरनेट मीडिया

न्यूयार्क, एजेंसी : किसी रेस्तरां में बैठकर कोल्ड ड्रिंक के साथ फ्रेंच फ्राइज खाने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी फ्रेंच फ्राइज कितने की है? मैनहट्टन स्थित 'सेरेंडिपिटी3' नाम के रेस्तरां ने अपनी सबसे महंगी फ्रेंच फ्राइज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इसकी एक प्लेट की कीमत करीब 15 हजार रुपये है। लाकडाउन के कारण बंद चल रहे रेस्तरां ने दोबारा खुलते ही इस रिकॉर्ड कीमत वाली डिश के साथ शुरुआत की है। दुनिया का सबसे बड़ा वेडिंग केक और सबसे महंगी आइसक्रीम बनाने समेत 10 और रिकॉर्ड भी इस रेस्तरां के नाम पर दर्ज हैं।

दुनिया में बढ़ रहा विषैले पारे का खतरा

चिंताजनक ▶ अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर लगाया पता

इंसानों, वन्य जीवों व जलीय जीवों के लिए खतरनाक है यह तत्व

वाशिंगटन, एएनआइ : हमारी धरती कई संकटों से एक साथ जूझ रही है। इसी कड़ी में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। एक नवीन अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में विषैले पारे का खतरा बढ़ रहा है, जो इंसानों के साथ-साथ वन्य जीवों व जलीय जीवों के लिए भी घातक है। दरअसल, यूनिवर्सिटी आफ मैसाच्युसेट्स लोवेल के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर ने मैसाच्युसेट्स जंगल में जमा हुए पारे की मात्रा का अध्ययन कर यह दावा किया है कि दुनिया भर के जंगलों में जमा इस विषैले तत्व की मात्रा पूर्व के अनुमान की तुलना से बहुत ज्यादा है। इस अध्ययन के निष्कर्ष प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं।

प्रो. डैनियल ओब्रिस्ट और उनकी टीम द्वारा किया गया यह अध्ययन इंसानों, वन्य जीवों और जलीय जीवों को लेकर



शोधकर्ताओं ने मैसाच्युसेट्स जंगल में जमा हुए पारे की मात्रा का अध्ययन किया। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

ध्यान देने की जरूरत

अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष इस ओर संकेत करते हैं कि दुनिया में विषैले पारे का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसके कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

चिंताजनक स्थिति प्रकट करता है, क्योंकि जंगलों में जमा पारा आखिरकार नदियों और झीलों से होता हुआ महासागरों में पहुंचता है।

अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक, पारा एक अत्यधिक जहरीला प्रदूषक है, जो मछली, पक्षियों, स्तनधारियों और मनुष्यों के लिए खतरा है। हर साल बिजली संयंत्रों में कोयला जलने, सोने के खनन व दूसरी औद्योगिक प्रक्रियाओं से सैकड़ों टन पारा वातावरण में छोड़ा जाता है और हवा के जरिये यह प्रदूषक दुनिया भर में फैलता है।

यह होती है समस्याएं : यूनिवर्सिटी आफ मैसाच्युसेट्स लोवेल के अध्यक्ष प्रो. ओब्रिस्ट के मुताबिक, लंबे समय तक पारे के संपर्क में रहने से या प्रदूषक के अधिक स्तर वाले भोजन का सेवन करने से प्रजनन क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और तंत्रिका व हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ओब्रिस्ट के अनुसार, जंगल दुनिया के सबसे प्रचुर, उत्पादक और व्यापक पारिस्थितिक तंत्र का गठन करते हैं। उन्होंने बताया कि यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जो इस बात की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है कि वातावरण में मौजूद पारा किस तरह से दुनिया के जंगलों में जमा होता है। साथ ही पारे के गैसीय रूप में मौजूदगी के बारे में भी अध्ययन से पता चलता है, जोकि पूर्व के अध्ययनों में सामने नहीं लाया गया है।

इस तरह से पहुंचता है नुकसान : बकौल प्रो. ओब्रिस्ट, पेड़ अपनी पत्तियों के माध्यम से वातावरण से गैसीय पारा लेते हैं और जैसे ही पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, वे मूल रूप से वायुमंडलीय पारे को पारिस्थितिक तंत्र में स्थानांतरित कर देते हैं। अध्ययनकर्ताओं के दल ने पिछले 16 महीनों में मापा कि कैसे वातावरण में मौजूद पारा हार्वर्ड जंगल में जमा होता है। अध्ययनकर्ताओं ने करीब चार हजार एकड़ के स्थान में अध्ययन किया, जिसमें रेड ओक (लाल शाहबलूत) और रेड मेपल जैसे पेड़ हर साल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जंगल के 100 फीट ऊंचे अनुसंधान टावर के जरिये विभिन्न ऊंचाइयों पर रखी गईं माप प्रणालियों के एक सेट ने गैसीय पारे के जमाव का आकलन किया।

अध्ययन में यह आया सामने : प्रो. ओब्रिस्ट के मुताबिक, इस जंगल में जमा पारे का 76 फीसद हिस्सा गैसीय वायुमंडल से आता है। यह बारिश और बर्फ में जमा पारे से पांच गुना और कचरे में जमा पारे से तीन गुना अधिक है।

बीपी और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में साबुत अनाज कारगर

अनुसंधान



जर्नल आफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुआ है अध्ययन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

यह पुरानी कहावत है कि मोटा खाना, मोटा पहनना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। अब विज्ञानी भी शोध कार्य के बाद इसी परिणाम पर पहुंचे हैं। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि दिन में तीन बार साबुत अनाज खाने वालों में उच्च रक्तचाप (हाई बीपी), मधुमेह (डायबिटीज) और कमर का आकार बढ़ने की संभावना कम रहती है। जो कम साबुत अनाज खाते हैं, उनमें अपेक्षाकृत इन रोगों का ज्यादा खतरा रहता है।

जर्नल आफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में इसका उल्लेख किया गया है। मैसाच्युसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर आन एजिंग में यह जांच की गई कि साबुत अनाज हृदय रोग के पांच खतरों को कैसे प्रभावित करता है। ये पांच खतरे हैं, कमर का आकार बढ़ना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्राल। अध्ययन 1970 में शुरू किया गया, जिसमें 3100 लोगों ने भाग लिया। इन सबकी आयु मध्यम और वृद्ध श्रेणी की थी। शोधकर्ताओं ने साबुत अनाज का प्रयोग करने वालों को चार श्रेणियों में बांटा। पांच प्रमुख खतरों के संबंध में उन सभी का अध्ययन किया। प्रत्येक चार साल के इस अध्ययन में पता चला कि जो लोग दिन में तीन बार साबुत अनाज का उपयोग कर रहे थे, उनके कमर के आकार में आधा इंच की वृद्धि हुई। दूसरी ओर साबुत अनाज न लेने या एक बार बहुत कम मात्रा लेने वालों में यह वृद्धि एक इंच हो गई। साबुत अनाज खाने वालों में बीपी-ब्लड शुगर भी अपेक्षाकृत कम देखा गया। कम साबुत अनाज लेने वालों में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ मिला। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के बाद पाया कि साबुत अनाज खाने वालों में हृदय रोग बढ़ाने वाले पांचों खतरे कम पाए गए। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

जाह्नवी कपूर की फिल्म का नाम होगा मिली!



जाह्नवी की दूसरी रीमेक फिल्म होगी मिली। इंस्टाग्राम

पिछले दिनों खबर आई थी कि जाह्नवी कपूर मलयालम फिल्म हेलेन की हिंदी रीमेक में काम करने वाली हैं। अब खबरें हैं कि जाह्नवी इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू करने वाली हैं। इस फिल्म की शूटिंग इनडोर के साथ कई आउटडोर लोकेशंस पर भी होगी। ऐसे में प्रोडक्शन टीम अच्छी लोकेशंस की तलाश में है। फिलहाल कोरोना काल में विदेश में शूटिंग करना आसान नहीं है। इसलिए फिल्म की टीम देश में ही अलग-अलग जगहों पर शूटिंग करने की तैयारी में है। जाह्नवी फिल्म की टीम से अगस्त से जुड़ेंगी। फिल्म का नाम बदलने की भी खबरें हैं। सूत्रों की मानें तो इस फिल्म की हिंदी रीमेक का नाम मिली होगा। जी स्टूडियो और जाह्नवी के पिता बोनी कपूर इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन मूल फिल्म के निर्देशक माथुकुट्टी जेवियर ही करेंगे। फिल्म हेलेन एक ऐसी लड़की के आसपास रची गई है, जो नर्स है। वह कनाडा जाने की तैयारी में है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब एक दिन वह घर नहीं पहुंचती है। फिल्म में मनोज पाहवा जाह्नवी के पिता के किरदार में होंगे। यह जाह्नवी के करियर की दूसरी रीमेक फिल्म होगी। इससे पहले जाह्नवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म धड़क से की थी, जो मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक थी।



पहली बार किसी शो की मेजबानी करती नजर आएंगी कंगना • इंस्टाग्राम

अमेरिकी रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड के भारतीय रूपांतरण में दिख सकती हैं बॉलीवुड क्वीन

डिजिटल प्लेटफार्म पर डेब्यू करेंगी कंगना

डिजिटल प्लेटफार्म की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सिनेमा के सुपरस्टार्स में भी इसके प्रति काफी आकर्षण नजर आ रहा है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर और सैफ अली खान जैसे अभिनेताओं के बाद अब अभिनेत्री कंगना रनोट भी डिजिटल प्लेटफार्म पर पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। वह डिजिटल प्लेटफार्म पर अपनी पारी की शुरुआत एक रियलिटी शो की मेजबानी से करेंगी। वह पहली बार किसी शो की मेजबानी करेंगी। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह अमेरिकी रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड का भारतीय रूपांतरण होगा। इसमें परिस्थितियां भारतीय संस्कृति और भावनाओं के अनुरूप बनाई जाएंगी। टेम्पटेशन आइलैंड का प्रसारण अमेरिका में 2001 में शुरू किया गया था। शो में शादीशुदा या डेट कर रहे कपल के रिश्तों की मजबूती और विश्वसनीयता को परखा जाता है। फिलहाल इस शो के प्लेटफार्म के नाम पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं कंगना ने मंगलवार को अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफार्म के लिए ही बन रही फिल्म टिकू वेड्स शेरू के अभिनेता का एलान किया है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में होंगे। नवाजुद्दीन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कंगना ने अपनी टीम में उनका स्वागत किया। वहीं मणिकर्णिका फिल्म्स की तरफ से इंस्टाग्राम पर लिखा गया, हमारी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेता (नवाजुद्दीन) टिकू वेड्स शेरू की टीम से जुड़ गए हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अपना शेर मिल गया। शूटिंग जल्द ही शुरू होगी।

'अपने फार्महाउस पर महज कुछ घंटों में ही शूट किया मजबूर हो गए...'

कोरोना काल ने कलाकारों को अपने घर और आसपास ही सीमित सुविधाओं के साथ काम करना सीखा दिया है। इसका बखूबी फायदा उठाया बहुत हवा सा... और चांद सिफारिश... जैसे गानों के गायक शान ने। शान का नया म्यूजिक वीडियो मजबूर हो गए... गुरुवार को रिलीज होगा। इस गाने के बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने बताया, 'गीतकार राजेश मंथन के साथ मैंने कई गाने बनाए हैं। मेरे पास उनकी कई गजलें और कविताएं हैं। यह गाना मैंने उनकी ही एक कविता से प्रेरित होकर तैयार किया है। मुंबई से कुछ दूरी पर मेरा एक फार्महाउस है। आजकल मैंने उसी को अपना शूटिंग स्टूडियो बना लिया है। इस वीडियो की अभिनेत्री ज्योति कपूर मेरी पत्नी राधिका की बचपन की बेस्ट फ्रेंड हैं। गाने में एक छोटी बच्ची की भी जरूरत थी और किस्मत से ज्योति की भी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। फिर मैंने ज्योति को उनके पति और बच्ची के साथ अपने फार्महाउस पर बुलाया और कहा कि वहीं हम सब मिलकर शूटिंग-शूटिंग खेलेंगे। ज्योति के पति और उनकी बेटी से ही मेरी कास्टिंग पूरी हो गई। एक ही परिवार से होने के कारण कोरोना का खतरा भी कम था। फिर मैंने अपने निर्देशक मेहुल गडानी से बात करके एक दिन का शेड्यूल बनाया। खास बात यह है कि शूटिंग के दिन बीच-बीच में बारिश भी हो रही थी। फिर भी हमने इस पूरे गाने की शूटिंग अपने फार्महाउस पर सिर्फ कुछ घंटों में ही पूरी की।' शान जल्द ही अपना दूसरा म्यूजिक वीडियो भी रिलीज करेंगे।



आज रिलीज होगा शान का नया गाना मजबूर हो गए। टीम शान

नेपो डैड कहने पर करण जौहर का करारा जवाब

दो बच्चों की जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं है। खासकर तब जब यह जिम्मेदारी सिंगल पैरेंट के कंधों पर हो। फिल्ममेकर करण जौहर दो जुड़वा बच्चों के पिता हैं। अपने दोनों बच्चों यश और रूही के लिए वह वक्त निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अक्सर वह इंटरनेट मीडिया पर अपने बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा करते रहते हैं। बुधवार को करण अपने दोनों बच्चों के कमरे से इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़े। दरअसल, करण लाइव आने के मूड में नहीं थे, वह मीटिंग के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उनकी बेटी रूही ने करण के फोन से इंस्टाग्राम लाइव का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इस वजह करण लाइव आ गए। करण ने बहुत कोशिश की कि उनके बच्चे इस लाइव पर उनके साथ आएं, लेकिन दोनों मस्ती के मूड में थे। करण के कई बार कहने पर ही दोनों सिर्फ हैलो बोलने के लिए लाइव पर आए। इस दौरान करण ने एक यूजर को भी लताड़ दिया। दरअसल, उस यूजर ने लाइव के दौरान करण को नेपो (नेपोटिज्म) डैड कह दिया, जिससे करण गुस्सा तो नहीं हुए, लेकिन हंसते-हंसते उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नेपो डैड कहने वाले तुम्हें अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है।



बेटी रूही के कारण लाइव आए करण जौहर। इंस्टाग्राम

सारांश की रीमेक बनाना चाहते हैं अनुपम खेर



करियर की शुरुआत में सारांश से अनुपम को मिली थी पहचान • इंस्टाग्राम

कुछ फिल्में कलाकारों के दिल के काफी करीब होती हैं। अनुपम खेर के शानदार फिल्मी करियर की ऐसी ही फिल्म है सारांश। साल 1984 में अपने करियर की शुरुआत में ही सारांश में एक बुजुर्ग का किरदार निभाकर अनुपम खेर ने खूब तारीफें बटोरी थीं। यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। अब अनुपम अपनी इस फिल्म की रीमेक बनाने की इच्छा रखते हैं। उनका मानना है कि इस फिल्म को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन एक नए सेटअप के साथ। एक लाइव चैट के दौरान अनुपम ने कहा कि मैं सारांश को एक एक्शन फिल्म की तरह दोबारा बनाना चाहता हूं। मैं इस दिशा में विचार भी कर रहा हूं। मैंने फिल्म में जिस बुजुर्ग इंसान का किरदार निभाया था, मैं चाहता हूं कि रीमेक में उस बुजुर्ग की भूमिका में कोई पूर्व रॉ या आर्मी से जुड़ा व्यक्तित्व हो, जो उसी तरह की परिस्थिति में हो, जैसा सारांश में था। अगर इस फिल्म को दोबारा बनाया गया, तो निश्चित तौर पर मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगा। अनुपम खेर की आगामी फिल्म नोटंकी है। इसमें उनके साथ वर्धन पुरी और सतीश कौशिक अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

सिनेमाघर में फिल्में देखना मिस करती हूं : तापसी

सिनेमाघर में सुकून से बैठकर फिल्में देखे हुए दर्शकों को काफी वक्त हो गया है। कोरोना काल में सिनेमाघर बहुत कम वक्त के लिए ही खुले हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद तो सिनेमाघर में जाकर फिल्में देखना और भी मुश्किल हो गया। हालत यह है कि अब भी कुछ जगहों पर सिनेमाघर 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे हैं, तो कहीं अब भी पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में दर्शकों के साथ-साथ फिल्मों के सितारे भी थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्में देखना मिस कर रहे हैं। अभिनेत्री तापसी पन्नू भी इनमें से एक हैं।



रश्मि रॉकेट फिल्म में नजर आएंगी तापसी पन्नू • जागरण आर्काइव

दैनिक जागरण से हुई बातचीत में तापसी ने बताया कि मैं तो थिएटर को बहुत मिस करती हूं। कई बार लगता है कि कब सब सामान्य होगा और मैं थिएटर में बैठकर फिल्म देखूंगी। कोरोना की दूसरी लहर से पहले जब सिनेमाघर खुले थे, तब मैंने फिल्म देखी थी। मुझे फिल्म देखने की तारीख भी याद है। इस साल पहली जनवरी को मैंने वंडर वूमन 1984 फिल्म थिएटर में देखने गई थी। पहली तारीख को फिल्म देखने का कारण यही था कि ऐसा कहा जाता है कि साल के पहले दिन आप जो काम करते हैं, वह पूरे साल करने को मिलता है। यही सोचकर मैं भी गई थी कि इस साल थिएटर में सुकून से फिल्में देखने को मिलेंगी, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया। बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का जो मजा होता है, वह भी मिस कर रही हूं। तापसी की आगामी फिल्मों में शाबाश मिट्ठू, रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा और दो बारह शामिल हैं।

मां के समझाने पर करिश्मा ने स्वीकार की थी दिल तो पागल है फिल्म



डिडयन आइडल के मंच पर बतौर अतिथि पहुंचीं करिश्मा। टीम सोनी

कई फिल्मों में देखा गया कि शुरुआती चरणों में कई कलाकार किरदार निभाने से इन्कार कर देते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा कलाकार उसी फिल्म को करता है तो वह फिल्म मील का पत्थर साबित होती है। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म दिल तो पागल है अभिनेत्री करिश्मा कपूर के लिए कुछ ऐसी ही फिल्म रही। करिश्मा ने इस फिल्म से जुड़ी यादें साझा कीं सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर, जहां वह आगामी एपिसोड की शूटिंग के लिए बतौर अतिथि पहुंचीं। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान प्रतिभागियों ने करिश्मा से जुड़े गानों पर परफॉर्म किया। करिश्मा ने उन गानों से जुड़े किस्से लोगों के बीच साझा किए। फिल्म दिल तो पागल है के बारे में उन्होंने बताया, 'इस फिल्म को कई अभिनेत्रियों ने करने से इन्कार कर दिया था। जब मुझे ऑफर मिला, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यह आई कि यह एक डांस फिल्म है, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना है। सभी इस फिल्म को यह कहकर इन्कार कर रहे थे कि फिल्म में माधुरी जी साथ डांस कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। मैंने भी मन बना लिया था कि यह मुझसे नहीं होगा। फिर यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा मुझे फिल्म की कहानी सुनाने आए। तब मेरी मां ने मुझे समझाया कि तुम्हें यह चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। तुम माधुरी दीक्षित की बड़ी प्रशंसक हो, तुम्हें यह फिल्म जरूर करनी चाहिए। बस बहुत मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। यह फिल्म मेरे लिए बहुत विशेष है, जिसमें मुझे शाह रुख खान और माधुरी दीक्षित से बहुत मदद मिली।' इस एपिसोड का प्रसारण इस सप्ताहांत में सोनी चैनल पर किया जाएगा।

राखी में दिख सकती है शाह रुख-संजय की जोड़ी



अभिनेता के तौर पर पहली बार संजय संग आएंगे शाह रुख • इंटरनेट मीडिया

हिंदी सिनेमा के बादशाह शाह रुख खान और खलनायक संजय दत्त भले ही पिछले कई वर्षों से सिनेमा में सक्रिय हैं, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने अभी तक किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है। अब दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखने की सिनेप्रेमियों की इच्छा जल्द ही पूरी होने जा रही है। खबर है कि दोनों अभिनेता वायकॉम 18 के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म राखी में एक साथ काम कर सकते हैं। सूत्रों की मानें तो दोनों ने न सिर्फ इस फिल्म को अपनी स्वीकृति दे दी है, बल्कि मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस फिल्म को हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि फिल्म राखी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि शाह रुख अभिनीत फिल्म रा.वन और ओम शांति ओम में संजय मेहमान भूमिका में थे। दोनों कलाकारों की आगामी फिल्मों की बात करें तो शाह रुख फिलहाल अपनी फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त हैं, वहीं संजय 13 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगे।